हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

29/03/2017/1100/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3975

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो बार-बार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि केन्द्र सरकार की ओर से हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी के छोटे-से-छोटे कार्यकर्त्ता से लेकर पूरी सरकार यही एक बात कहती है, तो जो यहां सूचना रखी है इसकी हम तुलना करेंगे। जब केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी तो उस समय वर्ष 2013-14 में दिनांक 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 तक प्रदेश को वित्तायोग की सिफारिशों से प्राप्त सहायता 541.05 करोड़ रुपये मिली। वर्ष 2013-14 में 1883.47 करोड़ रुपये और जब एन0डी0ए0 की सरकार आई तो वर्ष 2014-15 में 1108.87 करोड़ रुपये मिले। इसी तरह से वर्ष 2015-16 में 8436.15 करोड़ रुपये मिले और वर्ष 2016-17 में 8109.97 करोड़ रुपये मिले। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है यदि इसकी तुलना करेंगे तो 1 जनवरी, 2013 से लेकर 31 मार्च, 2013 तक यानी जो वर्ष 2012-13 था, उसमें 371.35 करोड़ रुपये मिले। यह यू0पी0ए0 की सरकार के समय का है। वर्ष 2013-14 में 990.34 करोड़ रुपये और जब एन0डी0ए0 की सरकार प्रदेश में आई तो उस समय यह राशि बढ़कर 2209.92 करोड़ रुपये हुई। इसी तरह से वर्ष 2015-16 में 2326.40 करोड़ रुपये मिले और वर्ष 2016-17 में 2871.65 करोड़ रुपये मिले। यह आंकड़ा 15 फरवरी, 2017 तक का है अभी मार्च चला हुआ तो इसमें और भी एक-डेढ़ महीने का आना है। ये जो बार-बार सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायक और इनके तमाम कार्यकर्त्ता कहते हैं कि हमें केन्द्र की ओर से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है तो मैंने स्थिति आपको बता दी है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो आपको सहायता प्राप्त हो रही है, ये जो 90:10 का अनुपात यू0पी0ए0 की सरकार के समय बन्द था, क्या वह आपको मिलना शुरू हो गया है? यदि हां, तो यह कब से मिलना शुरू हुआ है?

मुख्य मंत्री जी का जवाब श्री जे0एस0 द्वारा-----

29.03.2017/1105/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3975ः------जारी------

Chief Minister: Sir, the Hon'ble Member is rather confused in his thinking. Prior to Financial Year 2015-16 the devolution from the Central Government were received by the State Government as Planning Commission grants, funds recommended by the Finance Commission and amount under Centrally Sponsored Schemes. Besides, Government of India also passes the amounts funded by external agencies such as World Bank , Asian Development Bank etc.

But after the replacement of the Planning Commission by the NITI Aayog, Normal Central Assistance (NCA) and Special Plan Assistance (SPA / SCA) which were the main component of State Plan. Funding has been discontinued and the State Government has been receiving funds on the recommendation of the Finance Commission, various Centrally Sponsored Schemes and for EAPs only. The scheme is discontinued and the amount received during 2014-15 against those schemes are given below .

Names of the Schemes	**Amount received during 2014-15**
NCA	Rs.1382.75 crores
SCA/SPA -	Rs. 1350.00 crores
Rajiv Awas Yojana	Rs. 0.76 crores
NeGAP	Rs. 4.29 crores
RGPSA	Rs.15.26 crores
National Mission on Food Processing	Rs. 1.91 crores
BRGF	Rs. 11.92 crores
National Handloom Development Programme	Rs. 0.51 crores
TOTAL	**Rs. 2767.4 crores**

29.03.2017/1105/जेके/डीसी/2

This is over and above, the what has been given by the 14th Finance Commission. आपका ख्याल है कि भारत सरकार ने जो 14वाँ वित्तायोग है, उससे जो डिवॉल्व हुआ फंड, उसके अलावा हमें बहुत बड़ी रकमें अलग-अलग मद्दों में दी है, यह सही विचार नहीं है, जो हमको मिला है उसका मैंने आपको ब्योरा दे दिया है।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि प्रश्न में लिखा है कि मार्च 2013 से 2017 तक चार सालों में कुल मिला करके जो आपने फिगर यहां पर पढ़ी हैं, उसमें करोड़ों/अरबों के हिसाब से धनराशि भारत सरकार से मिली है। यह कुल धनराशि कितनी प्राप्त हुई है और आपने इस धनराशि में हर वर्ष कितना-कितना पैसा खर्च किया है?

एस0एस0 द्वारा जारी-------

29.03.2017/1110/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3975 क्रमागत

श्री गुलाब सिंह ठाकुर क्रमागतः

और कितना-कितना पैसा जो भारत सरकार से ग्रांट मिली है उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप यह बतायेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा ब्योरा दिया है। पिछले सारे वर्षों का ब्योरा मेरे पास नहीं है। अगर आपने मांगा हो तो वह भी दे देंगे। There is nothing to hide. और बात यह है कि जितना पैसा हमको मिला है हमने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया है।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो ग्रांट आई है उसमें से आपने योजनावार/मदवार हर वर्ष कितना-कितना पैसा खर्च किया और कितना-कितना पैसा अभी आपके पास पड़ा हुआ है जो आप खर्च नहीं कर पाए हैं?

मुख्य मंत्रीः जो आपका मूल प्रश्न है उसमें यह बात नहीं है जो आप अब पूछ रहे हैं। अगर आप यह बात भी प्रश्न में पूछते तो मैं उसका भी जवाब आपको देता और अभी भी मैं कहूंगा कि अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो मैं विभाग से जवाब तैयार करवा कर कुछ दिनों में आपको भेज दूंगा।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने एक अनुपूरक प्रश्न किया था, एक तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि मैं कंफ्यूजड हूं। कंफ्यूजड तो मैं आपकी इन फिगर्ज़ को पढ़कर हो गया। मैंने तो तुलना की है कि यू0पी0ए0 के समय में कितना पैसा प्रदेश को मिला और एन0डी0ए0 सरकार के समय में कितना पैसा आपको मिल रहा है। कंफ्यूजड तो आप कर रहे हैं, आपने फिगर दी है कि एन0डी0ए0 की सरकार आपको ज्यादा सहायतानुदान दे रही है। मैंने तो वही फिगर्ज़ पढ़ी हैं। साथ में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या जो भारत सरकार के द्वारा आपको पैसा मिला, यह जिन योजनाओं के लिए स्वीकृत हुआ क्या वहीं पर यह व्यय किया गया या कहीं अन्य जगहों पर तो खर्च नहीं कर दिया गया?

29.03.2017/1110/SS-AG/2

दूसरा, आपने एक जवाब दिया कि नाबार्ड के तहत ऋण प्राप्त हुआ है। यह 2014-15 में 400 करोड़ रुपया, 2015-16 में 500 करोड़ रुपया और 2016-17 में 484.75 करोड़ रुपया 15.02.2017 तक प्राप्त हुआ है। डेढ़ महीने का फिगर अभी आना शेष है। आपने नाबार्ड के अन्तर्गत सारे विधायकों के लिए राशि की सीमा तय कर दी है। पीछे यह 70 करोड़ रुपया थी और पहली अप्रैल के बाद उसको 80 करोड़ रुपया कर देंगे। क्या वह 70 करोड़ रुपया सभी माननीय विधायकों के क्षेत्रों में आपने बराबर आबंटित किया और

अगर नहीं किया तो क्या उसको भविष्य में जिनको आपने फालतू दिये हैं उनके वहां कटौती करके जिनको नहीं दिये हैं उनको आप आबंटन करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि पहले जो भी पैसा स्टेट गवर्नमैंट को आता था वह मुख्यतः प्लानिंग कमीशन से आता था। उसके अलावा फॉरेन ऐडिड प्रोग्राम होते थे उससे प्राप्त होता था। अब की बार प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। नीति आयोग से हमको कोई पैसा नहीं आता। नीति आयोग पैसा नहीं देता। अब जो भी आया है वह 14वें वित्तायोग की जो रिक्मेंडेशन्ज़ हैं उसके मुताबिक ही हमको पैसा मिला है। उसके अलावा जैसे वर्ल्ड बैंक है या एशियन डिवैल्पमैंट बैंक है या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्ज़ हैं उनसे हमें भारत सरकार ने लोन लेने की इजाज़त दी है। That's all.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले पैसा प्लानिंग कमीशन के माध्यम से आता था, वह सामान्य केन्द्रीय सहायता था। वह 2014-15 में 1382 करोड़ मैक्सिमम आया। लेकिन 2015-16 में जो वित्तायोग की सिफारिश के कारण आया, वह 8430 करोड़ आ गया। तो अगर एक हैड में कम हुआ है तो दूसरे में कई गुणा बढ़ गया। इसलिए फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कुल मिला कर जब प्लानिंग कमीशन था तब आपको ईयरली कितना आता था और अब कितना आ रहा है?

29.03.2017/1110/SS-AG/3

मुख्य मंत्रीः ये तो आपको मालूम है कि 14वें वित्तायोग में हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा आया है। I need not repeat it in this House. Over and above that Himachal Pradesh like any other State in India is also authorized to take loans from the World Bank, Asian Development Bank etc. which we take from time to time as per rules and the limit prescribed for us. That's all.

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2017/1115/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3975 जारी....

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लोन के बारे में तो अभी था ही नहीं। मैं तो यह पूछ रहा था कि प्लानिंग कमिशन जब था , तब आपको एनुअली कितना पैसा मिलता था? प्लानिंग कमिशन नीति आयोग है लेकिन भारत सरकार से आपको कितना प्रतिवर्ष मिल रहा है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है उसमें सारी डिटेल दी गई है। कृपया उसको पढ़ने की तकलीफ कीजिए और अपने प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर आएं।

Prof. Prem Kumar Dhumal: Sir, I take objection to these words, particularly, मुख्य मंत्री हमारे प्रश्न पर खीज रहे हैं परन्तु सवाल यह है कि जो फिगर्ज़ आपने दी हैं उसमें स्पष्ट हो रहा है कि आप गलत प्रॉपगेंडा करते रहे। केन्द्र से कई गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। आप गलत प्रोपगेंडा कर रहे हैं इसलिए हम बार-बार प्वाइंट आऊट कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कह दिया है that is the final reply.

Speaker: No, no. Hon'ble Member (Shri Ravinder Singh) your leader has already satisfied now.

29.03.2017/1115/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3976

श्री मनोहर धीमानः अध्यक्ष महोदय, यह उद्योग कई वर्षों से बन कर तैयार हो गया है लेकिन अभी तक ट्रायल उत्पादन ही शुरू हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कब तक इसमें व्यवसायिक उत्पादन शुरू होगा?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जब केन्द्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने यह कारखाना यहां पर मंजूर किया था और यह लगभग 106 करोड़ का कारखाना है। इसको स्थापित करने को ले कर सेना के कुछ ऑब्जैक्शन्ज़ थे। राज्य सरकार ने उनसे मामला टेकअप किया और यह मसला अब हल हो गया है। कारखाना पूरी तरह तैयार है और इसमें 200 लोगों को रोज़गार मिलना है। ट्रायल चल रहा है, 25 लोग उन्होंने लगाए हैं। बहुत जल्दी यह कमर्शियल उत्पादन में आ जाएगा।

श्री मनोहर धीमानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो 200 लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्या वह इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज के माध्यम से मिलेगा?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का उपक्रम है। उनकी भर्ती के क्या नियम है, उसके मुताबिक वे यह करेंगें लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि यह 106 करोड़ का कारखाना है और 200 लोगों को इसमें रोज़गार दिया जाएगा।

29.03.2017/1115/केएस/एजी/3

प्रश्न संख्याः3977

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 226 केस एफ.सी.ए. क्लीयरैंस के लिए गए हैं और उनमें से 119 पैंडिंग है। ये केसिज़ लम्बे अरसे से पैंडिंग है तो क्या कारण है कि ये केसिज़ क्लीयर नहीं हो रहे हैं ? दूसरा, जो 7th circle Dalhousie के अंडर 14 केसिज़ गए हैं उनमें से सिर्फ भरमौर डिविज़न के क्लीयर हो कर आए हैं। पर्टिकुलरली डलहौज़ी डिविज़न के 6 केसिज़ गए हैं, इनमें से 5 क्लीयर नहीं हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि देहरादून में जो नोडल ऑफिसर्ज़ टेकअप करते हैं क्या वे पिक एण्ड चूज़ बेसिज़ पर करते हैं? क्योंकि कुछ डिविजन्ज़ के इतने-इतने केसिज़ पैंडिंग हैं और कुछ डिविजन्ज़ के सारे केसिज़ क्लीयर हो रहे हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह इत्तेफ़ाक है। It is not meant to be so. मगर यह ठीक है कि जो भी केसिज़ जाते हैं, सभी केसिज़ को प्रस्तुत किया जाता है । कुछ पहले निकल जाते हैं और कुछ प्रोसैस में होते हैं। माननीय सदस्या ने जिस बात का जिक्र किया है, मैं इस बात को देखूंगा और उन केसिज़ को जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्राप्त करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2017/1120/AV/AS/1

प्रश्न संख्या : 3977---------- क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ये केसिज किन कारणों से पैंडिंग हैं। जब यहां से केस बनकर जाता है तो प्रीजम्प्शन यह होती है कि उसमें सारी चीजें डील कर ली गई है। इन केसिज के पैंडिंग होने के मुख्यता क्या कारण है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यता उसमें यह होता है कि क्वायरीज उठाई जाती है और उसके बारे में फर्दर इनफार्मेशन मांगते हैं। एक केस को स्वीकृति देने से पहले कई प्रकार की क्वायरीज आती रहती है। उन क्वायरीज का उत्तर देने के बाद ही वह उस पर गौर करते हैं। This is a very cumbersome and very delaying process.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, फारैस्ट क्लीयरैंस के कारण हमारे बहुत सारे विकास कार्यों में बाधा आई है। हम इस बारे में प्लानिंग की मीटिंग में भी लगातार बात करते रहे हैं कि इस बारे में कोई रास्ता निकाला जाए। हमारी विधायक प्राथमिकता की सारी योजनाएं इस कारण से लम्बित है क्योंकि उनमें फारैस्ट क्लीयरैंस अवेटिड है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे जितने भी इस प्रकार के मामले फारैस्ट क्लीयरैंस के लिए जाते हैं क्या उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि उनमें सारी टैक्निकल या

दूसरी फार्मेलिटीज को एक बार में ही निपटा दिया जाए? हम एक बार नीचे से केस भेजते हैं तो उस पर ऊपर से क्वायरी लगकर आती है। क्वायरी को दूर करके उस केस को फिर से भेजा जाता है मगर दोबारा से क्वायरी लगकर केस वापिस आ जाता है। यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है और इसमें वर्षों बीत जाते हैं। वर्षों बीतने के कारण हमारे प्रदेश के बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास कार्य के प्रोजैक्ट लम्बित पड़े रहते हैं। यहां से जो प्रोजैक्ट भेजे जाते हैं क्या उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि उनकी वन-गो में सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाए और क्वायरीज लगने के कारण वह बार-बार वापिस न आए। क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी?

29.3.2017/1120/AV/AS/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि फारैस्ट क्लीयरैंस का जो मामला है It is a very cumbersome process यहां फारैस्ट डिपार्टमैंट से जो केस बनकर जाते हैं वे माकूल होते हैं फिर भी उनके ऊपर किसी-न-किसी प्रकार की क्वायरी लगाई जाती है। जब उस क्वायरी का जवाब जाता है तो उस पर कोई और नई क्वायरी लगाई जाती है। इसलिए इन योजनाओं में देर हो रही है और मैं समझता हूं कि इसके भुक्तभोगी सारे एम0एल0ए0 हैं क्योंकि सारे निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह का विलम्ब हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है और प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होती। कोई भी प्रोजैक्ट फारैस्ट डिपार्टमैंट के द्वारा आगे स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और वहां से बार-बार क्वायरीज आती है। हम उन क्वायरीज का उत्तर देते हैं और बड़ी मुश्किल से वह पास होता है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजैक्ट रुके हुए हैं। I am very much concerned about it. We have sanctioned the projects, we have got the money for it, it is budgeted मगर काम इसलिए चालू नहीं हो पाता क्योंकि फारैस्ट क्लीयरैंस नहीं मिलती। अब कोशिश की जा रही है कि हम कोई ऐसा तरीका अपनाये जिससे कि ऐसे मामले वहां से जल्दी-से-जल्दी और फाइनल तौर पर मंजूर होकर आए।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार कुल्लू की दो डिविजन से 18 केसिज देहरादून पहुंचे हुए हैं, 11 मामलों में इनप्रिंसिपल अप्रूवल बता रहे हैं और केवल एक केस में अप्रूवल मिली है। जैसे मान्यवर मुख्य महोदय ने स्वयं कहा कि सारे-का-सारा कारण यही है कि जो फारैस्ट क्लीयरैंस में देर होती है। मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को स्मरण करवाना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा था कि जिला स्तर पर सर्कल का जो कन्जर्वेटर है वह नोडल एजैंसी होगी और वह मामले को अंतिम रूप देकर ही आगे फारैस्ट डिपार्टमैंट को भेजेगा।

श्री वर्मा द्वारा जारी

29/03/2017/1125/टी0सी0वी0-ए0एस0/1
प्रश्न संख्या 3977..... क्रमागत
श्री महेश्वर सिंह ..... जारी

लेकिन हो क्या रहा है, जब वह केसिज़ सर्कल से यहां पर आ जाते हैं, तो एक नई एजेंसी खड़ी कर दी गई और टॉलैंड में एक नोडल ऑफिसर बैठा दिया गया है। वन विभाग में इतनी ज्यादा ऑफिसर्ज़ तैनात हैं, इसलिए उनको कोई-न-कोई काम देना है। जहां एक प्रिसिंपल सी0सी0एफ0 होता था, वहीं आज 8-8 सी0सी0एफ0 बैठें हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं, वह बार-बार ऑब्जेक्शन लगाता रहता है। माननीय वन मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, निश्चित रूप से आपके पास बड़े ऑफिसरों की बड़ी फ़ौज है, लेकिन अच्छा गद्दी वह होता है, जो भेड़ें ज्यादा पाले और मेड़ें कम पालें, लेकिन यहां मेड़ें इतने ज्यादा है कि आपस में ही भिड़ते रहते हैं और हमारा सत्यानाश करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या कोई सरलीकरण करेंगे, ताकि ये बार-बार ऑब्जेक्शन्ज़ न लगाएं। ये बेकार में बैठकर फाईलें भेजते रहते हैं और फिर मंत्री जी ऊपर से एक और काम करते हैं, जब सिंगल फाईल फाईनल अप्रूव्ल के लिए आती है, तो कहते हैं, पेड़ जितने कट रहे हैं, उनकी संख्या में कमी लाओ। ये पॉसिब्ल ही नहीं है, जब सारा केस कम्प्लीट करके भेज दिया, तो उसमें कमी कहां से लाएंगे? इसी लिए विलम्ब होता है, तो क्या इन पर अंकुश लगाएंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री महेश्वर सिंह ने कहा है कि फॉरेस्ट केसिज़ को निपटाने में देर हो रही है, वह देर हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में संबंधित क्षेत्र का जो वन मण्डल होता है, वह पूरे कागज़ात को कंप्लीट करके, सारे फैक्ट्स-एण्ड-फिगर्ज़ को देखकर ही एप्लीकेशन को आगे भेजता है, लेकिन जो क्वायरीज़ आती है, वह देहरादून से आती है। देहरादून से इन केसिज़ को मंजूरी दी जाती है। जब क्वायरीज़ आती है, तो तुरन्त उसका जवाब दिया जाना चाहिए। कई दफ़ा मैं देखता हूं कि उन क्वेरिज़ का जवाब समय पर नहीं दिया जाता है। मैंने आदेश दिए हैं कि अगर वहां (देहरादूर) से कोई क्वायरीज़ आती है, तो उसका उत्तर 24 घण्टे के अंदर वापिस जाना चाहिए, ताकि उसमें देरी न हों। ऐसा

नहीं है कि सभी केसिज़ में देर लग रही है, कुछ केसिज़ ऐसे भी हैं, जो मंजूर होकर तुरन्त आ जाते हैं। मगर कुछ ऐसे केसिज़ हैं, जिनमें कोई -न-कोई क्वायरीज़ उठाई जाती है। मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी में इसका खुद भुक्तभोगी हूं और जिसकी वज़ह से कई काम रूके हुए हैं। ऐसे ही सभी विधान सभा क्षेत्रों के अंदर भी हैं। इसका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है? इसके लिए देहरादून में जो मंजूरी देने वाला कार्यालय हैं, उस कार्यालय में भी सरलीकरण करने की आवश्यकता है। ताकि इस प्रकार के केसिज़ जल्दी-से-जल्दी निकलें। कई दफ़ा फ़जूल की क्वायरीज़ आती है जिनका कोई सिर-पांव नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता कि इस डिर्पाटमेंट के अंदर जो लोग स्वीकृति देते हैं, वह जानबूझकर ऐसा करते होंगे, लेकिन मुझे शक-शूबा होता है कि कुछ केसिज़ में वे जानबूझकर ही देरी करते हैं। मैं प्रदेश से बाहर के फॉरेस्ट मिनिस्ट्रों को भी पत्र लिख रहा हूं कि उसको एक्सपीडाइट करने के लिए कुछ करिए और इसके प्रोसिज़र को बदलें। इसमें अनावश्यक क्वायरीज न पूछी जाये।

अध्यक्षः अब बहुत हो गया है, 6 सप्लीमेंटरीज़ हो गई है, अब और कितनी सप्लीमेंटरीज़ करेंगे? ये सारा क्लीयर भी हो गया है। आप लोगों ने इसको शुरू किया और 6

सप्लीमेंटरीज़ कर दी है। ---(व्यवधान)--- What do you want to say Shri Ravinder Singh ji ?

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी ।

29/03/2017/1130/ एन0एस0/डी0सी0 /1

प्रश्न संख्याः 3977 -- क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय देखेंगे कि इसमें सभी माननीय विधायकों की मुश्किल है और वह यह है कि निचले स्तर (मण्डल लैबल) पर फोरैस्ट और पी0डब्लयू0डी0 विभाग की ज्वाईंट इंसपैक्शन होती ही नहीं है। उसके पीछे बहुत सीधा-सा कारण है कि वहां पर पटवारियों की कमी है। डिवीजन में पटवारी जहां पर जा करके पैमाइश/डिमार्केशन करते हैं, वह नहीं हो रही है। आपने कोशिश की भी है लेकिन पटवारी मिलते ही नहीं है। आप मेरे विधान सभा क्षेत्र देहरा डिवीजन को देखें तो वहां पर केवल मात्र तीन ही हैं। हमारी जो सड़कें नाबार्ड में अप्रूव हुई हैं, वे अभी तक पैंडिंग पड़ी हुई हैं, वहां पर कोई उनको देखने के लिए जाता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसके ऊपर यह कहना है कि क्या आप आउटसोर्सिंग के द्वारा जो कानूनगो और पटवारी रिटायर हो चुके हैं, उनको हायर करके एक समयबद्ध सीमा 3-4 महीने के अन्तराल में स्पैसिफिक जो राशि उन सड़कों के लिए नाबार्ड या विभिन्न एजैंसियों के माध्यम से सैंक्शन हुई है, इनको आप 3-4 महीनों में पूरा करेंगे? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश की लगभग 2700-2800 सड़कें लम्बित पड़ी हुई हैं। उन सड़कों के लम्बित रहने के पीछे क्या कारण है? एक बार उन सड़कों का केस बन गया था लेकिन न तो उन सड़कों को वन विभाग ने टेकअप किया और न ही पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने टेकअप किया है। वे सड़कें हमारे ग्रामीण विकास विभाग या पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने बनाई हैं लेकिन उनकी क्लीयरैंस नहीं मिल रही है। क्या आप आदेश करेंगे कि

इन सड़कों को प्रायोरिटी के आधार पर डिमार्केशन करके एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस के लिए भेजा जाए?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने यहां पर जो प्रश्न उठाया है या फिर अपनी समस्या के बारे में बतलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है।

प्रश्न समाप्त

29/03/2017/1130/ एन0एस0/डी0सी0 /2

प्रश्न संख्याः 3978

डा0 राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है, उसके अनुसार आपने 791 बसें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत खरीदी हैं और उसमें से काफी सारी बसें ऐसी हैं जो उपयोग में नहीं आ रही हैं। क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितनी बसें ऐसी हैं जो उपयोग में नहीं आ रही हैं और उसमें कितने स्टॉफ की कमी है तथा आप कितने दिनों में स्टॉफ को पूरा करेंगे? दूसरा, मैं जानना चाहता हूं जैसा कि आपने बताया कि 163.68 करोड़ रूपये की राशि केंद्र से मिली है और शेष आपने अधिक खर्च किया है। इसमें केंद्र से सहायता मिलते समय कितने प्रतिशत प्रावधान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का था?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राजीव जी ने पहली बात कही है कि 791 बसें वर्ष 2013 में जब यू0पी0ए0 की सरकार थी तो उस वक्त हमने यह प्रोजैक्ट मंजूर करवाया था। इसके साथ-साथ 63 करोड़ रूपये का वर्कशॉप का प्रोजैक्ट भी मंजूर हुआ था। यह टोटल 200 करोड़ रूपये की राशि का प्रोजैक्ट था। इस 200 करोड़ रूपये की राशि में हमारा 25 प्रतिशत का हिस्सा जाना था और उसी को मिला करके यह 200 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट था। हमें 791 बसों के अंगेस्ट 163.68 करोड़ रूपये की राशि मिल चुकी है। यह एक महत्वकांक्षी प्रोजैक्ट था। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश था जिसने अपनी रिपोर्ट समय पर बना करके दी है और सबसे ज्यादा बसें लेने में हम लोग कामयाब भी हुए हैं। आपने स्टॉफ की कमी के बारे में पूछा है तो

मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि उसकी प्रक्रिया चालू है। उसमें ड्राईवरों की भर्ती चली हुई है और कंडक्टरों की भर्ती पर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है तथा यह केस मान्य कोर्ट में चला हुआ है।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने नालागढ़ डिपो के लिए 37 बसों की बात की है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी बसें रूटों पर चलती हैं और कितनी बसें स्टॉफ की कमी के चलते आइडल खड़ी हैं? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नालागढ़ डिपों में बहुत ही कम बसें हैं।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

29/03/2017/1135/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3978...जारी

श्री कृष्ण लाल ठाकुर... जारी

क्या नालागढ़ डिपो को और बसें दी जाएंगी? कुछ रुट आपने टैम्परेरी, kept in abeyance रखे थे, वे रूट्स कितने थे, कितने रिस्टोर कर दिए गए हैं और बाकी कब तक रिस्टोर किए जाएंगे? नये रूट्स में बसें चलाने की क्या पोसिबिलिटीज़ हैं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो बसिज़ दी हुई हैं, वे अधिकांश रोड़ के ऊपर चल रही हैं। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि बसों की फ्लीट 3000 से ऊपर हो गई हैं, जोकि पहले 1700 के करीब थी। यह प्रैक्टिकली डबल हो गया है। सड़कें बहुत ज्यादा बन रही हैं और हम बसों का ज्यादा प्रावधान कर रहे हैं। मैंने माननीय सदस्य को कहा था कि जहां बसों की शोर्टेज़ होगी वहां और बसें प्रोवाइड की जाएंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में हमें 250 छोटी बसिज़ खरीदने के आदेश दिए हैं। इसकी टेंडर प्रकिया चल रही है। जैसे ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है, हम और बसें

खरीदेंगे। हर जगह जहां छोटी बसों को चलाने की व्यवस्था होगी वहां हम छोटी बसें उपलब्ध करवाएंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जिला सिरमौर में कुल कितनी बसिज़ हैं और शिलाई विधान सभा क्षेत्र में इस वक्त कितने बस रूट्स अप्रूवड हैं? वर्तमान में कितनी बसिज़ शिलाई विधान सभा क्षेत्र में चल रही हैं और आगे सरकार कितनी बसिज़ चलाने का विचार रखती है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसका ब्योरा क्षेत्रवार नहीं होता है, यह डिपोवार होता है। अगर माननीय विधायक जी की यह मंशा है कि कौन से नए रूट चलाये जाएंगे उसके लिए कृपा करके आप मेरे साथ बैठ के बात करें। उसका समाधान निकालेंगे।

29/03/2017/1135/RKS/DC/2

डॉ राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह प्रोजैक्ट 200 करोड़ रुपये का था। मैं यह जानना चाहता हूं कि एन.डी.ए. गवर्नमैंट आने के बाद इसमें कितनी धनराशि प्राप्त हुई। क्या सारी-की-सारी धनराशि खर्च कर दी या कुछ राशि शेष है? क्या केंद्र सरकार से कुछ और राशि आना बाकी है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजैक्ट पूरे देश में यू.पी.ए. सरकार के समय में शुरू हुआ था। उस वक्त हमने कोशिश करके सबसे पहले प्रोजैक्ट रिपोर्ट दी और हमें 200 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट मिला। माह अक्तूबर, 2013 में यह प्रोजैक्ट अप्रूव हो गया था। उसके बाद दूसरे मद में राशि हमें अभी प्राप्त हुई है। 163 करोड़ रुपये की राशि आ चुकी है। (व्यवधान)... धूमल साहब, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं। 21 करोड़ रुपये की राशि अभी आनी है। मुझे आपसे एक आग्रह करना है कि कृपा करके जो 63 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट हमारा खत्म कर दिया है जोकि एच.आर.टी. सी. की कार्यशालाओं को स्ट्रेंथन करने का था, उसके लिए आप सभी लोग जाइए(विपक्ष वाले)

और मुझे भी साथ ले जाइये। अगर हमारे जाने से 63 करोड़ रुपये आ जाते हैं तो मैं आपका दो बार धन्यवाद करूंगा।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि नये रूट्स को चलाने के लिए आश्वासन दिया जाए। बहुत सारे रूट्स पी.डब्ल्यू.डी. से पास हो गये हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा जब माननीय सदस्य मेरे पास आएंगे तो हम रूट वाईज़ डिस्कस कर लेंगे। (व्यवधान)... आप मेरे पास आना जहां बसें चलाई जा सकती हैं वहां हम बसें चलाएंगे। नई बसें आने दो आपको बसें दे दी जाएगी।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

29.03.2017/1140/SLS-AG-1

Question No. 3978 continues . . .
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister Continues . .

Hon'ble Speaker, Sir, within due course of time, I will start few buses in Nalagarh.

Concluded

29.03.2017/1140/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 3979

डॉ० राजीव सैजल : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके 'क' भाग में बताया गया है कि इस फोरलेन सड़क का निर्माण M/S G. R. Infrastructure

Projects Ltd. द्वारा किया जा रहा है। भाग 'ख' में दुर्घटनाओं की जानकारी दी गई हैं लेकिन इसमें परवाणु से लेकर ढली तक की जानकारी दे दी गई है जबकि फार्स्ट फेज़ में केवल टिम्बर ट्रेल से चम्बाघाट तक ही इस सड़क पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि जब से इस फोरलेन पर कार्य शुरू हुआ है, इससे चम्बाघाट और टिम्बर ट्रेल के बीच में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इसके 3 कारण हैं। जिस कंपनी को यह निर्माण कार्य दिया गया है, वह वांछित अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है। उनसे 3 प्रकार की अपेक्षाएं हैं। पहली यह कि जहां यह कार्य शुरू हुआ है वहां धूल ज्यादा न उड़े, इसके लिए कंपनी को सुनिश्चित करना है कि वहां पानी का छिड़काव नियमित हो, जो कि वे नहीं कर रहे हैं। दूसरे, यह निर्माण कार्य कुछ भागों में शुरू हुआ है और जहां निर्माण कार्य चला है वहां रोड को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा वह है जहां कार्य शुरू है; जहां बिछाई का काम हो रहा है। दूसरा हिस्सा वह है जहां ट्रैफिक को चालू रखा गया है। जिस हिस्से पर ट्रैफिक चल रहा है, यह कंपनी उसकी मेंटेनैंस नहीं कर रही है। इस पोर्शन पर अनेकों गड्ढे बन गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में एक बस बच्चों को लेकर पंजाब से आई थी जो वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दैवयोग से किसी बच्चे के साथ तो कैजुअल्टी पेश नहीं आई लेकिन उस बस का कंडक्टर मारा गया। तीसरे, पहाड़ी की तरफ़ जो कटान हुआ है वहां ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। बरसात में पत्थर गाड़ी पर आकर भी गिरे हैं। मैं समझता हूं कि एक तो वहां पानी का छिड़काव नियमित हो,...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप अपना सप्लीमैंटरी ब्रीफ में रखें। इतना लंबा सप्लीमैंटरी नहीं होता।

डॉ० राजीव सैजल : सर, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और सरकार यह सुनिश्चित करें और आश्वासन दें कि उस कंपनी से जो अपेक्षाएं हैं, उनको कंपनी

29.03.2017/1140/SLS-AG-3

पूरा करे ताकि वहां दुर्घटनाएं न हों, धूल न उड़ती रहे और विशेषकर टू व्हीलर्ज़ को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, वह परेशानी उन्हें न झेलनी पड़े। क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी, यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कालका से शिमला नेशनल हाईवे का काम दो अलग-अलग कंपनियों में बांटा गया है। इन्होंने कालका से सोलन तक के हिस्से के बारे में अपना प्रश्न रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य की चिंताएं हैं, उनके कंसर्न्ज हैं, हम उनको देखेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं यह बात कह सकता हूं कि कुल मिलाकर इस सड़क पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यदि यही गति रही और इसी स्पीड से काम होता रहेगा तो जो कंपनी का लक्ष्य है; जिस लक्ष्य के भीतर यह सड़क बनकर तैयार होनी है, उस लक्ष्य को वे प्राप्त कर लेंगे। यह एक पहलू है। दूसरे, अगर इस सड़क को बनाते समय यदि यात्रियों को कोई कठिनाई आ रही है उनको लेकर आपने जो अपनी चिंताएं बताई हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान देगी।

समाप्त

अगला प्रश्न ...श्री गर्ग जी

29/03/2017/1145/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3980

श्री हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इतना कठिन भी नहीं था कि सूचना एकत्रित की जाती रहे क्योंकि मैंने तो चुराह और चंबा के बारे में पूछा था, लेकिन यह प्रश्न क्लब कर दिया गया है। बाकी माननीय सदस्य अपने तौर से पूछेंगे। लेकिन मेरा मूल प्रश्न था कि 'सरकार ने कौशल विकास परिषद का गठन करने के उपरांत इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2017 तक कितने बेरोजगारों को

रोजगार दिया? दूसरा प्रश्न मेरा था कि चंबा में किन-किन संस्थानों को प्राधिकृत किया है जो वहां कौशल विकास के नाम पर अलग-अलग ट्रेड्ज में प्रशिक्षण दे रहे हैं? तीसरा यह पूछा था कि चुराह विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां कौशल विकास परिषद जिसका इन्होंने गठन किया है, उससे रोजगार सृजन के लिए कई तरीके से प्रोत्साहन मिल सकता था। क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार अलग-अलग मामलों में फंस रहे हैं। जैसे नारकोटिक्स के बहुत सारे केस होते हैं। अगर हम इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते, तो अच्छा होता और बहुत से संस्थान ऐसे हैं जिनको अवैध तरीके से प्राधिकृत किया गया था, लेकिन अब प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वस्त करेंगे कि विस्तृत सूचना हमें इसी सत्र के दौरान मिल जाएगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न लगा है, यह पूरी तरह अव्यवहारिक प्रश्न है, इसका उत्तर तैयार करवाना संभव हीं नहीं है, यह कौशल विकास योजना की स्प्रिट के बाहर का सवाल है, इसे तैयार करवाने के लिए यदि सारी मैन पॉवर लगा दी जाए, तब भी 6 महीने लगेंगे, इसके लिए दर्जनों-दर्जनों कागज़ के रिम लगेंगे और सारा विभाग व प्रशासन इसमें लगाने के बाद भी इसका उत्तर तैयार नहीं होगा क्योंकि जो बात यह यहां सदन में कह रहे हैं और जो प्रश्न लगाया गया है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि विधान सभा सचिवालय को यह प्रश्न यहां लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि इन्होंने कहा है कि जितने भी संस्थान हैं, उन सबको नपवाया जाए। अब सारे संस्थान नापे जाएंगे। कौशल विकास भत्ते के बारे में इन्होंने पूछा है कि किस-किसको कौशल विकास भत्ता मिला, तो हम इनको वह सूची दे देते, लेकिन फिर इन्होंने पूछा कि कहां-कहां वे रोजगार मिले, तो हम उनको कहां देखने जाएं, उसके बाद इन्होंने पूछा कि जितने भी संस्थान हैं उनमें क्या अनियमित्ता हुई? तो ऐसे प्रश्न के लिए कितनी मैन पॉवर चाहिए, कितना समय

29/03/2017/1145/RG/AG/2

चाहिए और 6 महीने लगाकर भी सूचना आना मुश्किल है। जो चीज संभव ही नहीं है, अगर माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि चुराह में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, तो हम इनको यह सूचना दे सकते हैं, कौन-कौन व्यक्ति है, तो हम इस बारे में इनको सूचना दे सकते हैं और उसको कितना-कितना मिला। लेकिन इन्होंने तो इतना बड़ा सवाल खड़ा

कर दिया। क्योंकि इनके साथ माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी लग गए। वे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अपनी जिन्दगी का सारा तजुर्बा इस प्रश्न में लगा दिया ताकि सारा विभाग 6-8 महीने तक व्यस्त रहे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने या तो स्वयं ठीक ढंग से प्रश्न नहीं पढ़ा या जो इनके मन में वहम थे, वे इनकी जुवान पर आ गए। इसमें यह कहां पूछा गया है कि अनियमित्ताएं कहां-कहां हुईं? (ग) में यह है कि 'कितने ट्रेड्ज में विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है?' तो आपने जिन-जिन संस्थानों में प्रशिक्षण दिया है, उनकी सूची देने में क्या दिक्कत है?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धूमल साहब तो दो बार मुख्य मंत्री रहे हैं और ये सिर्फ अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं। जबकि ये स्वयं समझ चुके हैं कि जितने संस्थान हैं उन सबको नपवाने की बात कह दी, जितने संस्थान हैं उन सबमें अनियमित्ताओं की बात कह दी, जितने संस्थान हैं उनके द्वारा मिली नौकरियों का ब्योरा कह दिया। जो बात माननीय सदस्य श्री हंस राज जी यहां पूछ रहे हैं, वह मैं निश्चित तौर पर इनको दे देता और वह मैं इनको कमरे में भी दे दूंगा, लेकिन श्री महेन्द्र सिंह जी का जो ऐक्सपर्ट ओपीनियन इसमें लगा, उसके बाद यह प्रश्न अव्यवहारिक हो गया है।

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2017/1150/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3980 क्रमागत---

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं अभी प्रश्न पूछ ही रहा था। माननीय संसदीय कार्यमंत्री, उद्योग मंत्री भी हैं, आप बोलने के लिए बीच में ही खड़े हो गए। कहने का भाव यह है कि प्रश्न या तो आप सचिवालय से स्वीकार ही न करते। जब डिटेल्ड प्रश्न स्वीकार हुआ है और आपके विभाग ने भी किया है, अब आप कह रहे हैं कि सारे विभाग को लगा दें

तो भी छः महीने में नहीं हो सकता। पैमाइश तो छः महीने में हो सकती है अगर पैमाइश का भी प्रश्न हो। अगर आपका पूरा विभाग उन संस्थानों की पैमाइश करने में लग जाएगा तो यह काम हो सकता है। प्रश्न इस करके पैदा हुआ कि जिन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है वे इसके योग्य ही नहीं हैं। प्रश्न तो यह है। इसलिए उनकी पैमाइश के लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं हो सकती है? पैमाइश हो सकती है आप रिकॉर्ड मंगवाइए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो धूमल साहब कह रहे हैं, वैसे संस्थान हमने पहले ही जिलाधीशों की जांच के बाद हटा दिए थे। अब तो वे संस्थान हैं जो मल्टी नेशनल हैं, जो अच्छे संस्थान हैं या जो जिलधीश से जांच करवाने के बाद बचे हुए हैं। उनको नपवाने के लिए इतने मल्टी नेशनल के हैड क्वार्टर में हम कहां जाएंगे? आप दो दफा मुख्य मंत्री रहे हैं और आपको यह स्वयं भी मानना चाहिए कि यह सवाल अव्यवहारिक है। इस सवाल को विधान सभा सचिवालय को नहीं लगाना चाहिए इस बात से मैं आपके साथ सहमत हूं लेकिन अब यह हमारे पास आ गया है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें जितनी सूचना मांगी गई है, आज दिन तक विधान सभा में किसी ने ऐसा प्रश्न लगाया ही नहीं होगा जैसा महेन्द्र सिंह जी ने लगाया है।

अध्यक्षः बात यह है कि The information is not available with the Hon'ble Minister, तो आप क्या बात पूछेंगे? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सूचना नहीं है। No, next Question. यह गलत बात है। He said there is no information.

29/03/2017/1150/MS/AS/2

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मंत्री जी गलत कह रहे हैं और ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्षः जब सूचना है ही नहीं तो आप क्या मांगेंगे? He said there in no information regarding this....(Interruption)...कृपा करके आप लोग ऐसा मत कीजिए।

..(Interruption).. Shri Mahender Singh, you say something which this Question does not require.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो आपकी चेयर को भी गुनहगार ठहरा रहे हैं कि विधान सभा सचिवालय को यह प्रश्न स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। आपकी चेयर को इस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री और मंत्री कह रहे हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसी प्रकार का "कौशल विकास भत्ते" का प्रश्न दिसम्बर, 2016 को विधान सभा में लगा है और आपने उसकी सूचना दी है। हम आपसे उस सूचना के अलावा यह जानना चाहते थे क्योंकि आपने उस सूचना में कहा था कि जितने भी कौशल विकास भत्ते के लिए प्रशिक्षणार्थी हैं, हम उन सबको यानी जितना-जितना उनका मानदेय बनता है, वह आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनको दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारा इनके ऊपर एक ही आरोप है। अध्यक्ष जी, इन्होंने दूसरी बात कही कि जितनी ऐसी डिफंक्ट इकाइयां थीं, जो ऐसे ही चली हुई थी उनको जिलाधीशों ने हटा दिया है। अगर डिफंक्ट इकाइयां चली हुई थीं तो आज भी एक अखबार में छपा है कि "कौशल विकास भत्ते के नाम पर की ठगी- हिमकॉन नामक संस्था ने दी 1000/-रुपये देकर 3000/-रुपये सरकार से लेने की पगार"। अगर आप आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एक-एक व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं फिर जो हजारों ऐसी इकाइयां हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ते के नाम पर चली हुई हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह उस प्रश्न के उत्तर में है जो प्रश्न पीछे दिया हुआ है। उसमें एक हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था, बस्सी, हमीरपुर इसके 90 सेंटर चले हुए हैं। यह मंत्री जी ने उत्तर दिया है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जिन प्रशिक्षणार्थियों को आप 1000/- रुपये या 1500/- रुपये दे रहे हैं,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

29.03.2017/1155/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3980:-------**जारी**----

श्री महेन्द्र सिंहः----जारी--------

क्या वह सारे का सारा पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है या फिर वह पैसा उनके अकाउंट में न जा करके जितनी इकाईयां हैं, जो-जो इकाईयां चली हुई हैं उनके माध्यम से दिया जा रहा है? आदरणीय अध्यक्ष जी हो क्या रहा है कि जिन्होंने इकाईयां चलाई हुई है पैसा उनको जा रहा है? वह 1000/- रूपये की जगह 700/-रूपये अभ्यार्थियों को दे रहे हैं और 300/-रूपये अपने पास रख रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसमें ऐसा कोई व्यक्ति बिठा करके हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो इस प्रकार के संस्थान चले हुए थे, उनकी पूरी छानबीन करके, इस प्रकार के जो घपले हुए हैं उनकी जांच करके उन दोषियों को क्या आप सजा दिलाएंगे?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि महेन्द्र सिंह जी आपके आसन्न का बहुत सम्मान करते हैं। जहां तक ये पिछले सवाल की बात कर रहे हैं, हम 1 लाख 55 हजार लोगों को, जिनको कौशल विकास भत्ता मिला है या जिनको 124 करोड़ रूपया मिला है। किनको मिला है और कितनी राशि मिली है, यह सूची तो हमने पहले भी मुहैया करवाई है और अब भी मुहैया करवा सकते हैं लेकिन अब इन्होंने इसका स्कोप ऐसे एन्लार्ज किया है जो कि सम्भव नहीं है। दूसरे ये कह रहे हैं कि कोई 700/-रूपये देता है और किसी को 300/-रूपये मिलता है। ये आपके मन का वहम है। ____(व्यवधान)____ आप पहले सुन भी लिया करो। आपकी बात जब हम आराम से सुनते हैं तो आप भी सुन लिया करो। सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं होता है। जब हम आपको बता रहे हैं कि कौशल विकास भत्ता पूरे का पूरा केंडिडेट के खाते में जाता है, किसी फर्म को नहीं जाता है। इसमें ठगी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। केंडिडेट के खाते में पैसा जाता है अगर केंडिडेट आगे किसी को देता है वह अलग बात है। अखबार में क्या छपा है यह आप ऑथैंटिकेट करके रखें हम उसकी पड़ताल करेंगे? लेकिन कौशल विकास भत्ता केंडिडेट के बिल्कुल खाते

में जाता है इसमें ठगी की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। 1 लाख 55 हजार लोगों को कौशल विकास भत्ता मिला है और 124 करोड़ रूपएं बांटे गए हैं। इसमें 100 करोड़ रूपया हमें सरकार दे रही है। लेकिन जो चीजें आपने इसमें डाली है, यह आपने जानबूझ करके किया है। जब एक बार हमनें जांच करवा ली और डी0सी0 ने कह दिया कि ये संस्थान हटा दो। वे सारे के सारे संस्थान हटा दिए गए लेकिन पैसा तब भी उनको नहीं जाता था। (व्यवधान) जब नई योजना आई , (व्यवधान) नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जब योजना आई।

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज सुन लीजिए।

उद्योग मंत्रीः कुछ लोगों ने आन-फानन में संस्थान खोलने की कोशिश की। हमने उसके नियम तय कर दिए। अब तो बिल्कुल सीमित संस्थान हैं। पैसा व्यक्ति के खाते में जाता है और इसमें ठगी की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप कह रहे हैं कि भत्ता संस्थान वाले खा रहे हैं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संस्थान ठीक नहीं है। जब मंत्री जी ने कह दिया कि भत्ता अकाउंट में जाता है तो फिर ऐसी चीजें नहीं हो सकती है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि इस प्रश्न के ज़वाब में माननीय मंत्री महोदय ने सारे का सारा ज़वाब दे दिया। जवाब में लिखा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब आपके पास पहले यह सूचना थी तो आपने पहले सदन को गुमराह क्यों किया? अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 11 मिनट लगे और सूचना एकत्रित ही की जा रही है। मेरा आपसे प्रश्न है कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जब आपके पास इसकी सूचना थी तो आप इस प्रश्न की सूचना को पूरा करते। क्या सरकार सोई पड़ी है? सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है? ___(व्यवधान)___

29.03.2017/1155/जेके/एएस/3

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्य, सरकार जाग रही है इसीलिए ज़वाब दे रही है। सरकार पूरी तरह से सजग है और सरकार पूरी तरह से जाग रही है लेकिन आधे-अधूरे सवाल का ज़वाब नहीं दिया जा सकता है। आपने ने क,ख,ग,घ,च,छ और पता नहीं कहां तक सवाल लगा दिए? आपने कहां तक सवाल पूछा? फिर आपने कहा कि सारे संस्थान कहां है और कहां-कहां नौकरियां मिल रही है? कहां-कहां अनियमितताएं हो रही हैं? हम आधे-अधूरे का ज़वाब नहीं दे सकते हैं। ____(व्यवधान)____

अध्यक्षः ये कह रहे हैं कि पैसा अकाऊंट में जाता है।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पैसा अभ्यर्थी के खाते में ही जाता है। ये आपका पोलिटिकल एजैंडा है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

29.03.2017/1200/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3980 क्रमागत

उद्योग मंत्री क्रमागतः

माननीय सदस्य आप अपनी कांस्टीचुऐंसी में जा कर बच्चों से पूछो और फिर यहां बात करना।

प्रश्नकाल समाप्त

29.03.2017/1200/SS-DC/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;
ii. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 18.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.05.2016 को प्रकाशित;
iii. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक 16.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.04.2015 को प्रकाशित;और
iv. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 37 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(1)-1/2013 दिनांक

17.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.03.2015 को प्रकाशित।

29.03.2017/1200/SS-DC/3

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-बी(2)-2/2015 दिनांक 02.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2017 को प्रकाशित;
ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, कृषि प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-बी(2)-2/2014 दिनांक 02.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2017 को प्रकाशित;
iii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16;
iv. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित);

v. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

vi. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

29.03.2017/1200/SS-DC/4

vii. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सप्लाई कोड, 2009, विद्युत सप्लाई कोड समीक्षा पेनल को पुर्नगठित करने बारे) जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 (सप्लाई कोड) दिनांक 22.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.03.2016 को प्रकाशित;

viii. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व एवं इसकी अनुपालना)(द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 30.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.03.2016 को प्रकाशित;

ix. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ शुल्क के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 दिनांक 11.04.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.04.2016 को प्रकाशित;

x. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (क्रॉस रियायती अधिभार, अतिरिक्त और क्रॉस रियायती अधिभार को चरणबद्ध करने बारे) (प्रथम् संशोधन) विनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीइआरसी/391 दिनांक 10.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.11.2016 को प्रकाशित; और

xi. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बिज़ली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसी/419 दिनांक 23.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2017 को प्रकाशित ।

((vii) से (xi) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

29.03.2017/1200/SS-DC/5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

i. समिति का **177वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है;
ii. समिति का **178वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष

2012-13 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का **179वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **सचिवालय प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

29.03.2017/1200/SS-DC/6

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति (वर्ष 2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

i. समिति का **25वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/कार्यों के आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **26वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूंः-

i. समिति का **71वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) (वर्ष 2009-10) के ऑडिट पैरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है ।

29.03.2017/1200/SS-DC/7

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज जी --(व्यवधान)-- मुझे बोलने तो दीजिये। मैं आपका नाम बोल रहा हूं। आपका नोट मुझे आया हुआ है। अब श्री सुरेश भारद्वाज जी कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आजकल हिमाचल प्रदेश का बजट पास कर रहे हैं और डिमांडस के ऊपर चर्चा हो रही है तथा कटौती प्रस्ताव चर्चा में हैं। परसों मांग नं0-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर जवाब आना था। लेकिन जवाब को अगले कल टालने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने प्रयत्न किया। कल उसका जवाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दिया। जवाब एक बजे के बाद भी चलता रहा। लगभग डेढ़ बजे के करीब जवाब खत्म हुआ। जवाब हमने बैठ करके सुना। उनसे क्लैरीफिकेशन्ज़ लीं, वे जवाब नहीं दे सके तो जवाब से असंतुष्ट हो करके हमने वाकआउट किया। क्योंकि वह लंच टाइम था, आपके बुलेटिन नं0-2 में स्पैसिफिकली यह लिखा गया है कि सामान्यतः एक बजे से विधान सभा लंच अवकाश के लिए उठेगी। हमारा इम्प्रैशन यह था कि जवाब आ गया है,

मांग इसकी निकल जायेगी और अगली मांगें लंच के बाद टेक अप होंगी। इसलिए हमने जब सदन से वाकआउट किया तो हम वापिस नहीं आए थे। जब लंच टाइम है तो लंच टाइम में जान-बूझकरके जो सबसे बड़ी मांगें शिक्षा विभाग और पी0डब्ल्यू0डी0 महकमें की थीं, जिसके ऊपर एक नहीं बल्कि 10-10, 15-15 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दे रखे थे और हिमाचल प्रदेश के ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं तथा दोनों ही विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2017/1205/केएस/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब न देना पड़े, क्योंकि शिक्षा और पी0डब्ल्यू0डी0 में ही सबसे ज्यादा अकर्मण्यता आज हिमाचल प्रदेश में हो रही है। जिस प्रकार से कॉलेजिज़ और स्कूल खुल रहे हैं और वहां पर टीचर्ज़ नहीं हैं, पढ़ाई में यह हाल हो गया है कि पब्लिक सर्विस कमिशन में हिमाचल प्रदेश का एक भी युवक एच.ए.एस. में पास नहीं हुआ। लॉ सैक्रेटरी बैठे हैं, ये इस बात को जानते हैं । ऐसी गुणवत्ता शिक्षा की है। रूसा सिस्टम चल रहा है। सारा हिमाचल प्रदेश रोष में हैं और उनकी डिमांड्ज़ पर जब चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा का अधिकार विधान सभा में हमें मिला हुआ है क्योंकि हमें जनता ने चुनकर यहां भेजा है और जनता की बात यहां पर करें, उस बात को भी नहीं करना चाहते हैं। सदन चलाना नहीं चाहते। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इस प्रकार से कल दोनों डिमाण्ड्ज को खत्म कर दिया है जिसकी हम भरपूर निन्दा करते हैं और इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अगर ऐसा ही व्यवहार भविष्य में भी रहा तो लोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाना मुश्किल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात केवल मात्र रिकॉर्ड के लिए आपके सामने रखना चाहता था।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी रिकॉर्ड के लिए ही कहना चाहता हूं कि जिस वक्त ये मांगे आनी थी, they were out of the House, आपने वाकआऊट किया था । The House was not adjourned for the lunch, you just Walked Out और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने आगे की कार्यवाही की। उन्होंने दो मांगे रखी। दो मांगें कोई दो मिनट में पास नहीं हुई। उस दौरान भी आप वापिस नहीं आए। (व्यवधान) अगर आप इतने विज़िलैंट हैं then you should have been here, वाक आऊट करके एकदम दरवाजे से वापिस आ जाते। अध्यक्ष महोदय, कसूर इनका अपना है। यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ।

29.03.2017/1205/केएस/डीसी/2

Speaker: Hon'ble Prof. Prem Kumar Bhumal Ji, you would like to say something. ---(interruption)--- Please, when somebody is speaking, you all should keep quite.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय भारद्वाज जी ने कल की घटना का जिक्र किया । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब एक बजे भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का उत्तर दे रहे थे तब भी साधारणतया पीठ से पूछा जाता है कि मंत्री जी आप कितना समय और लेंगें और उसके बाद आप चर्चा अलाऊ करते हैं और सदन अग्री कर जाता है और जब वह आइटम खत्म होती है तो लंच आवर होता ही है। स्वभाविक था, वह बात मिस हुई। आपने भी हाऊस एक्सटैंड करने की बात नहीं की कि लंच आवर लेट होगा। हमने पूरा उत्तर सुना। कुछ शंकाएं सदस्यों की थी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन्ज़ लीं। मंत्री जी के उत्तर से वे संतुष्ट नहीं थे । स्वाभाविक था अध्यक्ष महोदय, आप सदन में उन कटौती प्रस्तावों पर वोटिंग करवाते और वह मद पास हो जाती। उसके बाद अगली डिमांड लेने से पहले लंच टाईम ड्यू था। डेढ़ तो बज चुका था। यह भी सही है कि सत्तारूढ़ दल बहुमत में

हैं। पहले पुलिस और सम्बद्ध संगठनों पर चर्चा हुई । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं अपना लिखा हुआ जवाब सदन के पटल पर रखता हूं। उत्तर तब भी नहीं दे पाए। स्वास्थ्य मंत्री से भी लोग संतुष्ट नहीं थे। तो अगर लोक निर्माण और शिक्षा विभाग की मांगों पर भी चर्चा हो जाती, हम अपने ग्रीवन्सिज़ रखते। जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, वे अपने सुझाव रखते। जो आलोचना करनी थी, आलोचना होती। लोकतंत्र में यह होता है। उसका उत्तर सम्बन्धित मंत्री देते तो तब भी वह वोट से पास हो जानी थी। लेकिन जिस तरह यह शॉर्टकट अपनाया गया, कि आप हाऊस में नहीं थे इसलिए दो डिमांड्ज़ पेश हो गई तो आप बाकी डिमांड्ज़ भी पेश कर देते। गिलोटिन अगले कल लगना था, पिछले कल लगा देते।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2017/1210/AV/AG/1

श्री प्रेम कुमार धूमल -------- जारी

(---व्यवधान---) इन्होंने ठीक किया जो आपकी (बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री) बात नहीं मानी, आप जैसे ऐडवाइजर होंगे तब तो सारा बेड़ा गर्क हो जायेगा। (---व्यवधान---) लेकिन ऐसा करना गलत था और यह लोकतंत्र की हत्या है। अध्यक्ष महोदय, अगर चर्चा होती तो बहुत अच्छा होता। लोक निर्माण विभाग के बहुत सारे मुद्दे जैसे आज प्रदेश में सड़कों की स्थिति है हम उन बातों को आपके ध्यान में लाना चाहते थे। लेकिन जिस जल्दबाजी में किया गया है वह निन्दनीय है। हम उसमें अपना प्रोटैस्ट रजिस्टर करवाना चाहते हैं कि गलत हुआ है और यह प्रथा गलत रही है। लंच आवर में लोक निर्माण और शिक्षा से सम्बंधित दो मागों को पास करना गलत था।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छा होता अगर माननीय सदस्य सदन में होते और उन मांगों पर चर्चा होती। ये लोग बाहर गये You didn't adjourn the

House. House was in session. और उस दौरान दो मांगें पास हो गई। It is their negligence. They chose to walk-out at a time when they should have been in the House to present their point of view. (---व्यवधान---) हमें कोई डर नहीं है। हम बैठने को तैयार थे, चाहे रात के 12.00 भी बज जाते। हमारे पास बहुमत है तो हमें किस चीज का डर है? आप लोग ही छोटी-छोटी बातों को लेकर वाकआऊट करते रहते हैं। आपने वाकआऊट किया You went out. हमने आपको हाऊस से नहीं निकाला, स्पीकर ने आपको हाऊस से नहीं निकाला। House was in session. Naturally, he called for the next item and next item was passed. उसके बाद दूसरी आइटम भी पास हो गई। (---व्यवधान---) नहीं, नहीं। House had not been adjourned. हाऊस एडजर्न होता तो दूसरी बात थी। (---व्यवधान---) हां, इसका मतलब यह है कि आप लोग इन मांगों के प्रति सीरियस नहीं है। (---व्यवधान---) आप लोग सिर्फ पोलिटिकल ड्रामा करते रहते हैं। (---व्यवधान---)

Speaker: I request every Hon'ble Member that let us finish this matter now. When the items are being taken you should be present. You should not go out

29.3.2017/1210/AV/AG/2

so that you can participate in that because this is important, as important for you as a Ruling Party. What has happened yesterday . . .

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपको भी लंच ठीक टाइम पर देना चाहिए था। आप जो कह रहे हैं कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था तो लोकतंत्र में वाकआऊट करना विपक्ष का अधिकार है और लंच करना भी अधिकार है। आपने लंच एक बजे नहीं किया तो डेढ़ बजे कर देते। हम इस प्रीजम्प्शन में बाहर गये थे। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उस दौरान दो महत्वपूर्ण डिमाण्ड्ज को पास करवा दो।

अध्यक्ष : आपने मुझसे डायरैक्ट बात पूछी है तो मैं इसका जवाब इस मान्य सदन में दूंगा। ऐसा है कि there are hundreds of instances where the proceedings of the House

has been taken up in lunch also and at night hours also and out of time also. In lunch hours also many sittings have been done by you. (Interruption) I tell you. I don't have to say anything in the proceedings of the House. The proceedings are initiated by the Members. I have to control them. As Speaker I have to do whatever the House wants. The House wanted that items should be taken up, I started it. If they don't want lunch, they can go on lunch also.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सही है कि लंच आवर में प्रोसीडिंग्ज होती है और रात के 12.00 बजे तक भी होती है, but it is always with the consent of the House i.e. Opposition and Ruling Party both. You never sought that approval. (---व्यवधान---) हाउस पूरा बैठा हुआ था।

अध्यक्ष : **श्री वर्मा द्वारा जारी**

29/03/2017/1215/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

अध्यक्षः आपको पूरा एक्सपीरियंस है, हाउस के बगैर तो कार्यवाही चल ही नहीं सकती है। जब हाउस कहेगा तभी चलाएंगे न।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः इसलिए आपको पहले पूछना चाहिए था, या तो पहले कहते कि आज लंच नहीं होगा और आज सारा दिन प्रोसीडिंग चलेगी। हम हाउस में बैठते।

अध्यक्षः हाउस ने कहा कि let us proceed with the proceedings. तो मैंने शुरू किया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः हाउस ने कहा one side of the House.

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा डिमाण्डज़ लगें, इसलिए हम लंच भी नहीं कर रहे हैं।

29/03/2017/1215/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

अध्यक्षः बिंदल साहब जी अब हो गया है। बात यह है कि लंच हो जाएगा ।

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त लोक महत्व का विषय है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। बिब्रेजिज़ कॉरपोरेशन बनाने के बाद एक बहुत गम्भीर मामला ध्यान में आया है और माननीय मुख्य मंत्री जी इसको संज्ञान में लें। बद्दी में बिब्रेजिज़ कॉरपोरेशन का डिपो हैं और किसी भी डिपो से बिना पेमेंट से शराब जारी नहीं हो सकती, परन्तु बद्दी के डिपो से राजनैतिक, जैसे मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर 4 करोड़ रूपये की शराब बिना पेमेंट लिए कुछ ठेकेदारों को जारी की गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ये बहुत गम्भीर विषय है। माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार इसकी तरफ गम्भीरता से ध्यान दें और ऐसे ही मामले अनेक स्थानों पर हो सकते हैं। इसलिए हम बार-बार कह रहे थे कि बिब्रेज़िज़ कॉरपोरेशन के माध्यम से बहुत-सारे मामले उठ रहे हैं। मुझे इतना ही आपके माध्यम से कहना था।

Speaker: We will take up this issue when it will be appropriate.

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा यह मेरे ध्यान में नहीं हैं। इन्होंने बताया है, इसकी जांच की जाएगी और देखा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

29/03/2017/1215/टी0सी0वी0-ए0जी0/3

<u>वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान</u>

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान की अनुदान मांगों को चर्चा एंव मतदान होगा। अब मैं मांग संख्याः 13 'सिंचाई जलापूर्ति एवं सफाई' को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 13 'सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई' के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम-3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 22,60,77,70,000/- रूपये (राजस्व) एवं 4,89,66,16,000/- (पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस मांग पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, बिक्रम सिंह, डॉ0 राजीव बिन्दल, रिखी राम कौंडल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर, गोविन्द सिंह ठाकुर, वीरेन्द्र कंवर, कृष्ण लाल ठाकुर और गोविन्द राम शर्मा की ओर से 6 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या इन्हें प्रस्तुत करना चाहेंगे या उनकी ओर से मैं प्रस्तुत हुआ समझूं ।

सदस्यगणः प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्षः मांग तथा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार से हैं:-

मांग संख्याः 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	**कटौती प्रस्ताव**	**मांग संख्याः**
	नीति का अननुमोदन	**13**

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई**
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

29/03/2017/1215/टी0सी0वी0-ए0जी0/3

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री विजय अग्निहोत्री,
श्री इन्द्र सिंह,
श्री बिक्रम सिंह,
डॉ0 राजीव बिन्दल,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
श्री कृष्ण लाल ठाकुर,
श्री गोविन्द राम शर्मा,

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।

2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।

3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

29/03/2017/1215/टी0सी0वी0-ए0जी0/4

अब मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं।

अब श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। एक बात मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कटौती प्रस्ताव पर 2 या 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बहुत ज्यादा समय तक बोलना अच्छा नहीं लगता । Please don't speak so long.

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी ।

29/03/2017/1220/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री महेन्द्र सिंह : सर, यह समय विपक्ष का ही है। इस पर हम जितना बोलना चाहें, हम बोल सकते हैं। हम कम बोलेंगे तो ज्यादा डिमांडज़ कवर होंगी और हम ज्यादा बोलेंगे तो कम डिमांडज़ कवर होंगी।

अध्यक्ष : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप बार-बार वही मत बोलते रहिएगा।

श्री महेन्द्र सिंहः सर, बार-बार कोई नहीं बोलेगा। हमारे अलग-अलग विषय होंगे।

अध्यक्ष : मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि जितना टाईम मैं आपको हाउस में बोलने के लिए देता हूं, मुझे याद नहीं है कि कभी किसी ने आपको इतना समय बोलन के लिए दिया हो।। take the opportunity to give every Hon'ble Member ample time to speak. यह आप भी देखिए कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा और बहुत ज्यादा लम्बा काम हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वैस्ट है। Shri Mahender Singh Ji, please continue.

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या : 13-'सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई' को ले करके जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से विभिन्न सम्माननीय सदस्यों ने दिए हुए

हैं। उसमें आई0पी0एच0 विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी कहते हैं कि 'जल ही जीवन है।' जल के बिना जीना बड़ा दुर्भर है। लगातार चार वर्षों से विपक्ष की तरफ से पूरे प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों से आई0पी0एच0 विभाग के बारे में अलग-अलग दिक्कतें सामने आ रही हैं। अनेकों ऐसी उठाऊ पेयजल परियोजनायें, बहाव पेयजल परियोजनायें, उठाऊ सिंचाई परियोजनायें, बाढ़ नियन्त्रण की परियोजनायें हैं। इन सभी परियोजनाओं में की जो दुर्गति इन साढ़े चार वर्षों के बीच में हुई है, इसका जिक्र लगातार इस हाउस में भी हुआ है। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को विशेषकर अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित दो परियोजनाओं का मेमोरैंडम दिया था। हमने चार्ज़शीट के माध्यम से उन परियोजनाओं के अलावा विभाग के अन्दर जो अन्य कार्यों में अनियमिततायें पाई जा रही हैं, उनके बारे में भी हमने बड़े विस्तार के

29/03/2017/1220/ एन0एस0/ए0एस0 /2

साथ जिक्र किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पेयजल परियोजनायें हैं, इन पेयजल परियोजनाओं में जहां उठाऊ पेयजल परियोजनायें, उठाऊ सिंचाई परियोजनायें, बहाव परियोजनायें थीं, उन सभी परियोजनाओं का काम विभाग पहले अपने तौर पर करता था। लेकिन वर्ष 2013 के उपरांत पूरे प्रदेश में आई0पी0एच0 विभाग का जो सिस्टम है, उसे बदल दिया गया है। आज आई0पी0एच0 विभाग एक ऐसी स्थिति में आ पहुंचा है कि आज विभाग को जो ऊपर का हिस्सा यानि top heavy Administration है, वह तो बिल्लकुल भरा हुआ है। लेकिन जहां से लोगों की सेवायें होनी हैं, जहां वाटरगार्ड लगने हैं, फीटर, असिस्टैंट फीटर, पम्प ऑपरेटर, असिस्टैंट पम्प ऑपरेटर लगने हैं, जहां से विभाग की अनेकों परियोजनाओं की एस्टिमेट डी0पी0आर्ज़0 बननी हैं, जो सर्वेयरज़ हैं, जे0ईज़0 हैं, ईवन एस0डी0ओज0 तक आज सारे-के-सारे स्थान लगभग 60 प्रतिशत खाली पड़े हुए हैं। इस प्रदेश में लगभग 12 लाख से भी ज्यादा बेरोज़गार नौजवान हैं। अगर आप विभागीय तौर पर भर्ती करते, विभाग

के सामने और माननीय मंत्री महोदया के सामने दो ऑप्शन्ज़ थीं। पहली ऑप्शन थी कि विभागीय भर्ती की जाती

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

29/03/2017/1225/RKS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह... जारी

लेकिन आपने विभागीय भर्ती को नज़रअंदाज कर दिया। आपने अधिकारियों के कहने पर आउटसोर्स का एक नया फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं को चलाने के लिए शुरू कर दिया है। हमने आप से अनेकों प्रश्न पूछे हैं और आपने अनेकों प्रश्नों का उत्तर दिया है। माननीय मंत्री जी ऐसी-ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं को बनाने की लागत कम है और उन परियोजनाओं को एक वर्ष तक चलाने की लागत ज्यादा है। आपने उन परियोजनाओं को एक वर्ष के लिए आउटसोर्स करके ठेकेदारों को दे दिया है। अब आप कहेंगे कि उन परियोजनाओं के नाम हमें बताइए। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये आंकड़े विपक्ष की तरफ से बनाये हुए नहीं हैं। ये आंकड़े हमें आपके द्वारा दिए गए विधान सभा प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न संख्याः 1391 और 1528 इस विधान सभा के बीच में लगे हैं। मैं सुन्नी क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। एक बरोटी-ब्राह्मणा पेयजल परियोजना 3.50 लाख रुपये में बनी और उस परियोजना को एक साल तक चलाने का ठेका आपने 3.82 लाख रुपये में दे दिया। सुन्नी क्षेत्र की ही दूसरी स्कीम कोठी-कोटली पेयजल परियोजना को बनाने में 2.25 लाख रुपये लगे और आपने उस स्कीम को चलाने के लिए एक साल के ठेके में 3.02 लाख रुपये में दे दिया। इसी सुन्नी क्षेत्र में गम्भर-भमौत स्कीम है। इस स्कीम को बनाने में 1.97 लाख रुपये लगे और आपने इस स्कीम को 3.20 लाख रुपये में एक साल के लिए आउटसोर्स कर दिया। इसी क्षेत्र में शिवघाटी-बाघा एक स्कीम है जोकि 3.34 लाख रुपये में बनी और आपने इसको 5.40 लाख रुपये में एक वर्ष के लिए चलाने को दे दिया। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का इलाका है। दूसरा,

बिलासपुर में एक स्कीम कलोह-छंझियार 3.42 लाख रुपये में बनी और आपने उसका ठेका 8.10 लाख रुपये में एक वर्ष तक चलाने के लिए दे दिया। सोलन में दयारसीघाट स्कीम 5.00 लाख रुपये में बनी और 11.50 लाख रुपये में उस स्कीम को चलाने का ठेका दे दिया गया। माननीय मंत्री जी हमें दुःख इस बात का होता है कि इस प्रदेश के राजस्व खजाने को किस प्रकार से लूटा जा रहा है? यह आपने

29/03/2017/1225/RKS/AS/2

एक नया सिस्टम शुरू किया है। आपने वर्ष 2013-14 में मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर उठाऊ पेयजल परियोजना टोरखोला को चलाने का ठेका 1.62 लाख रुपये में दिया। वर्ष 2014-15 में उसी स्कीम को चलाने का ठेका 20.25 लाख रुपये में दे दिया गया। यह क्या हो रहा है? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो यह विभाग द्वारा तैयार किए गए विधान सभा प्रश्नों के उत्तर में दर्शायी हुई राशि है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर एक ड्राउट प्रोन एरिया है। टिहरा, चौलथरा और रखोह के क्षेत्र में उठाऊ पेयजल परियोजना कांडापतन-अवाह देवी 10वें दिन चलती है। 20-20 दिन के बाद लोगों को पानी मिलता है। पहले तो डेढ़ महीने के बाद भी पानी मिला। पानी उठाने का काम आई.पी.एच. विभाग कर रहा है लेकिन पानी वितरण का कार्य आपने ठेके में दे दिया है। 20 दिन के बाद पानी आएगा और वह पानी इतनी मात्रा में नहीं दिया जाएगा कि उन 14 पंचायतों के पूरे क्षेत्र को मिल जाए। 14 पंचायतों में से लगभग 3 पंचायतों को पानी मिलेगा। लेकिन आपने वहां पर भी 6.10 लाख का ठेका दे दिया। 8.30 लाख का एक ठेका दे दिया।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

29.03.2017/1230/SLS-DC-1

श्री महेन्द्र सिंह ... जारी

10,58,400 रुपये के 3-3 महीने के ठेके दे दिए। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपके द्वारा प्रश्नों के दिए गए उत्तरों से ही यह सूचना दे रहा हूं; यह आंकड़ें मैं अपनी तरफ़ से नहीं दे रहा हूं। जब पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा तो आपने पानी बांटने का ठेका कैसे दे दिया? या तो आप पानी उठाने का ठेका देते और फिर उसी को वितरण का भी ठेका दे देते।

आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और आपका विभाग पानी देने में पूर्ण रूप से असफल हो रहा है। आपकी नीयत पर कोई प्रश्नचिन्ह हमारी ओर से नहीं है। लेकिन आप विभाग के मंत्री हैं। अगर विभाग में किसी भी प्रकार की कोई करप्शन होती है, हट-फिरकर बात हैड ऑफ द डिपार्टमैंट यानी मंत्री के ऊपर ही आती है।

आपने जिला चम्बा में डलहौजी की पानी की स्कीमें 28.05 लाख रुपये में, 27.90 लाख रुपये में और 55.95 लाख रुपये में दे दीं। यह केवल मात्र पानी उठाने के काम हैं, वितरण के नहीं हैं। पानी उठाने के लिए भी आई.पी.एच. विभाग की अपनी करोड़ों रुपये की मशीनरी वहां लगी है। बिजली का सारा ख़र्च भी आई.पी.एच. विभाग ही वहन कर रहा है। जिसने ठेका लिया है उसके ठहरने की व्यवस्था आपके पंपहाऊस में बने चौकीदार क्वार्टर्ज़ में हो रही है। आपने वहां पर करोड़ों रुपये की मशीनरी लगाई हुई है। हम आज दोबारा आपको सचेत करना चाहते हैं कि जब लास्ट में ठेकेदारों का ठेका पूरा होगा, वह उस करोड़ों रुपये की मशीनरी को वहां से उठाकर जाली खोखे वहां पर रखकर चले जाएंगे और फिर आप उनका क्या करेंगे?

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

आपने उन ठेकेदारों का कोई सिक्योरिटी अमाऊंट भी नहीं रखा है। अगर आपने उनका सिक्योरिटी अमाऊंट रखा होता तो आप कुछ कर पाते। आपकी एक-एक स्कीम करोड़ों रुपयों की है। लगवालती-बमसन स्कीम 65 करोड़ रुपये की स्कीम है।

29.03.2017/1230/SLS-DC-2

उस स्कीम का आपने ठेका दे दिया। लॉस्ट में ठेकेदार उस मशीनरी को उठा लेंगे। चण्डीगढ़ और दूसरी जगहों पर काफी खोखे मिलते हैं, वहां से उठाकर आपके वहां रख देंगे और कह देंगे कि जल गई, हम क्या करें। क्या विभाग के एग्रीमैंट्स में इस बारे में कोई क्लॉज है? मेरे पास एग्रीमैंट्स की कापी पड़ी है; यह कापियां आपने ही दी हैं। उसमें ऐसी कोई क्लॉज नहीं लगाई गई है कि उस ठेकेदार का इतना सिक्योरिटी अमाऊंट विभाग के पास जमा रहेगा और जब वह ठेका समाप्त होने पर विभाग को स्कीम हैंड ओवर करेगा, उस वक्त वह सब औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। मैं इसीलिए माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें बहुत-सी स्कीमों की सूचना तो दी ही नहीं गई है। अगर सारी सूचना को एकत्र किया जाए तो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 65-70 करोड़ रुपया आज इन स्कीमों को चलाने के लिए दिया जा रहा है। अगर इस राशि से आप हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गारों को रोज़गार देते तो कितना अच्छा होता। आपके विभाग ने एक और नया काम क्या किया? सैंट्रल विजिलैंस कमीशन की जो गाईडलाईंज हैं, उनमें साफ लिखा है कि ज्वायंट वैंचर किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, वह कौन-सा दवाब था, क्या वजह थी कि CVC की गाईडलाईंज को बदला गया कि ज्वायंट वैंचर नहीं होगा। ज्वायंट वैंचर न होने की वजह से क्या हो रहा है कि आई.पी.एच. विभाग द्वारा दो ही फर्मों को मनमाने रेट्स दिए जा रहे हैं और वह दोनों फर्में जाली हैं। एक ही फर्म ने अलग-अलग नामों से दो फर्में बना ली हैं क्योंकि वही फर्में क्वैलिफाई करती हैं। यह आऊट ऑफ स्टेट हैं। जो बड़े-बड़े काम हैं, जो स्कीमें 40, 50 या 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की हैं, उन स्कीमों में वही फर्में क्वैलिफाई हो रही हैं और उनको मनमाने दाम दिए जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि

जारी ...श्री गर्ग जी

29/03/2017/1235/RG/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह---क्रमागत

ये भारत सरकार की सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइड-लाईन्ज हैं, कोई प्रदेश सरकार की गाइड-लाईन्ज नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की छेड़खानी किसी भी दवाब में न करने के लिए विभाग को कहें। इसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हिमाचल प्रदेश के खजाने को हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पीछे कहा कि हम टैंक्ज की सफाई करेंगे। माननीय मंत्री महोदया, हम जितने भी सदस्य इस माननीय सदन में यहां बैठे हैं वे सब 68 विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे हरेक विधान सभा क्षेत्र में टैंक बने हुए हैं, लेकिन जो फिल्ट्रेशन बेड्ज, फिल्ट्रेशन गैलरीज या मैकेनिकल फिल्टर्ज हैं, उनका तो नामोनिशान नहीं है। वे बने हैं। एक बार फिल्टर बेड बन गया, उसमें रेत एवं कोयला डाल दिया, लेकिन उसके बाद उसको कोई नहीं देख रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि सीधे सोर्स से पानी ले रहे हैं और पानी की सीधी सप्लाई आगे दी जा रही है। आज अगर इस प्रदेश में पानी के कारण बीमारियां फैल रही हैं, तो उन बीमारियों के फैलने का सबसे बड़ा कारण गन्दा पानी है। हम इनके विभाग से यह जानना चाहते हैं कि वह जो बीस करोड़ रुपये पानी के टैंक्ज की सफाई के लिए लगाया, वे कौन-कौन से टैंक्ज हैं? अगर उनका ब्रेक अप ये दे दें, तो अच्छा होगा। क्योंकि यह प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और प्रदेश की जनता के साथ-साथ हम भी जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी कह रहे हैं कि आप फट्टे लटका रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और काम नहीं हो रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, हमारे काम तो हो ही नहीं रहे, लेकिन इनके सत्ता पक्ष के विधायक ऐसे आरोप लगा रहे हैं और उनके ये आरोप बिल्कुल सही हैं। सरकार का यह पांचवा साल है और पांचवे साल में भी अब लगभग मात्र तीन महीने बचे हैं। तीन महीनों के पश्चात हम सबको उस परीक्षा में जाकर बैठना है और जब परीक्षा में बैठेंगे, तो जो हमसे ऊपर परीक्षा लेने वाले हैं, वे हमसे पूछेंगे कि भई वह पैसा कहां गया जिनके लिए फट्टे लटकाए थे। वे फट्टे तो सिर्फ लटके हुए ही रह गए।

29/03/2017/1235/RG/DC/2

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिलान्यास हुए हैं या उस समय की उद्घाटन पट्टिकाएं लगी हुई हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि उनमें पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री या मंत्री के नाम अंकित हैं। इसलिए यह इनके लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। क्या कानून-व्यवस्था इस प्रदेश में खत्म हो गई है? क्या विभाग के अधिकारी/कर्मचारी फील्ड में नहीं रहते? अगर वे फील्ड में रहते हैं तो क्या वे इस बात को देख नहीं सकते कि यहां क्या हो रहा है या कौन सी पट्टिका टूटी है और अगर टूटी है, तो क्यों टूटी हुई है? आज अगर हमारी पट्टिकाएं टूट रही हैं, तो कल को इनकी पट्टिकाएं टूटेंगी। क्या यह बात अच्छी है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। एक वाटर सप्लाई की एन.सी.पी.सी. हैबीटेशन, झुंगी कन्सा की एक करोड़ रुपये से अधिक की स्कीम है। इसकी सारी-की-सारी लाईन ओपन बिछा दी और सारी लाईन वर्स्ट हो गई। इसके जो टैंक बने, सारे-के-सारे टैंक फट गए। मुझे जिला स्तर की एक समिति में जवाब मिला कि वह स्कीम चली हुई है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो उस स्कीम के चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमने अपनी चार्ज शीट में लिखा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो स्कीमें हैं जिनका मैंने जिक्र किया है और महामहिम राज्यपाल को हमने अपना ज्ञापन भी इस बारे में दिया है। लेकिन हमें बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि आज उस ज्ञापन को दिए हुए लगभग 8-9 महीने हो गए हैं और 8-9 महीनों से हमें उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। एक Executive Engineer जिसने उस घोटाले का अन्ज़ाम दिया, दो स्कीमों की राईजिंग मेन की सात करोड़ रुपये की सारी-की-सारी पाईप टूट चुकी है। दोनों स्कीमों की टैस्टिंग नहीं हुई। सात करोड़ रुपये की पाईप टूट गई, अब सात करोड़ रुपये की पाईप और लगेगी। तो यह 14 करोड़ रुपये का घोटाला है। यदि हम घोटालों की बात करते हैं, तो वहां से मंत्री महोदय कहते हैं कि आप

घोटालों की बात करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है। वहां सैक्रेट्री महोदय को बुलाया गया था। हमें ये बताएं और मेरा

29/03/2017/1235/RG/DC/3

प्रश्न इससे पहले भी इस बारे में लगा हुआ था कि उस पर क्या कार्रवाई की गई? अगर कार्रवाई की गई है, तो सदन को और हमें बताया जाए। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। वह स्कीम उस क्षेत्र को पानी देगी जो ड्रॉट-प्रोन एरिया मेरे विधान सभा और श्री इन्द्र सिंह जी के विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है। माननीय मंत्री जी, हमें बड़ा दुःख होता है कि ऐसी पाईपें जो पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के तहत पिछड़े क्षेत्र को दी जाती हैं। इसके लिए पैसा डिपॉजिट से आता है और इसके लिए उपायुक्त पैसा देते हैं। तो पिछड़े क्षेत्र के नाम से पाईपें आती हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2017/1240/MS/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी---------

लेकिन वे पाइपें जहां बैकवर्ड पंचायतें हैं, वहां नहीं लग रही हैं बल्कि लोगों के घरों में लग रही हैं। उनसे लोगों के घरों की सीढ़ियां बन रही हैं और घरों में रेलिंग लग रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने विभाग को अपनी चार्जशीट में अंकित किया हुआ है, क्या आज तक उस पर कोई जांच हुई? नहीं हो पा रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपके विभाग ने करोड़ों रुपयों की फीटिंग खरीदी है। यह मेरा प्रश्न लगा था जिसका आपने जवाब दिया है। मैं यह नहीं कहता कि आपने जवाब नहीं दिया है। आपने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है। मैंने जब उस पूरे जवाब को पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि पूरे जवाब में करोड़ों रुपयों की फीटिंग आई0पी0एच0 विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर के एस0ई0 और एक्सियन तक, उन्होंने खरीदी हुई हैं। आप सभी माननीय सदस्यों को पूछ लें कि हम जब

कहीं भी किसी को कहते हैं कि फलां का नलका लगना है तो वहां जो जे0ई0, एस0डी0ओ0 और एक्सियन हैं वे कहते हैं कि फिटिंग नहीं मिल रही है। यदि फिटिंग नहीं मिल रही है तो वह करोड़ों रुपयों की फिटिंग कहां चली गई? इसमें दो कम्पोनैंट हैं। आपने एक तरफ सारी स्कीमें आउटसोर्स कर दीं और दूसरी तरफ आप करोड़ों रुपयों की फिटिंग खरीद रहे हैं। तीसरी तरफ करोड़ों रुपयों की वह फिटिंग धरातल पर नहीं है और चौथी तरफ आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो फिर उस फिटिंग को खरीदने का क्या औचित्य बनता है? इन सारी बातों का अगर हम संज्ञान लेंगे तो मुझे लगता है कि यह हम सबके लिए अच्छी बात रहेगी।

इसके अलावा, माननीय मंत्री जी हमने अपनी विधायक प्राथमिकता की स्कीमें दी हुई हैं। उनको दिए हुए चार साल हो गए हैं और अब पांचवीं बार दी हैं। हम जो विपक्ष की तरफ के सदस्य हैं, हमें बताया जाए कि जो हमने प्रायोरिटीज दी हुई हैं उनमें से किसी एक की भी डी0पी0आर0 बनी है? यदि हां, तो बताइए कि फलां की बनी है? डी0पी0आर0 क्यों नहीं बनी, वे इसलिए नहीं बनी क्योंकि आपके पास जो निचला स्टाफ है जिसकी मैंने चर्चा की है, उसमें न आपके पास सर्वेयर हैं, न जे0ई0 हैं, न एस0डी0ओज0 हैं और न ही आपकी ड्रॉईंग ब्रांच में जो एच0डी0एम0 या ड्राफ्टसमैन होने चाहिए, वे हैं। जब वे

29/03/2017/1240/MS/AG/2

स्थान खाली पड़े हुए हैं तो आपकी डी0पी0आर्ज0 कैसे बनेंगी? मेरा आपसे निवेदन है,

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। अभी 12 माननीय सदस्य बाकी बोलने वाले हैं और फिर उसके बाद माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर देना है। फिर तो इसी मांग में सब रह जाएंगे। मुझे सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए उतना ही समय देना पड़ेगा जितना मैं आपको दूंगा, इसलिए कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय मंत्री जी, एक दिन यहां कृषि विभाग का एक प्रश्न लगा था कि ए0आई0बी0पी0 जिसमें की केन्द्र से हमें पैसा मिलता है, उसकी कितनी स्कीमें हिमाचल प्रदेश से भारत सरकार को गईं। यहां पर आज वे इंटेलीजैंट मंत्री नहीं हैं। उन इंटेलीजैंट

मंत्री ने कहा कि हमने सात स्कीमें भेजी हैं जिनका अमाउंट 1329.86 करोड़ रुपये बनता है। मैंने सैप्लीमैंट्री पूछी थी और उपाध्यक्ष जी आप भी उस समय यहां पर थे। वैसे प्रश्न कृषि मंत्री जी का था लेकिन उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री जी दे रहे थे। मैं उनके ऊपर कन्टैम्प्ट ऑफ हाऊस कर रहा हूं। मैंने पूछा था कि आपने जो सात स्कीमें भेजीं हैं क्या उन सबकी समस्त औपचारिकताएं पूरी की हुई थीं? उन्होंने कहा कि हमने सारी औपचारिकताएं पूरी की हुई थीं। माननीय मंत्री जी जो आपका पिछले कल का जवाब आया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो स्कीमें थीं जिनमें एक एल0आई0एस0 सचार खड्ड थी और दूसरी एल0आई0एस0 कौंशल झरेड़ामण्डप थी। एक स्कीम 122 करोड़ रुपये की थी और दूसरी 108 करोड़ रुपये की थी। उसमें आपने जवाब दिया है कि उसका जो एफ0सी0ए0 का केस है वह अभी तक डी0एफ0ओ0 जोगेन्द्र नगर के पास पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष जी, अब आप ही बताइए कि एक जिम्मेदार मंत्री जो अपने आपको कहता है कि मैं सबसे इंटेलीजैंट मंत्री हूं। मैं होने वाला मुख्य मंत्री हूं और होने वाला प्रधानमंत्री हूं। वे आज सदन में नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और साथ में यह भी कहा कि अगर किसी को मेरे जवाब में शंका हो तो वह कन्टैम्प्ट

29/03/2017/1240/MS/AG/3

ऑफ हाऊस करे। मैं उनके खिलाफ कन्टैम्प्ट ऑफ हाऊस कर रहा हूं कि उन्होंने इस सदन को गुमराह किया हुआ है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की उन दो स्कीमों का अभी तक एफ0सी0ए0 केस ही नहीं बना है। अभी तक वह डी0एफ0ओ0 के पास पड़ा हुआ है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए 22 मिनट से ऊपर का समय हो गया है।

श्री महेन्द्र सिंहः जब केस ही डी0एफ0ओ0 के पास पड़ा हुआ है तो माननीय मंत्री जी, एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिह्न आज हिमाचल प्रदेश के आई0पी0एच0 विभाग के ऊपर लग रहा है। जो पाइपें आप खरीद रहे हैं उनकी गुणवत्ता के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचन चिह्न है क्योंकि जैसे ही उन पाइपों को बैंड करते हैं वे वैसे ही टूट जाती हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि जो आप पाइपों की खरीद कर रहे हैं, चाहे वह पाइपों की खरीद है, फिटिंग की खरीद है या चाहे वह टैंकों की सफाई है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

29.03.2017/1245/जेके/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः----**जारी**------

चाहे वह आपके पास है और जिन स्कीमों को आपने आउटसोर्स किया हुआ है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज काफी हो गया है।

श्री महेन्द्र सिंहः उन सभी स्कीमों के ऊपर आप बड़े ध्यानपूर्वक से देखें और इस प्रदेश की जनता को स्वच्छ जल प्रदान करने की आप भरपूर कोशिश करें। सरकार पानी को उपलब्ध करवाने में नाकामयाब रही है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी आपका धन्यवाद।

29.03.2017/1245/जेके/एजी/2

उपाध्यक्षः अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-13 के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अति महत्वपूर्ण मांग है और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां दूर-दराज के गांवों के अन्दर जनता बसती है वहां पर पानी पहुंचाना और वह भी स्वच्छ पेयजल पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। मैं यहां पर आपके माध्यम से कुछ बातें सरकार के ध्यान में और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले लगभग तीन साल से हम लगातार विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं, कहीं पर 500 मीटर पाइप लगनी है, कहीं पर 200 मीटर और कहीं पर 100 मीटर पाइप लगनी है। कई योजनाएं स्वीकृत है और धन का प्रावधान है परन्तु तीन साल में एक ही उत्तर हमें अधिकारियों का मिला है कि पाइपें नहीं हैं। बीच में कोई समय

आया पाइपें आई और जो आपके चहेते थे और मैं आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस से सम्बन्धित जहां-जहां ठेकेदार या गांव थे वहां पर पाइपें दे दी गई बाकी लोगों को नहीं दी और आज के दिन में भी इस समय पाइपें उपलब्ध नहीं है। जब प्रदेश के विभाग में पाइपें और फिटिंग्ज उपलब्ध नहीं है तो ऐसे कैसे सरकार चल रही है और कैसे पेयजल की सप्लाई चल रही है? यह बहुत चिन्ता का विषय है। कहीं पर एक पाइप टूट गई है तो उसके कारण पूरे गांव की स्कीम बन्द पड़ी है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी विचार करने की आवश्यकता है लेकिन आप अब क्या करेंगे, कैसे विचार करेंगे, अब तो आपका जाने का समय आ गया है?

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दावे व चुनौती के साथ कहना चाहूंगा कि 90 प्रतिशत पम्प हाऊसिज के ऊपर जांच बिठाई जाए क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है? उनमें जो बिजली की तारें हैं वे नंगी हो करके लटकी रहती हैं। मकैनिक

29.03.2017/1245/जेके/एजी/3

जब आता है तो उन तारों को दूसरे से जोड़ता है और मोटर को चला देता है उसके कारण मोटरें और पम्प लगातार खराब होते हैं क्योंकि उसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है? शायद एक भी पम्प हाऊस ऐसा नहीं होगा जिसके अन्दर प्रॉपर सॉकिट लगा होगा। सीधे तौर पर उसमें तारें डाल कर यह सारा संचालन चल रहा है। जो पम्प हाऊसिज़ हैं, उनमें जो मोटरें और पम्प लगे हैं, उसके बारे में मैं आज आरोप लगा रहा हूं कि एक-एक मोटर और एक-एक पम्प हाऊस की एक साल में चार-चार बार रिपेयर होती है। एक कहावत है "आन्ने की बुढ़िया रूपया सिर मुंडाई का"। अगर वह एक लाख रूपए की मोटर है तो 5-5 लाख रूपया उसकी रिपेयर का बिल आपके विभाग में जमा हो चुका है। एक ही मिस्त्री है। उसी मिस्त्री के पास मोटर ठीक करने के लिए जाती है और ठीक हो करके आ जाती है। वह जाती है या नहीं जाती है यह भी पता नहीं है। मैंने पहले भी यह विषय उठाया था और आपके अधिकारियों से भी लगातार यह विषय उठाया है। मोटर और पम्पों की स्थिति बहुत

खराब है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मोटरें और पम्प में जब भी हम नई स्कीम चलाते हैं तो स्टैंड बाई मोटर और पम्प लगाते हैं और 90 परसेंट पम्प हाऊसिज की स्टैंड बाई मोटरें और पम्प वहां से उठा लिए गए हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

29.03.2017/1250/SS-DC/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

या तो विभाग उठाकर उनको दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेता है या फिर वह स्टॉक एंटरी में से कहीं-न-कहीं डिलीट हो जाती है। रिपेयर के लिए जाती है उसकी चिन्ता किसी को नहीं होती है क्योंकि लोअर स्टाफ, जैसा भाई महेन्द्र सिंह जी ने कहा, वह है नहीं और जिम्मेवारी की स्थिति बहुत खराब है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अनट्रीटिड पानी का पिलाया जाना एक बहुत गम्भीर मामला है। हमारे यहां नाहन विधान सभा क्षेत्र में सारी स्कीमें खड्डों के ऊपर हैं। खड्डों में जे0सी0बी0 से गड्ढा मारते हैं क्योंकि तीन महीने पानी नहीं होता और उस गड्ढे में पाइप डालते हैं, उससे कुएं में पानी डालते हैं और उसको डायरैक्टली लिफ्ट करते हैं। ट्रीटमैंट प्लांट लगभग किसी स्कीम का नहीं चल रहा और वह खड्ड, गड्ढे और नाले का पानी डायरैक्टली लोगों को पिलाया जा रहा है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। जबकि आपने अपने उत्तर में कहा कि हमारे और प्लांटस ठीक चल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज नाहन विधान सभा क्षेत्र के 55 परसैंट हैडपम्पस खराब पड़े हुए हैं और 150 चिट्ठियां हमने आपके विभाग को लिखी हैं। --(व्यवधान)-- मैडम, आपको थोड़े लिखनी हैं। एस0ई0, एक्सियन को लिखेंगे। हैंडपम्पस ठीक करने के लिए मंत्री जी को चिट्ठियां थोड़े लिखेंगे। वे हैंडपम्पस खराब पड़े हैं और लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। उस हैंडपम्प को भी ठीक करवाया जाता है। ठीक कराने का चार्ज लिया जाता है परन्तु हैंडपम्प ठीक नहीं होता। हैंडपम्प वैसा-का-वैसा रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हैंडपम्प में अगला विषय यह है कि हैंडपम्पस लगाने में बहुत ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। कांग्रेस का छुटभैया आपके एक्सियन के पास जाता है, उसकी टेबल पर मुक्का मारता है और वहां से हैंडपम्प लगाने के लिए ले जाता है। जहां पर पीने का पानी भी है, सप्लाई का पानी भी है, वहां हैंडपम्प लग जाता है। परन्तु जहां पर पीने का पानी नहीं है, सप्लाई का पानी नहीं है, वहां पर

29.03.2017/1250/SS-DC/2

हैंडपम्प नहीं लगता है। मैं ऐसे स्थानों की बाकायदा आपके माध्यम से चर्चा करना चाहूंगा। हमारी ग्राम पंचायतें चाकली, बनेठी, क्यारी, कोलोंवालाबुढ, वर्मापापड़ी, सुरला, देवकापुरला हैं। पिछले तीन सालों में इन ग्राम पंचायतों में एक भी हैंडपम्प नहीं लगा है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं कि यहां हैंडपम्प लगाओ तो जिस दिन हम यहां हैंडपम्प लगाने के लिए ऑर्डर करते हैं उसी दिन मेरे साथ के विधान सभा क्षेत्र में वही डिवीजन पड़ती है और साथ की विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का नेता अपने यहां पर हैंडपम्प ले जाता है। जो पूरे-के-पूरे डिवीजन की सैंक्शन है, वह केवल कांग्रेस के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में लगाया जाता है। उसके कारण जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हैंडपम्पों में मैं विशेष रूप से नोट करवाना चाहूंगा कि मेरी विधायक प्राथमिकता में 2012-13 और 2013-14 में 160 हैंडपम्पस एपीयर हो रहे हैं। हर बार हम प्लानिंग की मीटिंग में कहते हैं लेकिन वह डी0पी0आर आज तक सैंक्शन नहीं हुई है। अगर वह डी0पी0आर0 बनती है तो उससे विभाग को फायदा है और इलाको को भी पानी पीने को मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी 40 ट्यूबवैल की डी0पी0आर0 और पांवटा व नाहन डिवीजन की 20-20 डी0पी0आर0 आज तक नहीं बन रही है। उसके बनने से इलाकों को और आपके विभाग को लाभ मिलेगा क्योंकि पीने के सोर्सिज़ खत्म हो गए हैं। जो विधायक प्राथमिकता के ट्यूबवैल हैं वे आपकी स्कीमों को एनरजाईज़ करने के लिए हमने दे रखे हैं और उसका इस्तेमाल भी आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पाइपों की वैल्डिंग के बारे में बताना चाहूंगा।

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2017/1255/केएस/एएस/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

इसके बारे में गम्भीरता से काम करने की आवश्यकता है। अधिकारी भी सुन रहे होंगे। स्कीम की हालत यह है कि उसके कई पाट्र्स है। राइज़िग मेन है, डिस्ट्रिब्यूशन है, डिस्ट्रिब्यूशन टैंक और पम्प हाऊस हैं और बिजली का काम है। होता क्या है, कहीं पर राइज़िंग मेन डाल दी पांच साल हो गए राइजिंग मेन डली हुई है, डिस्ट्रिब्यूशन नहीं डली है, पम्प हाऊस का काम नहीं हुआ है। कहीं पम्प हाऊस का काम हो गया, राइज़िंग मेन का काम हो गया, डिस्ट्रिब्यूशन नहीं डली है। पांच-सात साल इस काम में लग जाते हैं, इतने में पाइपें सड़ जाती है। सारे अधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस दिन उसकी टैस्टिंग करते हैं, उस दिन वे पाइपें फट जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि चूड़न गांव से धार क्यारी और महीधार के लिए बहुत बड़ी स्कीम है, उसमें पाइपें लगा दी, वैल्डिंग कर दी। अब उसमें जब तीन साल के बाद पानी चलाया तो वह चार किलोमीटर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। पूरा विभाग लगातार लगा हुआ है और लगभग 8 करोड़ रु0 की स्कीम पूरी बर्बादी के कगार पर खड़ी है और जनता को पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह से मातर पंचायत में पांच साल पहले पानी के डिस्ट्रिब्यूशन के नलके लग गए परन्तु आज तक उसमें पानी नहीं डला। टैंक बन गए, टैंक फट गए, टैंक खत्म हो गए, स्कीम का 100 प्रतिशत पैसा युटिलाइज़ हो गया, कन्ज्यूम हो गया, विभाग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक और गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र सरकार में आदरणीय मोदी जी ने हमको 2014-15 व 2015-16 के लिए दी। उसके लिए

डी.पी.आर्ज़. भेजनी चाहिए थी। भाई महेन्द्र सिंह जी ने उसका थोड़ा सा ज़िक्र किया। पूरे विभाग को सरकार को पता नहीं है कि कौन सी डी.पी.आर्ज़. बनीं। जब मैंने खुद इस विधान सभा में रेज़ किया कि आज जिला परिषद की मीटिंग्ज़ में यह पारित होने जा रहा है तब जा कर वह मामला नीचे रुका। हमने मीटिंग्ज़ में पार्टिसिपेट किया। एम.एल.ए. प्रायोरिटी की सारी स्कीमों को बिना

29.03.2017/1255/केएस/एएस/2

इवैल्युएट किए उन स्कीमों के नाम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में डालकर केन्द्र सरकार को भेज दिए। अब यह चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही कि वह आप नाबार्ड को भेजेंगें, कृषि सिंचाई योजना को भेजेंगें या सैंट्रेल फंडिंग को भेजेंगें या स्टेट फंडिंग को भेजेंगें? हम उसमें एक डाइलेमा की स्थिति में है कि वे योजनाएं कौन सी योजना के माध्यम से हमें मिलेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सिंचाई योजनाओं का ज़िक्र करना चाहूंगा। बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जिनके कारण किसान की आर्थिकी को भारी धक्का लगा है। ग्राम पंचायत प्रदूणी में गिरी प्रोजैक्ट के टेल वाटर की उठाऊ सिंचाई योजना है। उस योजना में 500 मीटर तक स्टील का पाइप है और 500 मीटर के बाद एक किलोमीटर तक सीमेंट का पाइप है। वह स्टील का पाइप प्रैशर से पानी छोड़ता है आगे जो सीमेंट का पाइप है वह फट जाता है उससे लोगों के सारे खेत बर्बाद हो गए और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। (घण्टी) उपाध्यक्ष जी, सिर्फ पांच मिनट लूंगा। शहीद कुलविन्द्र सिंह उठाऊ सिंचाई योजना में भी नौ करोड़ रुपया खर्च हो गया। खेत को पानी नहीं मिल रहा है। रामपुर माजरी सिंचाई योजना, रामपुर भारापुर सिंचाई योजना, गिरी की जो राइट बैंक कैनाल है उसकी जो दुर्दशा है, इन तीनों योजनाओं की बहुत ही दुर्दशा है। हमने एम.एल.ए. प्रायोरिटी दे दी। एम.एल.ए. प्रायोरिटी की डी.पी.आर. बना कर ही उसको ठीक कर दो। आप किसी

तरह से नहीं कर सकते, उसकी डी.पी.आर. को सेंक्शन कर दें। अगर वह डी.पी.आर. सेंक्शन हो जाती है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2017/1300/AV/DC/1

डॉ0राजीव बिन्दल-------- जारी

तो कम-से-कम 15 हजार किसानों को इसमें रिपेयर और मेंटीनैंस में काम मिलेगा। उठाऊ सिंचाई योजना जंगलाभूड का पानी खेत तक जाता ही नहीं और सारा-का-सारा पानी सड़क पर आ जाता है जिसके कारण लोक निर्माण विभाग की पूरी सड़क खराब हो जाती है। उठाऊ सिंचाई योजना बर्मापापड़ी, उठाऊ सिंचाई योजना काला अम्ब, उठाऊ सिचाई योजना नागल-सकेती, उठाऊ सिंचाई योजना पालियो, उठाऊ सिंचाई योजना बिक्रमबाग, उठाऊ सिंचाई योजना देवनी-खादरी इत्यादि की स्थिति बदतर है। इनको हम रिपेयर/मेटींनैंस के लिए पिछले 3-4 सालों से बार-बार एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में दे रहे हैं। एम0एल0ए0 प्रायोरिटी का पैसा लेकर इनकी रिपयेर कर दें और इसको इसलिए एम0एल0ए0 प्रायोरिटी दी है ताकि हमारी स्कीमें चल सकें। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां पीने का पानी बिल्कुल नहीं है और लोग हैण्ड पम्प से लाल पानी निकाल-निकालकर पी रहे हैं। परंतु विभाग है कि उसके *कान पर जूं नहीं रेंगती*। ग्राम पंचायत चाकली, ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, ग्राम पंचायत प्रदूणी इत्यादि में ऐसी स्थिति है। मगर इस प्रकार की स्थितियां अच्छी नहीं है। हम बार-बार बजट बढ़ा रहे हैं, हमने बजट बढ़ा दिया मगर बजट बढ़ाने का लाभ नहीं हुआ। नाहन टाऊन हिमाचल का एक बहुत बड़ा नगर है और गिरि पेयजल योजना के बिना नाहन का सर्वाइवल मुश्किल है। वर्ष 2012 में आदरणीय धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया था और उसका काम शुरू हुआ। गिरि पेयजल योजना के लिए 52 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अगर इस साल के बजट में गिरि पेयजल योजना के लिए कम-से-कम 20 करोड़ रुपये की राशि रखी जायेगी तब जाकर हम उसकी राईजिंग

मेन कम्पलीट कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ने की दिशा में काम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता प्रदेश में रिपेयर / मेंटीनैंस कैसे चल रही है? एस0ई0/एक्सियन को रिपेयर/मेंटीनैंस के अंतर्गत बहुत कम पैसा जा रहा है बल्कि मैं कहूंगा कि न के बराबर जा रहा है। उस पैसे से तो बाढ़/बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं हो रही है। इसलिए मैं

29.3.2017/1300/AV/DC/2

कहना चाहता हूं कि वास्तव में जिन स्कीमों की रिपेयर होनी है उनकी स्थिति बहुत खराब है। हमने खड्डों और नालों की चेनैलाईजेशन के लिए एम0एल0ए0 प्रायोरिटी दे रखी है। उन पर क्रेट वॉल और डैम बनाकर के पेयजल और सिंचाई योजनाओं की स्ट्रैंथनिंग के लिए हमने एम0एल0ए0 प्रायोरिटी दे रखी है। जब तक इनकी डी0पी0आर0 बनकर नाबार्ड और सैंन्ट्रल एजैंसी से उनकी फंडिंग नहीं होती तब तक हम पेयजल और सिंचाई के कितने भी दावे करते रहें वह सारे-के-सारे खोखले रहेंगे। हर गर्मी और बरसात के मौसम में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि होती है। गर्मी शुरू हो गई है और हमारी स्कीमें अभी से सूख गई है। उसके लिए कन्टिन्जैंट प्लान करने की जरुरत है। विशेषतौर पर हम जिला सिरमौर के लिए आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि वहां के लिए प्रावधान करें क्योंकि सरकार पानी देने में पूरी तरह से विफल हुई है। इतना कहते हुए मैं इस कट मोशन का समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

Deputy Speaker: The House is adjourned for lunch till 2.00 p.m.

29/03/2017/1410/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई

अध्यक्षः अब श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजय अग्निहोत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 13 पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं इसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। "सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई" बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि जल ही जीवन है और जल के ऊपर ही हमारा आस्तित्व निर्भर करता है। प्राचीन समय में जल के बारे में रहीम जी ने भी कहा है कि

"रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन,
पानी बिन न उभरे, मोती मानस चुन।"

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से, पानी से बहुत सम्पन्न देश हैं, यहां बहुत-सी नदियां, छोटे-छोटे नाले और खड्डे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रदेश में जहां एक ओर पीने और सिंचाई के पानी की समस्या हैं, वहीं, हमारी सरकार इन समस्याओं को दूर करने में नाकाम रही है। हम बिना किसी दूरदर्शी सोच के साथ जहां अन्य विभागों में काम कर रहे हैं, वहीं, आईपी0एच0 विभाग भी बिना किसी दूरगामी सोच के साथ काम कर रहा हैं। हम लोगों को स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध करवाने में नाकाम हो रहे हैं और इसका ज्वलंत उदाहरण, जहां शिमला में पीलिया का रोग फैला, गन्दा पानी मिलने के कारण, वहीं हिमाचल प्रदेश के बहुत-से क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या इतनी विकट हो गई है कि गर्मियों में पानी मिलता ही नहीं हैं, और बरसात व सर्दियों में अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। हमारे पानी के सोर्सिज़ खत्म होते जा रहे हैं और उन पानी के संसाधनों को बचाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई रही है।

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी ।

29/03/2017/1415/ एन0एस0/ए0जी0 /1

श्री विजय अग्निहोत्री ----- जारी

जहां खड्डों में /नदियों में अवैध खनन के कारण, चाहे वहां अन्य किसी कारण से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है। हमने उसे दोबारा से रिचार्ज करने के

लिए और उसको बचाने के लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की चेष्टा नहीं की है। पिछले चार वर्षों से इस सदन के अंदर बहुत से माननीय सदस्यों और मैंने भी कई बार ऐसे प्रश्न उठाये हैं और ऐसी बातें रखी हैं, जिनको ठीक ढंग से हल करने से इस प्रदेश की जल आपूर्ति की समस्या का समाधान हो सके, उसके लिए कुछेक साधन जुटाए जा सकें, मेरे हिसाब से इसके लिए सरकार गम्भीर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ब्यास नदी है और दो बड़ी खड्डें मान और कुनाह हैं और वहां पर बहुत सी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं। इनमें लगातार पानी का स्तर गिरता जा रहा है और कई जगहों पर जहां 12 महीनें खड्डें बहती रहती थीं, गर्मियों के दिनों में सूख जाती हैं और उनमें पानी बहना बंद हो जाता है। मेरे देखते-देखते ही 12 महीनें वहां पर घराट चलते थे, लेकिन आज वहां पर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने कोई बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ काम करने की कोशिश नहीं की है। मैंने पिछले चार वर्षों से इन दो खड्डों को ठीक करने के लिए और इनको चैनलाईज करने के लिए तथा इनके ऊपर चैकडैम्ज़ बनाने के लिए हर बार सरकार को लिखा भी है, इनको प्रायोरिटी में भी डाला है एवं विधायक प्राथमिकता में भी डाला है। इसके लिए मैंने इस मान्य सदन में बार-बार बोला भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस और काम कर रही है। वहां अवैध खनन हो रहा है, जे0सी0बी0 के साथ खनन हो रहा है। वहां पर रेत-बजरी निकालने के चक्कर में पानी खत्म हो गया है और पानी प्रदूषित भी हो रहा है। लेकिन आज तक कोई भी कदम सरकार की तरफ से इस ओर नहीं उठाया गया है कि इसको कैसे ठीक किया जाए? बार-बार बोलने के पश्चात मान खड्ड के तटीयकरण के लिए लगभग 25 लाख रूपये की राशि सैंक्शन हुई है और उसकी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि पानी को बचाया जा सके तथा उसको चैनलाईज़ किया जा सके। लेकिन

29/03/2017/1415/ एन0एस0/ए0जी0 /2

पिछले दो वर्षों से आई0पी0एच0 विभाग, हमीरपुर के पास डिवीजन में पैसा पड़ा हुआ है और उन्होंने पुणे के जिस संस्था के साथ सर्वे और डी0पी0आर0 बनाने के लिए बात करनी

थी, वह आज तक नहीं हो पायी है। वहां पर छोटे-छोटे चैकडैम बना करके पानी को बचा कर रखने की आवश्यकता है ताकि वे दोबारा से रिचार्ज़ हो जाएं। हमारे प्रदेश में पानी के कई भण्डार हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र तो ऐसा है, जहां पानी की ज्यादा कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र में पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरे हिसाब से इसमें कहीं-न-कहीं हमारी सरकार और हमारे प्रशासन तथा मशीनरी की कोई-न -कोई कमी रही होगी। हमने देखा है कि राजस्थान जैसे राज्य जहां पानी की कमी होती है, अलवर में जहां तरूण वातसंग जैसे संस्थानों ने काम करके वहां की नदियों को हरा कर दिया है। लेकिन हमारी अच्छी-अच्छी नदियां जो अच्छा पानी दे रही हैं, उनको भी हम बचा पाने में असमर्थ हैं। इस विषय पर माननीय मंत्री महोदया सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए दूरगामी योजना बनाने की आवश्यकता है और इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। केवल हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमने क्या किया और कहां तक पहुंचे तथा क्या करेंगे?, समयबद्ध ये सारी स्कीमें होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जैसा कि लोग कहते हैं कि आने वाला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। पानी के लिए तब लड़ा जाएगा जब मानव बचेगा, कहीं पहले ही खत्म न हो जाए। जो हमारी छोटी-छोटी नदियां और नालें हैं, उनको चैनलाइज़ करके और उनके ऊपर चैकडैम्ज़ बना करके तथा दोबारा से रिचार्ज करने के लिए एवं उनको बचाने के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ-साथ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आई0पी0एच0 विभाग में जहां इन स्कीमों को चलाने के लिए मैन-पावर नहीं है, हम आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग भी इस ढंग से की जा रही है कि अपनों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए और एक साल के लिए जिस स्कीम को माननीय मंत्री महोदया आप आउटसोर्सिंग पर देंगें,

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

29/03/2017/1420/RKS/AS/1

श्री विजय अग्निहोत्री...जारी

वह एक साल के लिए जैस-तैसे चलाने की कोशिश करेगा। उसमें जो बहुत ज्यादा चेंजिज़ करने की आवश्यकता है, कोई मशीनरी ठीक करने को है तो वह जुगाड़ करके इसे चलाऐगा। इसके बदले में वह पैसे लेगा और चला जाएगा। इस तरह आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। पहले जो जलरक्षक लगाए गए थे उनको 25 रुपये दिन का देते थे। फिर बाद में यह 50 रुपये हुए। आज हम उनको 1700 या 1750 रुपये तक पहुंचा सके हैं। हमने उनको पिछले 10 वर्षों से एंगेज किया हुआ है। हम उनकी सेवाएं ले रहे हैं। यह उनकी पार्ट टाइम जॉब है परन्तु उनसे पूरा दिन काम लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में पूरे-का-पूरा सिस्टम केवल जलरक्षकों के सहारे चल रहा है। क्योंकि सरकार के पास पम्प ऑपरेटर्ज नहीं हैं। कोई फंक्शनल स्टाफ नहीं है। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है उसी के साथ उसकी पोस्ट भी खत्म हो जाती है। आप कोई नई रिक्रूटमैंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो जलरक्षक रखे हुए हैं उनका शोषण किया जा रहा है। हमें उनके लिए कोई पॉलिसी बनाकर मिनिमम वेजिज़ पर रखना चाहिए ताकि जो सेवाएं वे दे रहे हैं वह ठीक चल सकें। हम जलरक्षकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैनपावर की जिस क्षेत्र में आवश्यकता है उसके लिए हमारी प्रायोरटी फिक्स नहीं है। आज आई0पी0एच0 की स्कीम को चलाने के लिए, पम्प को चलाने के लिए अगर पम्प ऑपरेटर की आवश्यकता है, लाइनमैन की आवश्यकता है, फीटर की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को वही आदमी पूरा कर सकता है। उसकी जगह कोई डेप्यूटेशन नहीं कर सकता है। क्योंकि पानी हर रोज और समयानुसार देना पड़ता है जोकि हमें देना भी चाहिए। इसके लिए फंक्शनल स्टाफ की रिक्रूटमैंट होनी चाहिए परन्तु सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। दिन-प्रति-दिन मानव शक्ति कम होती जा रही है। इन विषयों के ऊपर भी सोचने की आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग से कहीं भला होने वाला नहीं है। हम आउटसोर्सिंग में 1 लाख या 3

लाख की स्कीम को 10 लाख रुपये में दे रहे हैं। उसी 10 लाख रुपये में हम नये इम्प्लॉयज रख सकते हैं, जिससे उनके घर भी चलेंगे और हमारी स्कीम्ज़ भी ठीक चलेंगी। लेकिन हम स्टॉप गैप अरेंजमैंट करते हुए लोगों को बहुत एसैंशियल चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमीरपुर में नदौन, विधान सभा चुनाव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्लेन है। वहां आदरणीय धूमल जी ने अपने कार्यकाल में मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट का शिलान्यास किया था। उसका टैंडर हो गया था। बाद में टैंडर कैंसल हो गया। इसके लिए दोबार से टैंडर किया गया। एक-डेढ़ साल तक उसको और डीले किया गया। लेकिन आज भी उस प्रोजैक्ट का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। उस इरिगेशन प्रोजैक्ट के माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 134 गांवों को पानी मिलेगा। लेकिन उस प्रोजैक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा है। कार्य डीले करने के कारण उस प्रोजैक्ट की कीमत बढ़ती गई। जो काम 100 करोड़ रुपये में पूरा होना था वह 156 करोड़ रुपये में पहुंच गया है। अगर काम की यही गति रही तो यह खर्चा और भी बढ़ जाएगा। इसे तेज गति से करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोला-मंझयार-सेरा, फेस-1, फेस-2 और फेस-3 का काम चल रहा है। यह काम वर्ष 2002 से चल रहा है। वर्ष 2002 से आज तक उसमें करोड़ों रुपये खर्च हो चुका है। लेकिन एक भी पानी की बूंद किसी के खेत में नहीं पहुंची है। क्या हमने कभी बैठकर इसकी संवीक्षा की?

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप कट मोशन पर बोलिए इस तहर आप एक्सप्लेन करते रहे तो आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं।

श्री विजय अग्निहोत्रीः सर, मैं कट मोशन पर ही बोल रहा हूं। सरकार ने मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट के लिए एक पैसा भी नहीं रखा है।

Speaker: You can't speak for such a long time. You can briefly explain it.

29/03/2017/1420/RKS/AS/3

श्री विजय अग्निहोत्रीः सर, मैं आईपी.एच. पर ही बोल रहा हूं। मुझे पता है कि बोल कर कुछ होने वाला नहीं है परन्तु अपना मना हलका तो कर लें। मैं पिछले चार वर्षों से इस माननीय सदन में यही देख रहा हूं कि यहां मुख्य मंत्री, मंत्रियो से आश्वासन मिलते हैं उनमें कितनी ऑथैंटिसिटी से काम हो पाता है। यह मुझे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

29.03.2017/1425/SLS-AS-1

श्री विजय अग्निहोत्री... जारी

क्योंकि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र और प्रदेश के लोगों की समस्याएं यहां उठाऊं। प्रश्न पैदा करना मुझे ज्यादा ज़रूरी लगता है। उसका हल आज नहीं तो कल निकलेगा ही। ये नहीं निकालेंगे तो हम निकालेंगे। जो सिंचाई योजना 2002 से चली है, उसका मैं ज़िक्र ही न करूं कि वह काम नहीं कर रही है तो कैसे काम चलेगा। वहां एक वॉटर सप्लाई स्कीम Augmentation of resources of various Water Supply Schemes from Beas River है। वह 35.00 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली है। पिछले 6 सालों से उसका काम चल रहा है लेकिन पिछले 2 सालों से उस पर कोई काम नहीं हुआ। वह काम कब पूरा होगा?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का विभाग हैंड पंप भी लगाता है। हमारे वहां इनके एक बहुत चहेते लीडर हैं। कई लोग उनको फैमिली मैंबर बोलते हैं। वह दत्तक पुत्र की तरह कहते हैं कि यह विभाग मेरा ही है। मैं चाहता हूं कि जो हैंड पंप वहां पर पिछले 3-4 सालों

में लगे हैं, उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। कई जगह पर 20-20 मीटर की दूर पर हैंड पंप लगे हैं। विधायक जहां के लिए लिखकर देता है उसके अनुसार वहां पर डिमांड बेस्ड कोई काम नहीं हुआ। मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न उठाया था कि मैंने वहां पर हैंड पंप लगाने के लिए विधायक निधि से पैसा दिया। उन्होंने मुझे यह कहकर विधायक निधि वापिस कर दी कि हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है। दिनांक 06.12.2016 का आपके विभाग का पत्र है जिसमें लिखा है "In this connection it is intimated that a sum of Rs. 3.80 Lakhs is hereby return to your office which is unutilized due to non-availability of drilling machines". विभाग ने इस तरह मेरी विधायक निधि वापिस कर दी।...(व्यवधान)... मुझे पता है कि बोलकर क्या होगा। फिर उसी दिन की अख़बार में लिखा है कि 'माननीयों के अहं की बलि चढ़ा हैंड पंप।' इस अख़बार में उस ड्रिलिंग मशीन की फोटो भी है जो उस गांव में स्पॉट पर खड़ी है जहां के लिए मैंने हैंड पंप हेतु पैसा दिया था। फिर कहते हैं कि हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे विधायक निधि तो इस बार भी मिल गई, आप उसको काट

29.03.2017/1425/SLS-AS-2

सकते हैं तो काट लो। अगर नहीं काट सकते तो मैं जो हैंड पंप लगाना चाहता हूं, मैं इसके लिए कहां जाऊं? मैं किसी गांव में पाईप चेंज करवाना चाहता हूं, उसके लिए मैं कहा जाऊं? इसी लैटर के माध्यम से इन्होंने मुझे दो हैड्ज की वह निधि भी वापिस की जिससे मैंने विभाग को 2 हैंड पंप्स में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पैसा दिया था। क्या आप हैंड पंप में सबमर्सिबल पंप भी नहीं लगाने देंगे? आप या तो मुझे व्यवस्था बता दीजिए कि मैं कैसे कर सकता हूं या फिर मेरे पास वहां का विभागीय चार्ज दे दें ताकि मैं स्वयं ही हैंड पंप लगाता रहूं। इस बजट बुक और बाकी चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। आप जिस ढंग से विभाग को चला रहे हैं उससे हम हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध पानी का भी सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मांग के ऊपर ही बोला जाए। मांग तो पूरी होने वाली नहीं है। इस विभाग में जहां मैन पॉवर में कमी आई है, वहीं काम करने की इच्छाशक्ति में भी कमी आई है। जो स्कीमें कई वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद नदौन विधान सभा क्षेत्र और इस प्रदेश में पानी के लिए आज की तारीख में भी हा-हाकार मची हुई है। यहां तक कि रात को मैट्रोपोल में भी पानी नहीं था। आज कि सबसे बड़ी हैडलाइन है कि 'टैंकरों के साथ शिमला में हुई पेयजल की सप्लाई।'

जारी ...श्री गर्ग जी

29/03/2017/1430/RG/DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री---क्रमागत

कल को गर्मियों में क्या हाल होने वाला है? पिछले चार सालों से यह चल रहा है। आप कह रहे हैं कि इस बार के बजट अनुमान एवं इस बार की मांग पर आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यदि पुरानी व्यथा नहीं कहेंगे, तो कैसे रहेंगे? पिछले एक दशक से नदौन शहर की सीवरेज का काम चल रहा है और उस सीवरेज से एक भी कनैक्शन पिछले 10-12 सालों में नहीं हुआ है। उसकी अद्यतन स्थिति क्या है और उसको ये कब तक पूरा करेंगे? उसके लिए क्या प्रावधान इन्होंने रखे हैं? इसके अतिरिक्त एक और मजेदार बात यह है कि वहां कहीं-कहीं सीवरेज की लाईन में ही वाटर सप्लाई की लाईन भी सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने बिछाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इनके विभाग ने बहुत खरीददारी की है, लेकिन कहीं भी जाओ, तो विभाग के पास बदलने के लिए पाइप ही नहीं है। कई जगहों पर बीस-बीस सालों से पाइपें पड़ी हैं, वे सड़ गई हैं और गल गई हैं और उनमें गन्दा पानी घुस जाता है। कई बार तो कीड़े घुस जाते हैं और नलके से कीड़ा निकलता है। विभाग ने इस सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्या किया है? पिछले पांच सालों में नदौन विधान सभा क्षेत्र की कितनी ऐसी स्कीमों की डी.पी.आर्ज. विभाग ने बनाकर तैयार की हैं जिनके ऊपर काम शुरू हो गया हो या जिनकी अप्रूवल हो गई हो? इसलिए यह पूरे क्षेत्र की

समस्या है। यह सरकार सिर्फ ऐसे ही चल रही है। कल हम लोग उठकर चले गए, तो बिना चर्चा के ही दो मांगों को पास कर दिया गया। यदि कल ही सारी मांगे पढ़ देते, तो अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। इस सरकार ने इस प्रदेश की जलापूर्ति, सफाई और सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुछ नहीं रखा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

29/03/2017/1430/RG/DC/2

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-13 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की मुख्य जिम्मेवारी जनता को स्वच्छ और सही मात्रा में पानी देने की है और साथ ही इनकी किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की भी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं समझा हूं कि जिस ढंग से प्रदेश में पीने-के-पानी की या सिंचाई की पानी की आपूर्ति हो रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि विभाग अपनी दोनों जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में पूर्णतया असफल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नीति नहीं है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो it is a case of total system failure. विभाग की इस नाकामी की वजह से हम सब विधायकों को जो यहां बैठे हैं, जनता के बीच में जाकर खरी-खोटी सुननी पड़ती है। साथ में पानी न होने के कारण या कम मात्रा में पानी मिलने के लिए समाज के अंदर भी बहुत ज्यादा टैंशन होता है और समाज में लड़ाई-झगड़े होते हैं। तकरीबन हर गांव में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पानी की कमी नहीं है। यह कमी स्वतः विभाग द्वारा उत्पन्न की है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि ठीक नहीं है। तो यह मैं समझता हूं कि मूलतः इन सबके कारण सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। हर स्कीम की 15-20 साल के बाद री-

मॉडलिंग होनी चाहिए। स्कीम की री-मॉडलिंग होगी, तो पानी ठीक मिलेगा क्योंकि जब कोई स्कीम बनती है, तो उस समय सौ नलके होंगे और 15 साल के बाद 500 नलके हो जाएंगे और अगर पानी की पाइपें वही होंगी, तो झगड़े और टेंशन तो होगा ही। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि री-मॉडलिंग का होना बहुत जरूरी है।

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2017/1435/MS/DC/1

श्री इन्द्र सिंह जारी---------

अध्यक्ष महोदय, पानी पम्पिंग द्वारा मेन टैंक में डाला जाता है। लेकिन जब वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो लगभग 25 प्रतिशत पानी लीक होकर के वेस्टआउट हो जाता है क्योंकि आपकी जितनी भी पानी की पाइपें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हैं वे तकरीबन जंग लगी हुई हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है। यदि हम इस बारे में विभाग को कहते हैं कि फलां लाइन लीक कर रही है इसलिए इसकी कुछ पाइपें बदल दो तो विभाग जवाब देता है कि आप हमें पाइपें दे दो फिर हम बदल देंगे। I don't know how this system is working. माननीय मंत्री जी सुन रही हैं लेकिन जो सच्चाई है उसको आपके सामने पेश करना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए मंत्री जी, आप जरूर इस दिशा में कदम उठाएं।

महेन्द्र सिंह जी ने सही कहा कि जो आपकी पम्पिंग मशीनरीज हैं; the cumulative cost of repair of any pump is more than the original cost itself. तो उनकी कोई चैकिंग या मॉनिटरिंग नहीं है। It is left to the SDOs and Executive Engineers. It is open case of corruption , क्योंकि पता नहीं वह रिपेयर होता भी है या नहीं। किसको क्या पता है। साथ में कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रक्चर जो है, it has to be pyramidal structure. आपका टॉप हैवी है और बेस में आपके पास ग्राउंड स्टाफ है ही नहीं। जब ग्राउंड स्टाफ नहीं है तो काम कौन करेगा? व्हील कौन खोलेगा, पानी कौन देगा या कहीं

से पाइप लीक हो रही है तो उसको ठीक कौन करेगा? You have no answer to that. मैं ऐसा समझता हूं। आपके पास पम्प ऑपरेटर, जे0ई0, सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन नहीं हैं तथा ऊपर से मुख्य मंत्री महोदय नये-नये डिवीजन और सब-डिवीजन्ज खोले जा रहे हैं। There is no linkage at all with the reality. इसलिए और साथ में मेनपावर के अभाव में यह विभाग आगे के लिए काम कैसे करेगा, यह सोचने का विषय है। इसलिए आपने बड़ा सॉफ्ट ऑप्शन ऐप्लाई कर लिया है कि हम तो चला नहीं सकते इसलिए अनुबन्ध पर दे देते हैं और अनुबन्ध पर देने के लिए आपका कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आपने सारा एक्सियन पर छोड़ दिया है। एक्सियन बन्दे को बुला लेता है और टैण्डर कागज़ पर होते रहते हैं और किसी बन्दे को दे देते हैं कि लो, तुम एक-दो साल के लिए इस पम्पिंग स्टेशन को चला लो। आपने कभी सोचा कि साल-दो साल के बाद जब वह

चला जाएगा तो सारी मशीनरीज भी उठाकर ले जा सकता है? क्योंकि you have no control, you have no check on him. It is a open case of corruption. You are inviting corruption into the system. आप कृपा करके इसको बदलिए। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।

आपने सिंचाई की 100 के लगभग स्कीमें प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर दे दीं और छः-छः महीने के लिए दी है। स्कीमें कॉन्ट्रैक्ट पर उस एरिया में दे दी जहां छः महीने बर्फ पड़ा रहता है। आप उस पैसे को ऐसे ही किसी की जेब में डाल दो। Why to waste paper like this. इसलिए इस विभाग को भगवान ही बचा सकता है और मुझे लगता है कि भगवान भी नहीं बचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है।

मैं थोड़ी सी बात अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में 46 उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं। इनमें बहुत सी पुरानी भी हैं। स्कीमों की रि-मॉडलिंग नहीं हुई है। जगह-जगह से डिस्ट्रीब्यूशन पाइपें टूटी हुई हैं। जो उनमें होल बने हुए हैं उसमें हम बांस के टुकड़े लगाकर उनको प्लग करते हैं। हम एक्सियन को बोलते हैं कि इसे चेंज करो तो वे कहते हैं कि एस0ई0 साहब को बोलो और एस0ई0 बोलते हैं कि पैसे नहीं है और पाइपें नहीं हैं। डेढ़-दो सालों से तो डिवीजन्ज में हाफ इंच की पाइपें ही नहीं मिली हैं। यह

विभाग कैसे काम कर रहा है, मुझे बताइए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम विपक्ष के लोग यहां बैठे हैं, हमारे लिए पाइपें मना है और दूसरी तरफ वालों के लिए पाइपों के ट्रकों-के-ट्रक आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पैसा तो आपने खर्चना ही है। इसलिए इस तरफ भी देखने की जरूरत है।

इसी तरह से ग्रेविटी की मेरे पास 96 स्कीमें हैं। Maximum schemes are without filter, water is being supplied directly from the source. आप कितना अन्याय उन लोगों के साथ कर रहे हैं। यह इक्कसवीं सदी चल रही है और आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने किसलिए एक्सियन, एस0डी0ओ0 और जे0ई0 बिठाए हैं क्योंकि वे स्कीमों की चैकिंग पर कहीं जाते ही नहीं हैं। स्कीमों को कोई चैक ही नहीं करता है जबकि उनको स्पॉट पर जाकर चैक करना चाहिए। कम-से-कम दिन में एक स्कीम भी चैक करेंगे तो महीने में कितनी स्कीमें चैक कर सकते हैं लेकिन वे दफ्तरों में बैठे रहते हैं। हम

29/03/2017/1435/MS/DC/3

विपक्ष के लोग हैं इसलिए यदि हम उनको कहते हैं तो वे हमारे कहने से कहीं जाते ही नहीं हैं क्योंकि आपने उनके ऊपर एक चौधरी बिठाकर रखा है जिसको सलाहकार बोलते हैं। जहां वह जाता है उसके साथ सभी अधिकारी जाते हैं। काम कौन करेगा?

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

29.03.2017/1440/जेके/एजी/1

श्री इन्द्र सिंह ठाकुरः------**जारी**--------

इसलिए सारे सिस्टम को रीवैम्प करने की सख्त जरूरत है,मैं ऐसा समझता हूं। मैं, प्रो0 धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने समय में मुझे तीन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्ज कांडा-पत्तन दी थी। एक 40 करोड़ की, एक 29 करोड़ की और एक 15 करोड़ की

थी। जो 29 करोड़ की स्कीम थी उसमें मुझे आपने लिखित में बताया कि अक्तूबर 2014 में यह कम्पलीट हो जाएगी। आज 2017 चला हुआ है that scheme is not yet completed. आप गलत ज़वाब क्यों देते हो? आप लिखित में देते हो, विधान सभा के अन्दर देते हो। There is something wrong. Kindly correct it. जो दो स्कीमें हैं उनके बारे में श्री महेन्द्र सिंह जी ने ठीक बताया। आपने 15-15 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन उन दोनों स्कीमों की खड्ड में डाल दी। यह कौन इंजीनियर है जो इसको एक्सैप्ट कर सकता है? ठेकेदार तो सॉफ्ट ऑप्शन लेगा लेकिन यह देखना विभाग की डियूटी बनती है कि वह काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक 40 करोड़ रूपए की स्कीम है, 15 करोड़ रूपए की स्कीम है और आपने खड्ड में पाइपें बिछा दी, जो कि राइजिंग मेन की कॉस्टली पाइपें हैं। ऊपर से फ्लड आई और सारी बह गई। उन दोनों स्कीमों पर 25-25 करोड़ रूपया विभाग खर्च कर चुका है। वे स्कीमें डिफंक्ट हो रही हैं। कैसे वे स्कीमें रिवाइव होंगी यह पता नहीं है? इसलिए इस विभाग को जागने की बड़ी सख्त जरूरत है ऐसा मैं समझता हूं। जो 40 करोड़ रूपए की स्कीम है उसमें आप 24 करोड़ 50 लाख रूपया खर्च कर चुके हैं। अब वह सारे का सारा वेस्ट हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी मैन पॉवर की मेरे डिविजन में बहुत कमी है। मैडम कम से कम 100 जल रक्षक चाहिए, अगर आपने सारी स्कीमें मेरे चुनाव क्षेत्र में चलानी है। जल रक्षक के लिए पंचायतों से रेज़ोलूशन जाते हैं और एक्सियन उनमें बैठ जाता है क्योंकि उसको सरकार आगे से परमिशन ही नहीं देती है कि जल रक्षक रख दो। जल रक्षक को आप क्या देते हैं? आप 1750 रूपए देते हैं और 24 घण्टे उससे काम लेते हैं। जहां तक एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की बात है मेरे ख्याल में एम0एल0ए0 प्रायोरिटी लगनी ही नहीं चाहिए। Don't waste our time and your time क्योंकि न तो हमारी सड़कों की

29.03.2017/1440/जेके/एजी/2

कोई डी0पी0आर0 बनती है और न ही कोई अन्य बनती है। आई0पी0एच0 विभाग में पांच सालों में एक भी डी0पी0आर0 मेरी स्कीमों की नहीं बनी। हम किसलिए लिखते हैं? हम कूहलों के लिए बोलते हैं, कूहलों की प्रायोरिटी दे देंगे कि उनको बनाओ। आपका विभाग

कहता है कि इनफिजिबल है। उस एक्सिअन को पता ही नहीं है कि हमारे पास सोर्स ऑफ वॉटर कहां पर मिलेगा? दो महीने गर्मियों में सूखा रहता है। हमारे बुजुर्गों ने सिज़नल कूहलें बनाई है उनको हम रिवाईव करना चाहते हैं। सिज़नल कूहलों का मतलब है कि हमें धान की खेती के लिए पानी चाहिए बरसात में वह पानी खड्डों में होता है। हमें नवम्बर-दिसम्बर में गन्दम बीजने के लिए पानी चाहिए लेकिन वह पानी खड्डों में होता है। उसको इनफिजिबल करने का क्या मतलब है? एक मैंने जल संग्रहण के लिए एम0एल0ए0 प्रायोरिटी लिखी। मैं पर्सनली ऑन दी स्पॉट गया। मैंने उनको सब कुछ दिखाया लेकिन उसको इनफिजिबल कर दिया। ये कहते हैं कि it is not inaccessible. बन्दा चाँद में पहुंच गया लेकिन वह खड्ड में नहीं पहुंच सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि विभाग का क्या रिस्पाँस है? हम उसको क्या करें? ये सब कुछ गलत है इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप विभाग को थोड़ा सा अपने शिकंजे से कसिए। मेरी रेवन्यू रिकॉर्ड में 52 कूहलें हैं। 52 चैनल्ज बुजुर्गों ने बनाई है। जब तक आई0पी0एच0 ने नहीं ली थी सारी की सारी काम करती थी। जैसे-जैसे विभाग लेता रहा वे सब की सब कन्डम हो गई केवल 17 चलती है वह भी पार्शयली चलती है। अब हम इस विभाग को क्या बोलें? It is a very pathetic state of affairs. जितनी भी लिफ्ट इरिगेशन की स्कीमें पुरानी थी वे सब की सब खराब है या फिर बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मैं फिर से धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं। मुझे उन्होंने तीन स्कीमें लिफ्ट इरिगेशन की दी। वह 90-90 लाख रूपए की थी। बिल्कुल काम ठीक चल रहा था। सरकार बदली और काम स्लो हो गया। पता नहीं कहां पर डाईवर्ट कर दिया? इसके लिए भी आपको देखना चाहिए कि वह काम वहां पर चले जैसा पहले चल रहा था। मैं यहां पर माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहता हूं कि सरकार को

29.03.2017/1440/जेके/एजी/3

सोचना पड़ेगा should you give priority to the old system of water channels? जो वॉटर चैनल्ज यानि कूहलें होती थी। You want to give priority to that or you want to

give priority to lift irrigation schemes. I think lift irrigation schemes in the long run will not serve your purpose क्योंकि उसमें डिफैक्ट आते रहते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

29.03.2017/1445/SS-AG/1

श्री इन्द्र सिंह क्रमागतः

लेकिन जो फ्लो इरिगेशन की स्कीमें हमारे बुजुर्गों की थीं, वे खराब पड़ी हैं और लोगों ने नेगलैक्ट कर दी हैं we have to revive those schemes. इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में हम सीर खड्ड के चैनेलाइजेशन की बात करते-करते थक चुके हैं और it is a really pathetic state of affairs, Madam. अक्तूबर, 2012 में इसकी AA&ES 62 करोड़ रुपये की मंजूर हुई। हमने शिलान्यास किया। सरकार बदली लेकिन आप पांच सालों में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उस खड्ड ने कितना नुकसान कर दिया, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर मैंने आपसे पूछा कि कम-से-कम जो डेंजरस प्वाइंटस हैं, you kindly identify those things. मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि विभाग ने उनको आइडेंटीफाई कर दिया। उसके लिए आपने 2015-16 में 4 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट रखा। कमाल है! कुछ भी नहीं हुआ। वह 4 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट कहां गया? वह बजट किस तरफ डाइवर्ट हो गया? I request you to kindly look into this case. कम-से-कम आने वाली बरसात से पहले जो डेंजरस प्वाइंट्स हैं वहां पर आप कुछ-न-कुछ करके दीजिये। मैं यह आपसे रिक्वैस्ट करता हूं।

हमारे सरकाघाट टाऊन में सीवरेज की समस्या है। 1995 में वह काम शुरू हुआ, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं लेकिन यह तो अगली शताब्दी आ गई लेकिन वह काम चला ही नहीं है। उस समय उसकी कॉस्ट 5 करोड़ 61 लाख 57 हज़ार थी। जब

उसको दूसरी बार दोहराया गया, उसका 2011 में रिसर्वे हुआ तो 16 करोड़ पहुंच गया। लेकिन अभी तक भी वह स्कीम कम्प्लीट नहीं हुई है। उसके "A", "B", "C" तीन जोन हैं। "A" and "B" are complete. "C" is not yet complete. Kindly see that the thing is taken care of. ये जो हैंडपम्पस की बात यहां चली। हैंडपम्पस कौन लगाता है? जहां पर पब्लिक मांग है, जहां रिक्वायरमैंट हो, जहां पब्लिक द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जोकि फील्ड में रहते हैं और देखते हैं कि यहां जैनुअन रिक्वायरमैंट है वहां हैंडपम्प लगना चाहिए। लेकिन

29.03.2017/1445/SS-AG/2

उनकी बात मानी नहीं जाती। जो आपने चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकार बनाए हैं आप उनकी बातें मानते हैं। अभी 2015-16 में मेरे चुनाव क्षेत्र में 22 हैंडपम्पस लगे। जो 15 पंचायतें हैं उनमें एक हैंडपम्प लगा और एक गांव में तीन हैंडपम्पस लग गए। जिस गांव ने चौधरी साहब को वोट दिये थे, वहां तो तीन हैंडपम्पस लग गए। लेकिन जिन पंचायतों ने वोट नहीं दिये थे वहां एक हैंडपम्प लगा। वह भी उनके अपने आदमी के घर में लगा। What is this? इससे आपका विभाग अनावश्यक रूप से बदनाम हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था और अखबार में आया था कि 100 हैंडपम्पस विधायक लोग लगायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के मुताबिक हमारे खाते में यानी विधायक लोग 100 हैंडपम्पस लगायेंगे। ठीक है, यह खबर है। मैं अखबार को कोट कर रहा हूं। अब मैडम जो 100 हैंडपम्पस की बात हुई, जो हमारा सलाहकार है उसने तो 200 पहले ही बांट दिये हैं। तो मैं क्या लगाऊंगा विधायकों के? यह बात आपको सोचनी पड़ेगी। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमको लोगों ने वोट दिये हैं क्योंकि हमारी ऑनैस्टी पर लोगों को विश्वास है। हम सही काम करते हैं, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। जब रिक्वायरमैंट है तो हम पार्टी इत्यादि नहीं देखते। लेकिन हमारा कहना नहीं मानते हैं। इसलिए आप विभाग वालों को यह बात ज़रूर कहिये कि कम-से-कम जहां जैनुअन रिक्वायरमैंट है और जहां हाइड्रोलोजिस्ट बोलता है वहां हैंडपम्पस लगाईये। लेकिन जहां घिसे-पिटे नेता लोग बोलते हैं वहां हैंडपम्प न लगाया जाए और जहां हाइड्रोलोजिस्ट बोलता है कि यहां पानी निकलेगा, वहां हैंडपम्पस लगायें। ये डायरैक्शन्ज़ आपकी तरफ से जानी चाहिएं। जो पम्प हाउसिज़ हैं, आफरऑल पम्प हाउसिज़ में एक आदमी सारी रात जागता रहता है। अब उसके बैठने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर उसने थोड़ा रैस्ट करना है तो उसकी

व्यवस्था ठीक नहीं है। कहीं पंखे नहीं हैं। कहीं तारें इत्यादि लटकी हुई हैं। Quality of work life in that environment should also be taken care of. मैं ऐसा समझता हूं। यह महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि after all he is also a human being. मैंने आपसे इतनी बात करनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2017/1450/केएस/एएस/1

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-13, सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई पर जो कटौती प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभी माननीय विधायकों ने इरिगेशन एण्ड पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में क्या हो रहा है, इसकी विस्तृत चर्चा की है और अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से आपका विभाग काम कर रहा है, इसकी चर्चा की है। आप बड़ी वरिष्ठ मंत्री है और मुझे लगता है कि जो हम लोग यहां पर सुझाव देते हैं उनके ऊपर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए लेकिन पिछले चार वर्षों का जो हमारा अनुभव है, उससे ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं और आप सुनते रहते हैं। हम समस्या बताते रहते हैं और बाद में थर्सटी क्रो की कहानी सुनाकर आप बात को खत्म कर देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो बातें यहां पर आती हैं, जो हमारे विधान सभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विषय यहां पर आते हैं, उनके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए। मैंने पिछली बार विधान सभा के अंदर एक विषय रखा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम अमरोह है। मैंने सोचा बड़े वरिष्ठ मंत्री है, मैं अपनी बात रखूंगा, मेरे ऊपर विश्वास भी करेंगें। मैंने कहा कि उस स्कीम के अन्दर काम करते वक्त जो वहां पर ठेकेदार के आदमी काम कर रहे थे, उनके कपड़े भी उसी में रह गए और उसके बाद मरे हुए कबूतर उसमें रह गए। मैंने आपसे प्रार्थना की, मैंने कहा कि ऐसा विषय आया है और इस कारण गन्दा पानी जा रहा है। आपने

मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना लेकिन जिस समय आपने जवाब दिया, आपने कहा कि न तो उसमें कबूतर है और न ही उसमें कपड़े हैं। जब आप सच्ची बातों को इस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर विधान सभा के अंदर रखेंगें तो उसके कारण आपके काम करने वाले अधिकारियों का हौसला बढ़ता है कि हमसे जितनी मर्जी बड़ी गलती हो जाए, हमें तो बचा लिया जाएगा। मैं यह भी चाहूंगा कि यहां पर अगर कोई विषय रखते हैं और आपके अधिकारी व कर्मचारी यहां पर उन विषयों का उत्तर देते हैं तो उनके ऊपर काउंटर चैक जरूर किया जाए। जो बात यहां पर माननीय सदस्य बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं, उसके पीछे तर्क होता है। हम यहां पर केवल सेन्सेशन क्रिएट करने के लिए विषय को नहीं रखते। हमारी बात को गम्भीरता से नहीं लिया जाता और यही कारण है

29.03.2017/1450/केएस/एएस/2

कि आज आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा है। उसके खेत को पानी नहीं मिल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो सब डिविज़न है। एक सब डिविज़न डाडासीबा है और दूसरा सुनैत है। सब डिविज़न डाडासीबा के अंदर टोटल फीटर चाहिए 33 और आपके पास 17 हैं, पम्प ऑप्रेटर 34 चाहिए और आपके पास 25 है, चौकीदार 22 चाहिए आपके पास 9 हैं, बेलदार 111 चाहिए आपके पास 37 हैं, हैल्पर और पाइप मैन 41 चाहिए आपके पास 34 हैं, वाटर गार्ड 49 चाहिए और आपके पास 26 हैं। इसी तरीके से दूसरे सब डिविज़न सुनैत में टोटल वाटर गार्ड 56 है। आपको वहां पर टोटल वर्कर 187 चाहिए जबकि आपके पास 112 हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो पानी की स्कीमें हैं, लगबल्याणा, चनौता, टिक्कर, कनोल, हलोह, पुनली, पीह, सलुई और शांतला , ये बड़ी स्कीमें हैं। करोड़ों रुपया इनके ऊपर लगा है लेकिन इन स्कीमों के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी कम हैं। कोई बड़ी स्कीम है, उसके ऊपर आपने वाटर गार्ड लगाए हुए हैं लेकिन वाटर गार्ड भी आपके पास कम हैं। वाटर गार्ड लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है । निचले जो हमारे विभाग हैं, वहां से आपको बार-बार रिक्वैस्ट आ रही है। मेरी एक्सिअन आई.पी.एच., देहरा से बात हुई थी, वहां से बार-

बार रिक्वैस्ट आ रही है लेकिन आप लोग वाटर गार्ड नहीं लगा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक आपके पास कुछ और नहीं हैं वाटर गार्ड तो लगाइए। पांच-पांच किलोमीटर की रेडियस के अंदर एक-एक वाटर गार्ड काम कर रहा है। उसको काम करने का समय केवल चार घण्टे का दिया हुआ है लेकिन वह 12-12 घण्टे वहां पर काम कर रहा है और फिर भी लोगों को वहां पर समय पर पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जो व्यक्ति 12-12 घण्टे काम करता है, आप मुख्य मंत्री महोदय की यहां बैठकर बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा काम हो रहा है तो वाटर गार्ड के लिए भी आप लड़ाई लड़ें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी

29.3.2017/1455/AV/DC/1

श्री बिक्रम सिंह-------- जारी

एक वाटर गार्ड को 12 घंटे काम करने के लिए 1800 रुपये मिल रहे हैं। यहां पर जो व्यक्ति वाटर गार्ड के नाते काम कर रहा है उसको आप 1800 रुपये दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ गम्भीरता से उठाएं। साथ में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसको पैसे भी 6-6 महीने तक नहीं मिलते। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी सुचारु रूप से व्यवस्था करेगी। आपने वाटर सप्लाई स्कीमों पर पैसा खर्च कर दिया। आपने सुभाषपुर में 85 लाख रुपये की स्कीम लगाई लेकिन आज की स्थिति यह है कि आपके पास उस स्कीम को चलाने के लिए आपरेटर व वर्कर नहीं है। वैसे तो आपकी स्कीमें अकसर चौकीदारों द्वारा ही चलाई जाती है मगर आपके पास वहां चौकीदार भी नहीं है। वह वाटर सप्लाई स्कीम न चलने के कारण त्यामल, सुभाषपुर इत्यादि गांव में पानी नहीं मिल रहा। उसके साथ-साथ आपने और भी करोड़ों रुपये की स्कीमें चलाई हुई है। उसमें गमरूर, कानपुर, कूना, क्टो-टिक्कर, सालडोगरी इत्यादि में पानी की कमी है और वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। दूसरा आपने आऊट सोर्स वाला एक नया काम शुरू कर दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत सारी स्कीमें आऊट सोर्स है। माननीय मंत्री महोदया, उस पर कोई चैक नहीं है। अगर हमने कोई

स्कीम आऊट सोर्स कर दी है और उसका पम्प लगभग 9 घंटे चलना है वह केवल उस पम्प को 3-4 घंटे चलायेंगे। उसके बाद वह उस पम्प को नहीं चलायेंगे क्योंकि जो स्कीम आपने आऊट सोर्स की है और उसका अगर पम्प खराब होता है तो ठेकेदार को ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए उसने इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया कि मैं 9 घंटे मशीन नहीं चलाऊंगा, मैं केवल 3-4 घंटे मशीन चलाऊंगा। लोगों को पानी नहीं मिलेगा लेकिन मशीन के कम चलने से मेरी मशीन खराब नहीं होगी और मुझे उसकी रिपेयर नहीं करवानी पड़ेगी। आप इस बारे में क्रोस चैक करवाइए अगर हम गलत है तो आपको पता लग जायेगा। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जितनी देर वह चलनी चाहिए या जितनी देर उस स्कीम के चलने से पानी मिलता है वह उतनी देर नहीं चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहूंगा कि आप उसकी तरफ ध्यान दें क्योंकि उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चैक नहीं है। जब तक उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव चैक नहीं होगा तो व्यवस्था इसी प्रकार से खराब होती जायेगी। मैंने कल ही एक प्रश्न पूछा था कि पिछले 2-3 वर्षों में आपने कितने हैण्ड पम्प लगाये हैं। आपने देहरा सब डिविजन का पूरा जवाब दे दिया फिर मैंने उसमें से अपने निर्वाचन क्षेत्र की

29.3.2017/1455/AV/DC/2

सूचना निकाली। मैंने उसमें पाया कि जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर आपने 38 हैण्ड पम्प लगाये हैं। मेरे परम मित्र रतन जी साथ में हैं और इनके यहां 183 हैण्ड पम्प लगे हैं। (---व्यवधान---) काम करने वाले विधायक का मूल्यांकन तो आने वाले 5 महीनों के बाद होगा, फिर बात करेंगे। अभी इस पर बात करने की जरुरत नहीं है। आपने क्या किया है इस बारे में लोग आपकी सड़कें व हैण्ड पम्प देखेंगे। जिस समय आदरणीय मोदी जी की लहर आयेगी उस समय यह पम्प और सड़कें उड़ जायेगी और आप यह मेरा विश्वास रखना कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रो, जो यहां पर हैण्ड पम्प की बात की है, मैं भी विधायक हूं और ये भी विधायक हैं। हम भी आपके पास, विभाग के पास और डी0सी0 के पास रिक्वायरमैंट देते हैं। अगर पानी के बारे में चर्चा की जाए तो ज्वालाजी और जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर, मैं यह कोई कम्पेरिजन नहीं कर रहा हूं या मैं यह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके ज्यादा लगे हैं। लेकिन हमारे यहां पानी की कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो ये 38 पम्प लगाये गये हैं ये वहां नहीं लगाये गये जहां पानी की जरुरत है। जहां पर अनकंस्टिच्यूशनल आथोरिटी कहेगी कि यहां पर पम्प लगना चाहिए, हाइड्रोलोजिस्ट कह रहा है कि यहां पानी नहीं है लेकिन आपका नेता

कह रहा है कि यहां पर लगना चाहिए। वहां पर हैण्ड पम्प लग रहा है और आज की स्थिति यह है कि वहां उस हैण्ड पम्प में से पानी तो नहीं निकल रहा लेकिन भैंस और गाय उसमें बंधी हुई है। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल भी दे दूंगा। लेकिन मेरी डिटेल देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि पानी के अंदर कबूतर पड़ा है आपको तब पता नहीं लगा तो मैं आपको गाय/भैंस के बारे में पेरी सूचना दे भी दूं तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। यह आज की वस्तुस्थिति है और जहां-जहां पानी की जरुरत है और जहां-जहां आपकी वाटर की स्कीमें ठीक नहीं चल रही है वहां पर हैण्ड पम्प्स लगाने की जरुरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप मेरे विधान सभा क्षेत्र की ऐक्सियन से रिपोर्ट मंगवाइए। आपको उस रिपोर्ट से पता चल जायेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर हैण्ड पम्प्स की बहुत ज्यादा जरुरत है। आप कोई नई स्कीम तो दे नहीं पा रहे हैं, मैं इस बारे में मान्य सदन में पहले भी बोल चुका हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर यहां के मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री महोदय

श्री वर्मा द्वारा जारी

29/03/2017/1500/टी0सी0वी0-डी0सी0/1
श्री बिक्रम सिंह ..... जारी ।

कोई ऐसी एक स्कीम का नाम बताएं, जिस स्कीम का उद्घाटन और शिलान्यास भी इन्होंने किया हो। अगर एम0एल0एज0 ने कोई प्रायोरिटी दी है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर एम0एल0ए0 हैंडपम्प लगाने की बात करता है, तो उसके कहने पर हैंडपम्प नहीं लग रहा है, यदि वह आधे इंच की पाईप मांग रहा है, तो आधे इंच की पाईप नहीं मिलती है। अगर हम लोगों की समस्याओं को लेकर विभाग के पास जाता हैं, तो विभाग मूकदर्शक बनकर बैठा रहता है या फिर जब हम चले जाते हैं तो आपके जो दूसरे तथाकथित नेता हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग उस गांव में जाओ और आप लोग वहां की समस्याओं को लेकर आओ, फिर हम लोग काम करेंगे। यदि इस प्रकार का राजनीतिकरण किसी विभाग का हो गया है, मुझे नहीं लगता, पानी हमारे पूर्वज तो कुएं

बनाते थे, प्याऊ होते थे और उसका उनको पून्य मिलता था। आप उस पून्य के अधिकारी भी नहीं हो। आपने जिन लोगों को पानी मिलता था, उनका पानी भी छीन लिया है। जिन लोगों को यह पानी का अधिकार मिलना चाहिए था, उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे खेतों की हालत इतनी खराब है, आपकी एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम "चमुखा" है, जिस दिन से वह स्कीम बनी है, उस दिन के बाद ही वह स्कीम चली नहीं है। आपका जिस समय वहां पम्प चलाता है, तो आगे उसकी पाईप फट जाती है। मैंने एक्सियन साहिब को पूछा कि बताईये ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि जब हम पम्प चलाते हैं, तो आगे जो पाईप है, वह फट जाती है। मैंने कहा कि इसका डिजाईन किसने किया? मैं आपको पर्टिकुलरली नाम बता रहा हूं। ये एल0आई0एस0 चमुखा स्कीम हैं। मेरे पास कागज लेकर आये थे कि इसको एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डालो। करोड़ों रूपया खर्च होने के बाद स्कीम नहीं चलती है,उसके बाद और नया पैसा आ जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठेकेदारों और आपके जो ऑफिसर्ज़ हैं, उनके बीच में कही-न-कहीं कुछ-न-कुछ तो है। एक पम्प आज खराब हो गया, उसको ठीक कर दिया, 4 दिन बाद वह पम्प फिर खराब हो गया। मेरे पास तो आपके विभाग की ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि ठेकेदार, जे0ई0 और एस0डी0ओ0 मिले हुए हैं। पम्प वहीं-का-वहीं है, उसको खराब शो किया, फिर ठीक शो किया, फिर खराब शो किया और फिर ठीक शो किया। ये आपके विभाग में चला हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो मैं बातें

29/03/2017/1500/टी0सी0वी0-डी0सी जी0/2

कह रहा हूं, ये मैं अपने भाषण को बड़ा लच्छेदार बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप इसकी इंक्वायरी करवाईये। देहरा डिवीजन के अंदर क्या हो रहा है, इसको देखिये? ये मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ लगने वाले क्षेत्रों का भी यही हाल है, उन क्षेत्रों के अंदर भी ठेकेदारों का बहुत दबदबा है। जो काम करने वाले ठेकेदार है, उनको काम नहीं मिल रहा है और जो ठेकेदार विभाग के अंडर काम कर रहा है, वह स्पेसिफिकेशन्ज के अनुसार काम नहीं कर रहा है। अभी माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी बोल रहे थे, अधिकांश क्षेत्रों में खड्डें हैं और उन खड्डों में से पाईपें जाती हैं, जब बाढ़ आती हैं तो उसके बाद वे पाईपें उखड़ जाती है। जब ये पता है कि हर साल बाढ़ आएगी

और बाढ़ के कारण पाईप उखड़ेगी, तो फिर हम कोई और साईंटिफिक-वे प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? हम उस पाईप को किसी और रास्ते से लेकर क्यों नहीं जाते हैं? उस पाईप को खड्ड के ऊपर जहां तक उसका फ्लो नहीं जाता, वहां पर उसका प्रावधान क्यों नहीं करते? लेकिन अगर प्रावधान हो गया, तो पैसा कहां से आएगा, रिश्वत कहां से मिलेगी? आपके अच्छे-अच्छे कार्यक्रम कहां होंगे? आपके वाईस चेयरमैन कैसे फलेंगे-फूलेंगे? इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा आपने निवेदन है कि पानी को पानी की तरह बहने दो, इसका राजनीतिकरण मत करो। स्कीमों का राजनीतिकरण मत करो। लेकिन आने वाले वर्षों में, आपने इन 4 वर्षों में क्या किया है, लोगों ने इसका मूल्यांकन भी साथ में ही कर लिया है। इसलिए इसका भुगतान निश्चित तौर पर होगा। लेकिन फिर भी अगर जाते-जाते आप कोई पून्य का काम कर जाएंगे, तो शायद उसका आपको कोई फायदा मिले। मैंने जो ये विषय रखा है, मैंने इसको बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी के साथ रखा है, मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री जी सारी चीजों की जांच करवाएं, ताकि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो सकें। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदया, मैं आरम्भ में ही इससे पूर्व की डिमाण्ड न0 13 पर बोलूं, आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कि आप ममता की मूर्त है, ममतामयी है, करूंणामयी हैं, लेकिन आपकी इस शराफत् का आगे कोई असर नहीं होता है। आप यहां आश्वासन दे देती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी अंतर

29/03/2017/1500/टी0सी0वी0-डी0सी जी0/3

आत्मा को जगाईये और अपनी शक्ति को पहचानिए। इतना जरूर कहूंगा। महोदया, आज जो हालत है, फिटर्ज़ है नहीं,पलम्बर्ज़ है नहीं, पम्प ऑपरेटर्ज़ है नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी ।

29/03/2017/1505/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री महेश्वर सिंह.....जारी।

एक तरफ आपने फिटर्ज़ के कैडर को डैड घोषित कर दिया है। अगर आप फिटर्ज़ भर्ती नहीं करेंगे तब स्वाचालित रूप से आपकी स्कीमें अपने आप तो ठीक नहीं होंगी। उस स्कीम की मुरम्मत का कार्य कौन करेगा? पम्प ऑपरेटर्ज़ विभाग के पास नहीं हैं और लिफ्ट इरिगेशन की जितनी भी स्कीमें हैं, वे सब मशीनें इतनी मंहगी है कि आप उनकी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी हैं कि जो महंगे-महंगे पम्पस हैं, जिस दिन इनकी आउटसोर्सिंग की डेट पूरी हो, कहीं ठेकेदार ही उठा करके ले जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई सिक्योरिटी है? सभापति महोदया, आपको याद होगा, जिस दिन यह जल रक्षक लगाने की बात कही गई थी तो मैंने मंत्री महोदया से इसी माननीय सदन में पूछा था कि जलरक्षक क्या काम करेगा? इस पर मंत्री महोदया का जबाव था कि अभी तक तो मुझे भी पता नहीं है कि यह क्या काम करेगा? सभापति महोदया, मैं आज फिर आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह जलरक्षक क्या काम करता है? इसको पलम्बर की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, जो रैंच हैंडल नहीं कर सकता है, वह कैसे काम करेगा? उससे अच्छा होता कि इनको आप कम्पलैंट अटैंडेन्ट रख लेती और इनकी जगह फिटर की भर्ती करतीं तो काम आते। यह कम्पलैंट अटैंडेन्ट का काम कर सकते हैं। न जाने किस मकड़झण्डू के दिमाग की उपज थी कि आपने इन लोगों को जलरक्षक का नाम दे दिया है। ये कोई काम नहीं करते हैं। ये लोग जब रैंच चलाना ही नहीं जानते हैं तो काम कैसे करेंगे? सभापति महोदया, 'shortage of pipes' अब इस साल फिर कमी होने वाली है। मैंने मंत्री महोदया से एक निवेदन किया था कि आप ईमानदार हैं और विभाग में एक पुरानी परम्परा चली आ रही है कि जब बजट पास हो जाएगा, जब पाईपों की जरुरत पड़ेगी, तब टैंडर्ज़ कॉल किए जायेंगे। टैंडर को अप्रूव करने की पावर मंत्री के पास है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण है? आपके विभाग के तीन-तीन जोन हैं और हर जोन में

चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है, आप वर्ष के शुरू में ही जैसे जनवरी और फरवरी में ही अगर ये कोटेशन्ज़ ले लें तथा इनको अप्रूव कर दें तो कौन-सी दिक्कत है कि उसके बाद जो आपके जोन में चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं, वे अपने जोन के लिए पाईप नहीं खरीद सकते

29/03/2017/1505/ एन0एस0/डी0सी0 /2

हैं? मंत्री महोदया, आप मुझे बताईए कि ऐसा कौन-सा कारण है कि बार-बार फाईल आपके पास आती है? अभी आप सभी देखिए कि मार्च में बजट पास हो जाएगा और यह चुनावी साल है। कब आप पाईपें खरीदेंगे और कब आप काम करेंगे? यह मुझे मालूम नहीं है। इस माननीय सदन में एक सदस्य कह रहे थे कि पाईपों की कमी है। अगर वर्ष के शुरू में ही कमी है तो फिर बीच में क्या होगा? आप और हम लोग सभी चुनाव में व्यस्त हो जायेंगे और पाईपें फिर अगली सरकार खरीदेगी। ऐसी स्थिति है इसलिए मंत्री महोदया थोड़ा जागिए और इन बातों की तरफ ध्यान दीजिए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कुछ ही बिन्दुओं पर अपनी बात को बोल करके समाप्त कर दूंगा। एक मैंने पाईपों की बात कही है। दूसरा, मैं वाटर रेट के बारे में कहना चाहूंगा। वाटर रेट का आज जो प्रावधान है, दस प्रतिशत हर साल वाटर रेट बढेंगे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि एक दिन आयेगा, जिस दिन पीने का पानी महंगा होगा और शराब सस्ती हो जाएगी। यह दस प्रतिशत बढ़ाने का क्या मतलब है? हमारे यहां पर ग्रेविटी स्कीमज़ हैं और उसमें सरकार का खर्चा ज्यादा नहीं है। फिर यह हर साल दस प्रतिशत रेट क्यों बढ़ रहे हैं? अब मैं सीवरेज़ की तरफ आना चाहूंगा। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि स्वच्छता अभियान चलाओ। इसको कैसे चलायें? सीवरेज़ के चार्ज़िज आपने कुल्लू जैसी जगह में 50 प्रतिशत रखे हैं। 50 percent of the water rate. वहां पर हमारी पीने के पानी की स्कीमें फ्लो की हैं, न कि लिफ्ट की हैं। शिमला में लिफ्ट की स्कीमें हैं और सीवरेज चार्जिज़ 25 प्रतिशत हैं। यही चार्जिज़ मेरे क्षेत्र में 50 प्रतिशत हैं। जब मैंने वाटर रेटस को ले करके स्पैशल मैंशन यहां पर रखी तो हमें जबाव बाद में आया। वह जबाव इतना ज्ञानवर्धक लिखा हुआ है। मैं इसके लिए विभाग वालों को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने यह जबाव तैयार किया

हुआ है। मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे आज बोलने का अवसर मिलेगा, नहीं तो मैं उस जबाव को साथ ले करके आता।

श्री आर0के0एस0 द्वारा --------जारी।

29/03/2017/1510/RKS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह.. जारी

पानी बड़ा निर्मल है इसे जितना भी खर्च करो बहुत अच्छी बात है। यह पूण्य का कार्य है। हमने यह कहा था कि पानी के रेट्स को मत करिए। आप पानी की वेस्टेज को देखिए। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनमें बड़े-बड़े टैंक लगे हुए हैं और उनमें बॉल्स नहीं हैं। रातों-रात हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यह आपके लिए बड़ा जैश्चर होगा अगर आप 2000 लीटर पानी हर महीने हर कंज्यूमर को निःशुल्क देंगे तो आपका भला होगा। जो सरकारी बिल्डिंग्स में पानी की वेस्टेज हो रही है क्या इसका लेखा-जोखा आपके पास है? रेस्ट हाउसिज़ में रातों-रात कितना पानी चला जाता है। दूसरा, जो पानी के स्त्रोत हैं उनमें बहुत गंदगी फैली हुई है। मैंने कई बार यह बात यहां पर कही है। सबसे पहले सोर्स को प्रोटैक्ट करने की जरूरत है। आपके फिल्टर बैड्स बने हुए हैं। मणिकर्ण में एक स्कीम है, जहां फिल्टर बैड्स बने हुए हैं, फिल्टर टैंक्स बने हुए हैं, वे पानी डालने से पहले ही लीक हो गए। ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह काम ऐसे ही चलेगा? यह सब बातें मैं आपके ध्यान में ला चुका हूं लेकिन मैं इनको दोहरा रहा हूं।

ई-टैंडरिंग एक नया सिस्टम है। सभापति महोदया, ई-टैंडरिंग केवल-और-केवल आई0पी0एच0 विभाग ने इम्प्लिमैंट की। ई-टैंडरिंग से क्या हुआ? इनके पास A, B ,C ,D चार प्रकार के कॉंट्रैक्टर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा C&D प्रभावित हुए । इनकी संख्या बहुत है और जो काम इनको मिलते हैं वह साढ़े 7 लाख रुपये से ऊपर का दूसरा काम इन्हें नहीं मिलता है। इनको जो प्रमोट करने की कंडिशन है वे उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको एक ही काम मिलता है तो ए. और बी. ग्रेड कैसे मिल पाएगा। A और B

वालों की मॉनोपॉली शुरू हो जाती है तो सबलैटिंग शुरू हो जाती है। सभापति महोदया, आप भी इस बात से सहमत होंगी। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि ई.पी.एफ. की रजिस्ट्रेशन से इनको छूट दे दी जाए। यह मैंने लिखित रूप में भी दिया है। जो आपके XENs हैं उनकी पॉवर आज कितनी हैं। मैंने कहा था कि XENs की पावर तीन लाख रुपये की कर दीजिए और

29/03/2017/1510/RKS/AS/2

SDOs की पावर एक लाख रुपये की कर दीजिए। ताकि छोटे ठेकेदारों को काम भी मिले और हमारे काम भी हो जाएं अन्यथा काम नहीं होंगे। A और B क्लास के ठेकेदार सारे-के-सारे काम सबलैट करते हैं और काम सब- स्टैंडर्ड होता है। जरूरतमंद ठेकेदार काम भी ईमानदारी से करते हैं। इस तरीके से आपके विभाग में तत्परता आएगी। आखिर में, मैं फिर एक शब्द को दोहराऊंगा कि आज तो शायद आपको पता लग गया होगा कि ये जलरक्षक कोई काम नहीं करते हैं। इस पर विचार करिए। उस दिन भी मैंने कहा था कि एक दिन आएगा और एक कहावत भी है कि 'मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा कुएं से पानी।' वह हालत आज वहां पर है। यहां किसी ने जलरक्षक की बड़ी तारीफ की लेकिन हमारी तरफ तो जलरक्षक कुछ नहीं करते हैं। इसलिए इन सारी योजनाओं पर पुनर्विचार करें। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

29/03/2017/1510/RKS/AS/3

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री रिखी राम कौंडल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः सभापति महोदय, मांग संख्या-13- वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, जिसके बारे में इस माननीय सदन के अंदर दिए गए कटौती प्रस्ताव द्वारा चर्चा हो रही है, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं या हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो सड़कों के किनारे बोर्ड्स लगें हैं 'जल ही जीवन

है।' जब जल ही जीवन है और जल ठीक ढंग से न दिया जाए तो जीवन के साथ खिलवाड़ है। वाटर सप्लाई का जहां तक प्रश्न है मैं लम्बी बात नहीं करूंगा। अगर इस पर बात करने लगे तो विस्तार से चर्चा हो सकती है। वह तो डिस्कशन में आएगा।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

29.03.2017/1515/SLS-AG-1

श्री रिखी राम कौंडल... जारी

हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का कंसैप्ट, इस प्रदेश में जब से पंचवर्षीय योजनाएं बननी शुरू हुई; डॉक्टर परमार के बाद ही इस कंसैप्ट का ज्यादा विस्तार हुआ। अगर मैं नाम लूं तो पानी का सबसे ज्यादा विस्तार 1977 में हुआ जब शांता कुमार जी की सरकार बनी थी। उस समय हमने देखा कि यह बात घोषणा-पत्र में शामिल थी कि हम हर घर को नल देंगे और जब तक बहनों के सिर से घड़ें नहीं उतार लेंगे तब तक एक ही समय भोजन करेंगे। यह उनका प्रण था। उस प्रण को निभाते हुए उन्होंने अनेकों स्कीमें बनाईं।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में ग्रेवटी की 3-4 स्कीमों के अलावा लिफ्ट वॉटर सप्लाई की एक भी स्कीम नहीं थी। वर्ष 1977 में 4 बड़ी स्कीमों पर काम शुरू हुआ और वह पूर्ण हुईं। उस समय इस सदन में श्री विचित्र सिंह जी थे जो हमारे सुजान सिंह पठानिया जी के बड़े मित्र थे। वह कृषि मंत्री थे। उनके समय में हमें अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसा महसूस होने लगा कि पानी के बारे में सरकार बहुत सजग है और जिस तत्परता के साथ पानी का काम चला है, उसे देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी। उसके बाद अनेकों सरकारें आईं।

मैं यह नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया। अपने विवेक से, अपने अनुभव से और प्रदेश में उपलब्ध साधनों की उपलब्धता के मुताबिक हर सरकार ने पानी

की स्कीमों का विस्तार करने के लिए वॉटर सप्लाई और इरिगेशन स्कीमों का विस्तार किया। अब अगर हम यह कहें कि इन 4 वर्षों में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया तो इस बात से मैं स्वयं थोड़ा-सा सहमत नहीं हूं। लेकिन जितना काम 4 सालों के अंदर करना चाहिए था, उतना नहीं किया, मैं अपनी इस बात से सहमत हो सकता हूं।

सभापति महोदया, पानी की स्कीमों का रख-रखाव करने के लिए, जैसे यहां चर्चा हुई, फीटर, वॉटर गार्ड और पंप ऑप्रेटर इस कार्य को मैनेज करते हैं और

29.03.2017/1515/SLS-AG-2

सरकार उनको वेतन देती है। जहां-जहां स्कीमें बनी हैं उसके आधार पर उनके पद स्वीकृत होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय रविन्द्र रवि जी पिछली सरकार में जब आई.पी.एच. मिनिस्टर थे, उस समय वॉटर गार्डों की भर्ती हुई थी। उन वॉटर गार्डों के पैसे में अभी आपने थोड़ी-सी बढ़ोतरी की है। हमने एक कंसैप्ट रखा था कि आने वाले समय में उन वॉटर गार्डों की रैगुलर भर्ती करेंगे। लेकिन फिर चुनाव आ गया और लोगों ने सत्ता आपको दे दी। जब आप सत्ता में आए तो हमने सोचा था कि आप भी, जो प्रोपोजल हमारी सरकार ने बनाई थी कि कंट्रैक्ट पर भर्ती करेंगे, जैसे कि हर जगह कंट्रैक्ट पर भर्ती की जा रही है, आप इन वॉटर गार्डों को भी कंट्रैक्ट पर भर्ती करेंगे।

हमने पंचायतों में कुछ लोग लगाए। सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने इन 4 सालों में पंचायतों में कितने लोग लगाए? जो पुराने रैगुलर लोग थे, वह अब सारे रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह कोई एक भी नई भर्ती नहीं हुई। इरिगेशन की 4-4 स्कीमों को एक ही ऑप्रेटर चला रहा है। जहां तक हमारी LIS और सिंचाई सुविधा का प्रश्न है, हमारे यहां भाखड़ा डैम बना जिससे हम सारे लोग विस्थापित हुए। उस समय की सरकार ने जो MOU साईन किया, उसमें यह करना चाहिए था कि जो भाखड़ा रिज़र्वायर है, उससे हम पीने और सिंचाई के लिए पानी ले सकेंगे। उस समय की सरकार ने वह MOU साईन नहीं किया। हमने अपनी सरकार के समय में भी इस विषय को

उठाया। माननीय धूमल जी ने दिल्ली में जाकर प्रयत्न भी किए लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं हुई। हमें आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो 6 बार के मुख्य मंत्री हैं, केंद्र में इनका बड़ा अनुभव है, इनकी अच्छी जान-पहचान भी है, आप हमारी स्कीमों के लिए उस भाखड़ा डैम के रिज़र्वायर से पानी लेने के लिए, जब केंद्र में आपकी सरकार थी, केंद्र सरकार से बात करेंगे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ।

...(व्यव धान)...

जारी ...श्री गर्ग जी

29/03/2017/1520/RG/AS/1

श्री रिखी राम कौंडल---क्रमागत

आज रिजरवॉयर में हमारे घरों के पास पानी है, लोग पानी देखते हैं और जो ऑउस्टीज बसे हैं, वे पानी दूर से देख सकते हैं, लेकिन पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, सिंचाई की बात तो अलग है।

सभापति महोदय, मैं यहां कोट करना चाहूंगा। मेरी इस समय 5-6 स्कीमें हैं। एक सीर खड्ड बेसिन पर बनी हुई है और श्री धर्माणी जी की भी बनी हुई है, जो सुकर खड्ड, सिरियाली खड्ड और सीर खड्ड की जितनी भी हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, आज वे सारी बंद हैं और सिंचाई विभाग ने उन स्कीमों के मीटर भी कटवा दिए। इसके क्या कारण हैं? जिस सुविधा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कुछ आपकी सरकार के समय में हुआ और कुछ हमारी सरकार के समय में हुआ, तो आज जब लोगों को उससे सिंचाई की सुविधा न मिले, तो क्या हो सकता है? मैंने जब विभाग से पता किया, तो वे कहते हैं कि हमारे पास कोई आदमी ही नहीं है, कई स्कीमें ऐसे ही हैं। जब हमारे पास स्कीमें चलाने के लिए कोई कर्मचारी नहीं हैं, तो मीटर का हमें मुफ्त का पैसा पड़ रहा है। इसलिए हमने मीटर कटवा दिए। सभापति महोदया, इन बातों से कोई सरकार की पारदर्शिता जाहिर नहीं होती है। अगर आपके विभाग का अधिकारी यह कहे कि हमारे पास स्कीम चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है इसलिए हमने मीटर कटवा दिए, तो लोगों के बीच में एक अच्छी सरकार का सन्देश नहीं जाता है।

सभापति महोदया, मैं यहां अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र के एक कोटधार क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां 13-14 पिछड़ी पंचायतें पड़ती हैं। जैसे-जैसे वहां की आबादी बढ़ रही है, वहां पानी की समस्या गंभीर बनती जा रही है। हमने एक स्कीम प्रपोज़ की, जैसे माननीय श्री रविन्द्र सिंह, पूर्व सिंचाई मंत्री जी के समय में बिलासपुर में कोल डैम की स्कीम प्रपोज हुई, मैंने विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत एक स्कीम प्रपोज की, तो भाखड़ा के पास हमारा एक कुटभौंगड़ नामक एक स्थान है, वहां से हमने पानी उठाना था। लेकिन बी.बी.एम.बी. वालों ने उसके लिए एन.ओ.सी. नहीं दिया। मैंने विभाग को फिर लिखकर भेजा कि जहां रिजरवॉयर है, उसके साथ नाले में ग्रेविटी का पानी अपने आप पीछे को आ रहा है, इसलिए जितना भी उनका ऐक्वायर्ड एरिया है, उस ऐक्वायर्ड एरिये से पीछे यदि हमारा रिजरवॉयर मिल रहा है, तो

29/03/2017/1520/RG/AS/2

अच्छा है। तब भी उस स्कीम में बार-बार ऑब्जेशन लगाकर फिर वापस भेजा जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है और विभाग के प्रधान सचिव भी अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि उस स्कीम को तुरन्त क्लीयर करिए ताकि उस कोटधार के जितने भी टैंक हैं, उनकी प्रपोजल के अनुसार उन टैंकों में वह पानी उठाकर डाला जाना है ताकि पानी की गंभीर समस्या का समाधान होगा।
सभापति महोदया, इसके पश्चात मैं कहना चाहूंगा कि पानी की स्कीमें विभाग ने ऑउटसोर्सिंग पर दे दीं, ठेकेदारों को पैसा देने के लिए नहीं है। ऑऊटसोसिंग वाली स्कीमों में जो ठेकेदार जाता है, वह लाइन पंक्चर करके अपनी मर्जी का पानी लोगों को देता है, न तो एस.डी.ओ. का कंट्रोल उन पर हो रहा है और अधिशाषी अभियन्ता के पास सिर्फ पैनल्टी लगाने की पॉवर है और ऊपर से राजनैतिक दवाब पड़ जाता है, चाहे हमारा हो या आपका कोई हो। राजनीतिक दवाब तो दोनों तरफ से पड़ता है। हमारा कोई आदमी होगा, तो उसके लिए हम विभाग को कहेंगे और आपका कोई आदमी होगा, तो आप कहेंगे। उस दवाब में जितनी भी स्कीमों की ऑऊटसोर्सिंग की गई है, उन सबका सत्यानाश कर दिया गया। जहां किसी को नॉर्म्ज के मुताबिक नलका मिलता है, तो वह नॉर्म्ज के मुताबिक

नहीं दिया जाता और वह नलका मर्जी से जो वहां ठेकेदार है या दूसरे लोग रखे हैं, तुरन्त वे नलका लगा देते हैं। तो ऑऊटसोसिंग का यह हाल है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो ऑऊटसोर्सिंग की स्कीमें हैं, इनको विभाग को दीजिए क्योंकि सरकार का उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर लगा है, उन पर बहुत पैसा खर्च हुआ है। वे ऑऊटसोर्सिंग वाले ठेकेदार उस पैसे की बरबादी कर रहे हैं। या फिर आप एम.ओ.यू. साईन करते समय ऐसी कंडीशन लगाएं कि कोई भी ठेकेदार विभाग की अप्रूवल के बगैर लाईन को पंक्चर नहीं करेगा। लेकिन यहां तो हर मेन लाईन को पंक्चर करके नलके दे दिए गए हैं, तो पानी आगे कैसे जाएगा? ये विषय हमारे ध्यान में आए हैं।

सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसके पश्चात मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। पिछली सरकार के समय में जब श्री रविन्द्र सिंह जी, माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय एक निर्णय लिया गया कि हर सब-डिवीजन में जहां-जहां हमारी खड्डों में स्कीमें हैं उनमें डक्ट वॉल लगाई जाए। सिंचाई

29/03/2017/1520/RG/AS/3

एवं जन-स्वास्थ्य के हर सब-डिवीजन में दो-दो डक वॉल लगाई जाएं जहां हमारी पानी की स्कीमें चली हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसी स्कीम हैं सिरयाली खड्ड पर लगे। मैं विभाग के ध्यान में लाना चाहूंगा कि सीर खड्ड में कितनी अनियमित्ताएं हैं कि हमारे समय में झण्डुता में बैरन का एक टैण्डर हुआ, 11 गावों की एक बड़ी स्कीम है दो-अढ़ाई करोड़ रुपये की स्कीम की आज वह हालत कर दी गई है और

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2017/1525/MS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी---------

सीर खड्ड में एक डक्ट वॉल लगाई गई और सिर्फ वहां रेता ही चिन दिया और वह वॉल वर्षा होने से पहले ही गिर गई। जब वह विषय अखबारों में आया तो जिस ठेकेदार ने वह काम किया था उसको विभाग ने नोटिस दिया। अगर वह अखबार में विषय नहीं आता, हम विभाग के ध्यान में नहीं लाते तो उस गिरी हुई वॉल की भी उस जे0ई0 ने एम0बी0 में एंट्री कर दी थी। मेरा निवेदन है कि झण्डुता सब-डिवीजन के अंदर सीर खड्ड में जो हमारी बैरन स्कीम पर डक्ट वॉल लगाई गई है उसकी आप छानबीन करवाइए। आपके विभाग के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। जिस उद्देश्य के लिए वह स्कीम बनाई गई थी, आज उस स्कीम से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है । सभापति महोदया, आपकी सरकार आने के बाद आपने वह स्कीम ही बन्द कर दी है। अब किसी खड्ड में डक्ट वॉल नहीं लगेगी। अब उस पर कोई ध्यान नहीं है।

आज पानी के सोर्स सूख रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पानी के सोर्स को सरकार सूखा रही है। यह नेचर है। अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी तो कम होगा ही परन्तु उसको रोकने के लिए जो हम कर सकते हैं, वह हमें करना चाहिए।

सभापति महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी से एक निवेदन किया था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है इसलिए वहां कुछ हैण्डपम्प लगाए जाएं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने वे हैण्डपम्प तुरन्त स्वीकृत किए। परन्तु जब हमने विभाग के पास सूची दी तो पहले इनके चीफ इंजीनियर को पत्र गया और उसके बाद एक्सियन के पास पत्र गया। वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से हैण्डपम्प लगाएंगे? ऊपर से हर कोई आदेश कर देता है कि हैण्डपम्प लगा दो लेकिन हमारे पास धन नहीं है। तो मैं क्या पारदर्शिता इस सरकार की मान सकता हूं? मंत्री महोदया एक अनुभवी मंत्री और इस मान्य सदन की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जोकि इस मान्य सदन को स्पीकर के नाते भी सुशोभित कर चुकी हैं तथा बार-बार हरेक विभाग को देख चुकी हैं। ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और हम इनको बहुत मान-सम्मान देते हैं, इनका आदर-सत्कार करते हैं तथा कभी इनके साथ उलझते नहीं है। इनका पत्र जाए और विभाग के

29/03/2017/1525/MS/AG/2

लोग यह कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, यह अच्छा नहीं लगता। पैसे की व्यवस्था के लिए वे मंत्री से बात करे, विभाग के चीफ इंजीनियर से बात करे या सचिव से बात करे, तब

हैंडपम्प लगेंगे। वहां वास्तव में ही हैंडपम्पों की आवश्यकता थी इसलिए मंत्री महोदया इस पर थोड़ा गौर कीजिए। आप थोड़ी सी सख्ती कीजिए। आपकी शराफत का फिल्ड के अधिकारी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जैसे महेश्वर सिंह जी ने कहा कि थोड़ी सी सख्ती दिखाइए।

मैं एक प्रसंग सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हनुमान जी जब बड़ी विचित्र बातें करते थे तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि आप शक्ति-विहीन हो जाएंगे। जिसके लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी तो सृष्टि में तो हा-हाकार मच गया। फिर ऋषियों के पास सभी देवी-देवता गए कि आप अपना श्राप वापिस ले लीजिए। तो एक शर्त पर वह श्राप वापिस लिया कि आपको शक्ति जतानी पड़ेगी, जब शक्ति का आह्वान आपके पास करेंगे तो आपको ताकत आ जाएगी। मैं आज आपको शक्ति बता रहा हूं कि आपकी शक्ति कितनी है। इसका आप उपयोग कीजिए और उन अधिकारियों पर लगाम कसिये जो आज आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सभापति महोदया, मैंने ये कुछ विषय आपके समक्ष यहां रखे हैं।

मेरी विधायक प्राथमिकता में एक डी0पी0आर0 चॉक्ड पाइप की थी। जो ग्रेविटी की दूसरी स्कीमें हैं तो बिलासपुर में कोटधार के क्षेत्र में पानी में चूना ज्यादा है। हो सकता है कि धर्माणी जी के चुनाव क्षेत्र में भी ग्रेविटी की स्कीमों की ऐसी स्थिति हो तो चॉक्ड पाइप के लिए हमने विधायक प्राथमिकता में रखा है। उसकी डी0पी0आर0 सर्कल से भी आ चुकी है और यहां काफी दिनों से वह डी0पी0आर0 आपके विभाग के चीफ इंजीनियर के कार्यालय में पड़ी है। मेरा आपसे और सचिव महोदय दोनों से निवेदन है कि उस चॉक्ड पाइप की जो डी0पी0आर0 हमने विधायक प्राथमिकता में दी है उसको तुरन्त क्लीयर कीजिए ताकि टेलएण्ड पर जो लोग पानी से वंचित हो रहे हैं, उनको हम पानी दे सकें। ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं।

अन्त में मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में फोरलेन का काम चला हुआ है। मेरी दो पंचायतें उसमें सम्मिलित हैं। उन दो पंचायतों में विभाग ने फोरलेन के अधिकारियों को ऐस्टीमेट दिए हैं कि हमारे इतने हैण्डपम्प

29/03/2017/1525/MS/AG/3

आपने डिस्टर्ब कर दिए जोकि खराब हो गए हैं। जहां से सड़क निकली, वहां हैण्डपम्प बर्बाद कर दिए हैं जबकि वहां से हमारे लोग पानी भरते थे। हमारे कुएं और बावड़ियां सारी सूख गई हैं। हमारे सारी पाइपें डिस्टर्ब कर दी हैं। इसके लिए हमने बार-बार अधिकारियों तथा जिलाधीश महोदय से भी निवेदन किया। मैंने जब कानून-व्यवस्था में चर्चा चल रही थी तो मैंने इसको पासिंग रेफरेंस में कहा था कि जब फोरलेन के अधिकारियों के पास हमारे लोग जाते हैं तो वे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर भी गौर करें। माननीय मंत्री जी जो डी0पी0आर0 हमारे विभाग ने बनाकर फोरलेन वालों को भेजी है उसका तुरन्त पैसा लीजिए और उन हैण्डपम्पों को रिस्टोर कीजिए।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

29.03.2017/1530/जेके/डीसी/1

श्री रिखी राम कौंडलः-----**जारी**------

एक तो सड़क बनाएं। मिट्टी से हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं लेकिन सुविधा भी हमें मिलेगी। जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, वह उनकी सड़कों की वजह से बर्बाद हुआ है। उसको ठीक करने का एम0ओ0यू0 जो साईन हुआ है उस पर वे गौर नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी विभाग ध्यान दें। सभापति महोदया, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

29.03.2017/1530/जेके/डीसी/2

सभापतिः अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या-13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई, इस पर जो कटौती प्रस्ताव हम लोगों ने विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, यहां पर बहुत बातें हुई। हमारे साथियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। जहां-जहां विभाग की, सरकार की कमियां थी उन बातों का भी जिक्र हुआ। मैं यह मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और मानव जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। जैसे कि हमारे सब साथियों ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं भी इस बात से सहमत हूं। सभापति महोदया, मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा। दो-तीन प्वाईंट्स पर कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक वक्त था जब आबादी बहुत कम थी। आबादी कम थी लेकिन हमारे जो प्राकृतिक स्त्रोत, विशेषतौर पर जल के दोहन की उनकी संख्या भी ज्यादा थी और संख्या ज्यादा होने के साथ-साथ उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा थी। आबादी बढ़ती गई। स्वाभाविक रूप से पानी के बिना जीवन नहीं इसलिए पानी की मांग भी बढ़ती गई। जितने भी हमारे पानी के स्त्रोत थे उन स्त्रोतों से पानी ले करके आम आदमी को पीने के लिए उसे पहुंचाया जाए, उस दृष्टि से प्रयत्न हुए, प्रयास ह़ए। लेकिन आज हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि स्त्रोत तो वही हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ौत्तरी की गुंजाइश नहीं है। स्त्रोत बनने के बजाय अब घटते जा रहे हैं। आबादी भी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक रूप से पानी की मांग घटने के बजाय बढ़ती जाएगी। क्या हमने इन सारी बातों पर विचार किया कि ऐसी परिस्थिति में जो हमारा पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाने का परम्परागत तरीका है, उससे क्या गुजारा चल पाएगा? हम लोगों को आने वाले 50-100 सालों के लिए कुछ योजनाओं को बना करके इस विभाग को दिशा देने की आवश्यकता है। उसमें काम करने की आवश्यकता है, वह करना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है कि विभाग को आने वाले समय में लम्बे समय

29.03.2017/1530/जेके/डीसी/3

तक उन योजनाओं को चलाना है, चालू रखना है और उनके माध्यम से लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिले उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है और उस तरह से योजना बनाने की भी आवश्यकता है। हमने कई जगह देखा हमारा स्त्रोत एक है। एक गांव

ने मांग की कि हमें पीने का पानी चाहिए। हमने पाइपें जोड़ दी और पानी पहुंचा दिया। दूसरे गांव के लोगों ने भी मांग की कि हमें भी पीने का पानी चाहिए जो कि यहां से पहुंचना चाहिए और स्त्रोत वही है, वहीं से पाइपें जोड़ दी और वहां पर भी पानी पहुंचा दिया। उसके बाद दूसरी पंचायत के लोगों ने भी मांग की कि हमारे गांवों में भी पानी की सुविधा ठीक प्रकार से नहीं है इसलिए इस गांव को आप पानी पहुंचाइए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

29.03.2017/1535/SS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

और आपने फिर तीसरी पाइप लाइन उसी सोर्स से जोड़ दी। एक सोर्स की जो पानी की क्षमता है उससे ज्यादा आपने पानी की स्कीमें लगा दीं। उसका परिणाम यह निकल रहा है कि जो चली हुई स्कीमें थीं, जिन गांवों को वह स्त्रोत अच्छी तरह से पानी की सुविधा देता था, उस गांव को भी पानी की सुविधा बंद हो गई है। क्या यह सोचने का विषय नहीं है? आने वाले समय के लिए जो आज की तारीख में करने की आवश्यकता है, वह करना चाहिए। पानी की योजना बनाने से पहले उस सोर्स की पर लीटर कितनी कैपेसिटी है, उसमें एक मिनट में कितना पानी निकलने का स्कोप है, वह देखना चाहिए। उस दृष्टि से सब काम करने की आवश्यकता है। यह काम कौन करेगा? मंत्री विभाग को आदेश दे सकता है लेकिन यह काम जिम्मेवारी का है। विभाग में जो टेक्निकल स्टाफ है या अधिकारी हैं उनका यह जिम्मा है। एक तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

दूसरे सभापति महोदया, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हमारे इलाकों में कुछ जगह ऐसा है कि अभी सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है, यह सैशन समाप्त होते-होते वहां से मांग आनी शुरू हो जायेगी कि वहां पर पानी की कमी हो गई और वहां टैंकर लगाए जाएं। क्योंकि वहां पर पानी का सोर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी के

टैंकर वहां लगाकर लोगों को पानी की सप्लाई दी जाती है। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जो इस प्रकार के ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं उन्हें आइडेंटीफाई किया जाए। विभाग आइडेंटीफाई करता है। मैं यह नहीं कहता कि विभाग बिल्कुल आइडेंटीफाई नहीं करता। मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र का एक इलाका ऐसा है जहां पानी की बहुत दिक्कत है। हम वर्षों से बोल रहे हैं और मैंने विधायक प्राथमिकता में भी स्कीमें डाली हैं लेकिन उसके बावजूद हर सीज़न में यह होता है कि वहां टैंकर लगाना पड़ता है। क्या हम स्थायी रूप से वहां पर पानी की सुविधा नहीं दे सकते? अगर वहां पर ग्रैविटी की स्कीम सम्भव नहीं है तो हम वहां पर लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम क्यों नहीं दे सकते? यह आखिर कौन करेगा?

29.03.2017/1535/SS-DC/2

विभाग आगे से आगे यह काम टालने का काम करता है। इस बार का सीज़न निकल गया, फिर अगली बार देखेंगे। मुझे लगता है कि यह जो अस्थाई या एडहोक सोच है इसको बदलने की आवश्यकता है। हम 20, 50 या 100 साल के लिए योजनाएं बनाएं। आप कल्पना करिये, यह शिमला अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है। यहां पर वाटर सप्लाई स्कीम अंग्रेज़ों के समय से चल रही है। जब यहां की पापुलेशन 25 हजार थी, आज ढाई लाख से ज्यादा यहां पापुलेशन है लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ों के उस वक्त की स्कीम आज भी शिमला के शहर को पानी उपलब्ध करवा रही है। इतने लम्बे समय तक सोचने की आवश्यकता इस विभाग को क्यों महसूस नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर सोचने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि आज की तारीख में कुछ करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो बात हमारे साथियों ने कही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। एक नया रिवाज आ गया कि सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद कुछ नेता खड़े हो जाते हैं कि हैंडपम्प यहां लगेगा। अरे भाई, हैंडपम्प लगाने के लिए न तकनीकी दृष्टि से तूं दक्ष है और न मैं हूं। यह विभाग देखेगा, हाइड्रोलोजिस्ट वहां जाकर देखेगा कि यहां पर पानी उपलब्ध होगा या नहीं। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, सिर्फ यहीं

लगेगा। मशीन लेकर जाते हैं और खड़ी कर देते हैं कि यहां हैंडपम्प लगेगा। क्यों? हम उससे पूछते हैं कि भाई यहां तो घर एक है, हैंडपम्प तो वहां लगना चाहिए जहां गांव है। हैंडपम्प वहां लगना चाहिए जहां से बाकी गांव के लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। नहीं, क्योंकि यह मेरी पार्टी की सरकार है इसलिए मेरी पार्टी के समर्थक के आंगन में हैंडपम्प लगना चाहिए। यह सोच बदलने की आवश्यकता है। क्यों विभाग इस बात का चिन्तन नहीं करता कि यहां हैंडपम्प नहीं लग सकता क्योंकि फिजीबिलिटी नहीं है। पानी निकल सकता है लेकिन हैंडपम्प लगाने का औचित्य नहीं है क्योंकि एकमात्र घर को लाभ देने का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम सब गांवों के लोगों को पानी देना चाहते हैं। क्या इस सोच के साथ बात नहीं कर सकते?

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2017/1540/केएस/एजी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

दूसरे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि वहां पर गांव में किसी ने घर बना दिया तो घर बनाने के साथ-साथ वहां पर स्वभाविक रूप से पानी का कनैक्शन भी लगेगा। वह चुने हुए प्रतिनिधि के नाते इस बारे में हमें एप्लीकेशन देता है । हम उसे आगे भेजते हैं। हम तो विभाग की ओर से कह देते हैं कि भाई आजकल डिपार्टमैंट के नॉर्मज़ बड़े सैट हो गए हैं। उसमें यह हो गया है कि जिस स्कीम के अगेंस्ट पाइपे इश्यू होती हैं, हम परचेज़ करते हैं। जो हमें पाइपें सप्लाई होती हैं उन पाइपों को हम इस तरह से लूज़ दे नहीं सकते और इसलिए किसी के घर में नलका लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके दूसरे दिन देखते हैं वहां कांग्रेस का नेता आता है और हमारे सामने-सामने ट्रक में डालकर पाइपें ले जाता है। क्या यह सब करने की आवश्यकता है? मैडम, हम आपका बहुत आदर करते हैं। बाकी लोग तो आपको पानी पी-पी कर कोस रहे थे परन्तु मैं उतना नहीं कर रहा हूं। मैं आराम से व्यावहारिक बात कर रहा हूं। इस कल्चर को रोकने की आवश्यकता है। परिणाम उसका क्या होता है, आप पाइपें दे देते हैं क्योंकि नेता ने कहा है। देनी जरूरी है

नहीं तो वह उस जे.ई. को, एस.डी.ओ. को बदल देगा। उसका परिणाम यह होता है कि जिन स्कीमों के अगेंस्ट हमारी पाइपें आई होती है, वह स्कीम आधी अधूरी रहती है और एक कांग्रेस के नेता के घर के लिए तो पानी चला जाता है, उसको पाइपें मिल जाती हैं लेकिन हजारों लोग पानी के बिना रहते हैं क्योंकि जिस स्कीम के अगेंस्ट पाइपें आई थीं, वे सारी स्कीमें अधूरी रह जाती हैं। यह सब बदलने की आवश्यकता है। अगर आपको किसी के लिए पाइपें देनी हैं उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके लिए अलग से प्रावधान करिए।

सभापति महोदया, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। वहां पर कुछ योजनाओं पर बहुत तेजी से बहुत अच्छा काम चल रहा था लेकिन उसके बावजूद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार वर्ष बीत गए और अब तो पांचवा वर्ष भी बीतने वाला है लेकिन आज वे सारी योजनाएं जो आधे से ज्यादा हमने पूरी कर दी थी, आज वह स्कीमें जहां छोड़ी थी, वहीं के वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इन्तज़ार कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से जिस प्रकार से उनको इंस्ट्रक्शन्ज़ देने की आवश्यकता है, उनकी

29.03.2017/1540/केएस/एजी/2

खींचाई करने की आवश्यकता है, उस प्रकार से हो नहीं रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आप गलत तरीके से अधिकारियों को डांटो लेकिन विभाग सुचारू रूप से चले तो सही।

सभापति महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र की एक स्कीम जिसको साढ़े चार साल हो गए, उस स्कीम का मेरे गांव की स्कीम है, मेरी विधायक प्राथमिकता की स्कीम है , छड़ी खड्ड से तांदी की स्कीम है, कहा जा रहा है कि अभी एक साल उसको पूरा होने के लिए और लगेगा। जिसको पांच साल से ज्यादा समय हो गया, वह अभी तक अधूरी है। थाची धदवास मेरे विधान सभा क्षेत्र की वाटर सप्लाई स्कीम अधूरी है। कालीगढ़ की हमारे विधान सभा क्षेत्र की लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों का ज़िक्र करें तो करें क्या? क्या बोलें? मेरे सभी साथियों ने यहां पर ठीक कहा कि होना कुछ नहीं है लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए अपनी बात कह देनी चाहिए और हम भी इसीलिए कह रहे हैं।

सभापति महोदया, हमें इस बात की पीड़ा है कि हमारे पास सिर्फ पांच वर्ष का समय होता है। परफोर्म करने के लिए एक विधायक के पास और विभाग जिस प्रकार से काम करता है उस प्रकार से विभाग के बलबूते ही हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसका राजनीतिक लाभ लेने की बात है। जहां-जहां भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। हम विधायक प्राथमिकताओं में स्कीमें डालते हैं लेकिन उसके बावजूद विधायक प्राथमिकता का शिलान्यास करने के लिए वे नेता चले जाते हैं जिनकी जमानतें जब्त कर रखी हैं, वे वहां पर खड़े हो जाते हैं। उद्घाटन करने के लिए वे लोग खड़े हो जाते हैं। स्कीम किस गांव तक पहुंचनी चाहिए, किस गांव को उससे लाभान्वित करना चाहिए और किस मन्शा के साथ हमने उस स्कीम को डाला है, किन लोगों की मांग पर हमने उस स्कीम को डाला है, यह विधायक से ज्यादा दूसरा कोई आदमी नहीं जान सकता। लेकिन वहां पर विभाग को डायरैक्शन देने के लिए नेता वे खड़े हो जाते हैं जो नकारे होते हैं, हारे होते हैं इसलिए सभापति महोदय, इस विभाग के बारे में तो क्या, मुझे तो सरकार ही भगवान भरोसे चल रही है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, मैं जो कटौती प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं इनका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सभापति(श्रीमती आशा कुमारी): माननीय सदस्य, हंस राज जी, चर्चा में भाग लेंगें।

Contd..by Smt. AV.

29.3.2017/1545/AV/ए0जी0/1

श्री हंस राज : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे मांग संख्या 13 पर बोलने के लिए समय दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सिंचाई और सफाई जलापूर्ति एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसमें यहां दो-तीन स्कीमों का जिक्र करूंगा जो बहुत समय से चली हुई है और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। हमारा आयल, बंडतर, चीह, पंजेई और हिमगिरि का इलाका है जहां पर 3-4 सालों से एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चली हुई है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है और हमारी हिमगिरि और पंजेई पंचायतें सूखा क्षेत्र में आती हैं। पंजई, हिमगिरि और चीह में काफी दिक्कत होने वाली है इसीलिए वहां काम को थोड़ी रफ्तार दी जाए ताकि आने वाले

समय में लोगों को राहत मिले। हमारा बंजराड़ू तहसील मुख्यालय है और एस0डी0एम0 भी वहीं बैठते हैं। बंजराड़ू के लिए लड्डन, टेपा पंचायत से एक स्कीम आ रही है जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है और मेरी विधायक प्राथमिकता में भी थी। वह सैंक्शन हुई है और उसका टैंडर भी हो चुका है। उसका पिछले 1-2 वर्षों से काम चला हुआ है लेकिन उसमें मेरी यह सब्मिशन रहेगी कि जिस सोर्स से वह पानी टैप हो रहा है वहां उसके बीच में एक सुखराली नाला आता है। उसके ऊपर से ही वह पाइप लाइन आए और यह योजना 10-15 सालों के लिए सोचकर बनाई जाए क्योंकि इस योजना से हम भविष्य में काफी लोगों को लाभान्वित करवा सकते हैं। इसमें तीसा फर्स्ट, तीसा सेकिण्ड, बंजराड़ू, खुशनगरी, गवाड़ी और खखड़ी एक महत्वपूर्ण गांव है जहां पर पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। इसलिए खखड़ी, पंचायत बंजराड़ू के लिए भी कुछ किया जाए। मेरे बोलने का आशय यह है कि जो पाइप लाइनें आ रही है उसमें स्टोरेज टैंक ठीक बने। आगे जो पानी सबलैट किया जाए उसके लिए भी अच्छे स्टोरेट टैंक बने। साथ ही, हमारे लैंसवीं, भरारा, टिकरीगढ़ और देहरा पंचायत में पानी की व्यापक समस्या रहती है। अब आने वाला समय गर्मी का है इसलिए जिन पानी की स्कीमों में रिपेयर की जरुरत है तो वहां रिपेयर करवाई जाए। माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि पाइपें नहीं है, साकैट्स नहीं है या दूसरी जो व्यवस्थाएं रहती हैं उसकी

29.3.2017/1545/AV/ए0जी0/2

कमी से पानी बाधित न हो। कई बार हम गांव में प्लास्टिक से बांधते हैं। मैं भी आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट से सम्बंधित हूं क्योंकि मेरे फादर खुद पाइप फिटर है। उसमें इस प्रकार की छोटी-छोटी चीजें गांव के लोगों को काफी असुविधा देती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अभी से हाफ ईंच, पौनी ईंच और एक ईंची की पाइप्स को हमारे सलूणी में जो ऐक्सियन बैठते हैं, वहां के लिए सप्लाई हो। वह उनको आगे कोटी या बंजराड़ू के एस0डी0ओ0 को उपलब्ध करवाएं ताकि जून-जुलाई के महीने में जहां-जहां पर इक्विपमैंट्स या पानी की ज्यादा जरुरत पड़ेगी वह हम सप्लाई कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारा लोअर इलाका

जिसमें सिंचाई की योजनाएं भी हैं जैसे राजनगर, चकलू, चंडी, पलई इत्यादि है। कई उठाऊ सिंचाई योजनाएं शुरू हुई है जिसमें पेयजल योजना भी है जो हमारे लड़ोग से चंडी पंचायत में निकलती है और लास्ट बलधार और सुन्धार तक जाती है। इसमें टैंडर हुआ है और काम भी चला हुआ है लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए, वह नहीं है। यहां पर आफिसर्ज बैठे हुए हैं इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस बारे में थोड़ा आगे डायरैक्ट करें कि यह काम जल्दी-से-जल्दी हो। इसके अतिरिक्त हमारी कोहाल-सपरोट पंचायतें, कुठैड़, मसरूंड, दुलार और जुलाड़ा पंचायतों के लिए भी एक उठाऊ पेयजल योजना सपड़ाह से शुरू होनी है और इसमें भी मेरे ख्याल में टैंडर तक बात आ गई है। नाबार्ड से पैसा भी मिला है इसलिए यह जल्दी शुरू हो तो ठीक रहेगा।

सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अगला वक्ता श्री वर्मा द्वारा जारी

29/03/2017/1550/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः सभापति महोदय, मैं डिमाण्ड न0 13 "सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई" कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी बड़ी अच्छी हैं, अपनी क्षमता के अनुसार काम भी खूब करती हैं, ये बात मैं यहां भी कह रहा हूं और बाहर भी कहता हूं। सरकारी अधिकारी भी प्रयास करते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन तब भी यह लगता है कि कभी-कभी जिस कल्चर को हम नाम देते हैं- 'हिमाचल का कल्चर', वह कल्चर इतना खराब है, डॉ0 बिंदल जी कह रहे थे कि कई बार तो ऐसे-ऐसे लोग जाते हैं, जो अधिकारियों के टेबल पर मुक्के मारकर कहते हैं कि ये काम करो, कानून देखना बाद की बात है। मुझे लगता है कि कभी-कभी ये असमर्थ हो जाते हैं, जब ये कर नहीं पाते हैं। सभापति महोदय, मैं कुछ विशेष बिन्दुओं की ओर

माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा। मनाली, कुल्लू विधान सभा क्षेत्र के लिए सिंचाई की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना पर सन् 2011 में एक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। जिसको नाम दिया गया था - प्रीणी-बिजली महादेव लघु सिंचाई योजना और जिसकी डी0पी0आर0 पहले 399 करोड़ रुपये की बनी थी, लेकिन अब उसको रिवाईज किया गया है, जो लगभग 500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। जिसमें लैंड एक्वाजिशन के लिए 4 गुणा पैसा रखा गया है और बाकी व्यवस्था भी की गई है। एक और अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना जिससे 2 विधान सभा क्षेत्रों के लोगों का कल्याण होगा। इसको भी प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार तक बहुत गम्भीरता से ले जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ छोटी-सी सिंचाई योजना जो विधायक प्राथमिकता के माध्यम से ग्राम पंचायत पनगन हैं, वहां के कशेरी नाला से ले करके बढ़ा ग्राण पंचायत, ब्राण पंचायत तक जिसका कार्य पिछले कार्यकाल में प्रारम्भ किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि विभाग के इंजीनियर पता नहीं क्या काम करते हैं? उस समय उनसे कोई टेक्निकली गलती रह गई, आगे का काम हो गया, पीछे जो कुछ स्लाईडिंग पोर्शन था, वहां पर काम कोई अलग तरीके से होना था, बड़े पाईप के माध्यम से होना था, अब उसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। आगे पैसा खर्च हो गया है और स्लाईंडिंग पोर्शन के लिए धन की व्यवस्था करनी की आवश्यकता है, ताकि इन 4 पंचायतों के लिए सिंचाई की सुविधा हो सकें। इसके साथ बाड़ी,जैंडी, कटराईं ग्राम पंचायत तक

29/03/2017/1550/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

एक सिंचाई की नहर है, उस नहर से पानी जगह-जगह लोगों के घरों और सड़कों में जाता रहता है। उसकी मरम्मत पर पैसा भी खर्च किया गया है, लेकिन तब भी वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। उस ओर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेफ्ट बैंक में छाक्की-नगर से नथाण तक एक बहुत पुरानी सिंचाई की योजना हैं और इस सिंचाई योजना में भी जगह-जगह पर मरम्मत की आवश्यकता है। इसको भी विशेष तौर पर आप चैक करवा लें। जलापूर्ति की जहां तक बात है, स्वच्छ पानी चाहिए, लेकिन ये हम कहीं-कहीं कर नहीं पाते हैं। अभी गत 3-4 महीने पहले की बात है, जो हमारे टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों में ढ़क्कन नहीं है। कुल्लू शहर के साथ सेऊबा गांव के पास एक टैंक हैं, जिस

टैंक में किसी शरारती तत्वों ने ज़हर मिला दिया था। किसी तरह से पता चल गया और यदि प्रशासन तथा विभाग के अधिकारियों ने समय रहते पानी बंद नहीं किया होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सोलन गांव में पानी के नलके से पानी भरते-भरते एक सांप नलके से बाहर निकला और गांव के एक नौज़वान ने वह एक बोतल में डालकर लाया। उसने वह आई0पी0एच0 के अधिकारियों को दिखाया। उन्होंने कहा कि यह बात किसी को पता न चले, हम इसको ठीक कर देते हैं। इस ओर भी ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी ।

29/03/2017/1505/एन0एस0/ए0एस0/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर.....जारी।

मैं मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कुल्लू और मनाली के साडा क्षेत्र में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी माननीय जय राम जी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी लगभग 70 लीटर के हिसाब से मिलता है। नगर परिषद के अतिरिक्त इस सारे-के-सारे क्षेत्रों में इतने अधिक गैस्ट हाउस और होटल बन गए हैं कि एक-एक होटल 50 से 60 कमरों का है। उनके पीने के पानी की क्षमता 135 लीटर के आसपास बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम उस हिसाब से विचार नहीं करेंगे तो जो स्थानीय गांव के लोग को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्योंकि उनको पानी पूरा नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण होटल और गैस्ट हाउस हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो वहां पर फिटर तैनात है, उसको अगर वह शराब पीने वाला है तो शराब की बोतल दे देंगे और कोई 200 या 300 रूपये ज्यादा दूंगा, आप गांव के किसी व्यक्ति के घर का पानी तोड़ करके हमें पानी ज्यादा दे दे। इसमें ग्राम पंचायत बशोधी, मनाली गांव, शलीण, प्रीणी, जगतसुख तथा शणाग को इस दिशा में ठीक करने की आवश्यकता है और इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। सभापति महोदया, मैं एक और विषय ध्यान में लाना चाहूंगा। वर्ष 2013 में माननीय मुख्य मंत्री जी विंटर कार्निवल में मनाली आए थे तो उस समय एक

बात कही गई कि ओल्ड मनाली से ले करके आलू ग्राउंड और लैफ्ट बैंक में वाहन से ले करके जगतसुख तक एक सीवरेज योजना होनी चाहिए। आई0पी0एच0 विभाग ने लगभग 162 करोड़ रूपये की डी0पी0आर0 तैयार की है। यह घोषणा मुख्य मंत्री महोदय जी की है लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार के धन का प्रावधान नहीं हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा है तो अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अभी कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

सभापति महोदया, जहां तक शहरों की पानी की व्यवस्था की बात है। हम जहां पर रहते हैं, वहां पर ब्यास नदी साथ में बहती है। मेरे क्षेत्र में कई नदी-नाले हैं, रोहतांग की दाईं व बाईं पहाड़ियों पर बहुत बर्फ है। आज उस क्षेत्र में भी पीने के पानी की कमी हो रही है। मेरे क्षेत्र में मनालसू नाला से पानी आता है लेकिन फिर भी इस शहर के पीने के पानी को

29/03/2017/1505/एन0एस0/ए0एस0/2

ठीक करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ यहां पर पाईपों की बात सभी लोगों ने कही है कि पाईपें पिछले वर्ष जुलाई में आई हैं और इस साल के फरवरी में आई हैं। अभी 5-6 दिन पहले मैंने डिवीजन में फोन किया है, वे कहते हैं कि हमारे पास एक ईंच और सवा ईंच की पाईपें खत्म हैं और पाईपें कब आएंगी? लोगों को इस कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। विधायक प्राथमिकता की मैं अब ज्यादा कहानी नहीं सुनाउंगा, सिर्फ दो योजनाओं के बारे में बोलना चाहूंगा। एक योजना हलाण-I योजना जो लगभग 88 लाख की है। इसका काम वर्ष 2011 में प्रारम्भ हुआ था और अभी तक यह योजना ठीक प्रकार से तैयार नहीं हुई है। दूसरी, हलाण-II योजना वर्ष 2011 में लगभग 47 लाख रूपये की योजना का विधायक प्राथमिकता के तहत काम प्रारम्भ हुआ था और अब लगभग पांच वर्ष बीतने के बाद भी विभाग ने उत्तर दिया है कि वहां पर 75 प्रतिशत कार्य हुआ है। इस योजना की हालत भी खराब है। सभापति महोदया, दो योजनायें ऐसी थीं जो विधायक प्राथमिकता की थी। उनमें से नग्गर अर्चन्डी जाणा के लिए लगभग एक करोड़ रूपये की विधायक प्राथमिकता की योजना थी।

इसका शिलान्यास करने माननीय मुख्य मंत्री जी भी आए थे। माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी भी आईं थी। विधायक प्राथमिकता की यह मेरी योजना और मुझे ही इसकी सूचना नहीं थी। दूसरा, आपने किस प्रकार का शिलान्यास किया। रायसन-बागा बेंची की पीने के पानी की योजना जो कि मेरी विधायक प्राथमिकता की योजना लगभग तीन करोड़ की योजना है, उस योजना का मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई एवं जन-स्वास्थय मंत्री महोदया शिलान्यास करके आए हैं। ऐसा होता तो कई जगहों पर है। इन सब बातों को विधायकों के सम्मान के लिए ठीक करने की आवश्यकता है। साथ ही एक बहुत महत्वकांक्षी योजना जिसका नाम

श्री आर0के0एस0 द्वारा .....जारी।

29/03/2017/1600/RKS/dc/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर... जारी

पलचान से लेकर औट तक ब्यास नदी का तटीयकरण करना और इसमें साथ लगते नदी-नालों को भी शामिल करना है। आपका जवाब आया है कि 1,055 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. अभी हमने केंद्र सरकार को भेजी है। अब प्रदेश सरकार के अधिकारी और हम भी जो कर सकते हैं, वह करेंगे। लेकिन इसे बार-बार फोलो-अप करने की आवश्यकता है। दूसरा, गांव के साथ लगते जितने नदी-नालें हैं, ये सारे जो छोटे-छोटे नाले हैं, इन सब नालों का ग्राम पंचायत के द्वारा सर्वेक्षण करवाकर फ्लड प्रोटैक्शन के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। कुछेक ऐसे शहर हैं जो ब्यास नदी के साथ लगते हैं। पहले यहां प्रोटैक्शन का काम हुआ था। वहां पर अभी भी खतरा है। 15 मील के क्षेत्र में कई जगह क्रेट उखड़ गए हैं। कलाथ में जहां गर्म पानी निकलता है वहां ब्यास नदी कभी भी गांव को नुकसान कर सकती है। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से ईमानदारीपूर्वक सबकी बातों को सुनती हैं और समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करती हैं। लेकिन जो नीचे के कल्चर में रहे हुए लोग हैं वे कभी-कभी लगता है कि इस प्रकार की हुड़दंगबाजी करते हैं। अभी मैं एक जगह गया था और मैंने कहा कि मुझे पाइप चाहिए। मुझे कहा गया कि पाइप नहीं हैं। दूसरे दिन गांव

के 15-20 लड़के आए, उन्होंने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया और उसके फोन करने पर 20 पाइपें हमारे वहां पर पहुंची। एम.एल.ए. के बोलने पर तो पाइपें नहीं आई लेकिन उस व्यक्ति के फोन करने पर पाइपें आ गई। सरकारें तो बदलती रहती हैं। माननीय मंत्री जी आखिर में मैं कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए एक बात कहूंगा। जब कोई विधायक फोन करता है, माना मीटिंग में है, कोई बात नहीं वे छोटा सा मैसेज भी तो कर सकते हैं या फिर कॉल बैक करने का कष्ट भी कर सकते हैं। यह कहीं-न-कहीं चीजें होती हैं। उसी का परिणामस्वरूप है कि श्री रवि ठाकुर जी एक बहुत बड़े अधिकारी के खिलाफ प्रीवलेज ला रहे हैं। शायद लोकतंत्र में करना तो हमको ही है और ये विधायक तो कुछ भी कहते रहेंगे। साढ़े चार वर्षों में पीने के पानी के क्षेत्र में जो करना चाहिए था वह काम संतोषपूर्ण नहीं हुआ है। सभापति महोदया, इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद।

29/03/2017/1600/RKS/dc/2

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कंवर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः सभापति महोदया, जो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या-13 पर रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। पूरे प्रदेश के अंदर पीने के पानी की समस्या ने भंयकर रूप धारण कर लिया है। एक तो बारिशें समयानुसार नहीं हो पा रही है। दूसरा, इसका मुख्य कारण एडमिनिस्ट्रेटिव फेलयोर है। अपनी विधान क्षेत्र के अंदर जब हम पहली बार चुनकर गए थे तो वहां पर बहुत ज्यादा समस्या पीने के पानी की होती थी। मैंने अपने कार्यकाल में 9 से ज्यादा पीने के पानी की स्कीम्ज बनाई। आदरणीय धूमल जी के आशीर्वाद से उस समय सैंकडों हैंडपम्पज़ लगे। हम इस समस्या का समाधान पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन उस समय लोगों को हर रोज पानी मिलता था। पिछले साढ़े चार वर्षों से क्या हो रहा है? मेरी जो पहली पीने के पानी की स्कीम 17 पंचायतों के लिए बनी हैं, ऊना से लेकर सोलहसिंगी धार तक पानी पहुंचाया गया है। उसका डिस्ट्रिब्यूशन चेंज होना था। उसके लिए पैसे का प्रावधान भी हो गया था। लेकिन सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद उसके टैंडर हुए। टैंडर होने के बाद जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गए तो भूमि

पूजन भी किया गया। लेकिन चार वर्षों से चार करोड़ रुपये का कार्य पूरा नहीं हो पाया। ठेकदार ने 3-4 लोग रखे हैं। अब जैसे ही फसल कट जाएगी तो 4-5 लोग काम में लगा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा। फिर फसल का काम आ जाएगा।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

29.03.2017/1605/SLS-DC-1

श्री वीरेन्द्र कंवर ... जारी

मुख्य कारण यह है कि हम 4 सालों में उसकी डिस्ट्रिब्यूशन नहीं बदल पाए। मैडम, उसमें हमने बहुत पैसा दिया है, अगर आप देखने के लिए नहीं जा सकती हैं तो कम-से-कम किसी अधिकारी की ड्यूटि लगाएं कि वहां कोई मीटिंग तो लो, फीड बैक तो लो कि जो टैंडर दिया है, वह क्यों पूरा नहीं हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऊना से लेकर वहां तक राइजिंग मेन बिछी है तो वह बार-बार क्यों टूट रही है। आप उसकी इंक्वायरी करवाइए। विभाग ने जो टैक्निक एडवाइज उसमें देनी थी, वह समय रहते क्यों नहीं दी गई ताकि वह स्कीम प्रॉपर तरीके से बन पाती? हम पैसे का प्रावधान तो कर रहे हैं लेकिन बाकी काम तो विभाग ने करना है, वहां पर विधायक की टैक्निकल गाइडैंस नहीं चलेगी। यह समस्या बार-बार आ रही है। स्कीम 3 दिन चलती है और चौथे दिन उसका पाईप खुल जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप उसका समाधान एकमुश्त करिए ताकि वह पाईप बार-बार न खुले। जो टैंडर 4 वर्षों से लगने के लिए है उसके न लगने के लिए कौन जिम्मेवार है?

इसी तरह से हमारी पीने के पानी की स्कीम रामगढ़धार है। उसकी भी वही हालत है। वह स्कीम रामगढ़धार के लिए पीने का पानी पूरा नहीं कर पा रही है। वहां छोटे-छोटे गावों के लिए अलग पेयजल योजनाएं बन गई हैं। मुख्य मंत्री जी वहां गए और वहां पर 80 से ज्यादा हैंडपंपों की घोषणा करके आ गए। मैं कहना चाहता हूं कि अब इस पांचवें साल में

ही 4-5 हैंड पंप वहां लगे हैं लेकिन एक भी हैंड पंप मेरे वहां पर नहीं लगा। जो लगे हैं, जिनका ज़िक्र पूर्व वक्ता कर रहे थे, वह लोगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं लग रहे हैं। मुख्य मंत्री जी जब वहां पर जाते हैं तो एक शब्द वहां प्रयोग करके आते हैं यानी मकरझंडुओं की आवश्यकता के अनुसार वहां काम हो रहे हैं। लोगों को तो पीने का पानी चाहिए। जितने भी कुटलैहड़ में कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, सभी ने टैंक से सीधी लाईन ले ली है लेकिन गांव में बुरा हाल है। लीडर्ज़ के घरों में पानी आता है लेकिन बाकी गांव में पानी नहीं आता। विधान सभा क्षेत्र में यह स्थिति मेरे है। मेरे यहां एक करोड़ की लागत से एक नई स्कीम चरौला

29.03.2017/1605/SLS-DC-2

नगर शागडी नाम से बनाई गई है। गांव में उसका टैंक बना है लेकिन उस टैंक तक पानी नहीं पहुंचता। विभाग के छोटे कर्मचारियों ने बताया कि जितनी पॉवर की मोटर लगनी थी, उतनी नहीं लगी है। जब हम आपके अधिकारियों से यह कहते हैं, वह कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल ठीक किया है, आप झूठ बोल रहे हैं; पानी तो वहां पर पहुंचता है। वहां पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यह ऊना क्षेत्र की समस्या है।

माननीय सभापति जी, यहां पर एक विषय बार-बार आया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी ओर ध्यान दें। मोटरें महीने में कितनी बार खराब होती हैं? एक महीने में 8-8 बार मोटर खराब हो रही है। उस रिपेयर की कीमत कितनी है? यह एक मोटर माफिया पैदा हो गया है। वह बार-बार मोटरें खराब कर रहे हैं। मोटर में अगर वैसे ही थोड़ी-सी खराबी या इलैक्ट्रिकल फेल्योर हुआ तो उसको भी खराबी के खाते में डाल देते हैं। वहां कोई चैक करने वाला नहीं है और सारा काम राम भरोसे चला हुआ है। मैंने प्रश्न लगाया था कि पिछले 4 वर्षों में आपने कितना सामान खरीदा है, कितनी सप्लाई ली है और कितने नट-बोल्ट खरीदे तथा कितनी बार रिपेयर और मेंटेनैंस हुई? लेकिन उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी धनराशि की स्कीम नहीं है उससे 4 गुणा ख़र्च सप्लाई का हो रहा है। जब गांव में पाईप टूटती है तो विभाग लोगों से जाकर

कहता है कि आप यह सामान लेकर आओ, तभी आपकी पाईप जुड़ेगी। कर्मचारी वहां पर पहुंचते तक नहीं हैं। सप्लाई केवल कागज़ों में आती है और वहीं खत्म हो जाती है। यह इस विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा धंधा चला हुआ है। माननीय सभापति जी, मैं एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जारी ...श्री गर्ग जी

29/03/2017/1610/RG/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर---क्रमागत

सभापति महोदया, मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक चंगर सैणी स्कीम थी जो मैंने विधायक प्राथमिकता में दी थी और माननीय धूमल जी ने पिछली सरकार में उसका शिलान्यास किया था। उसके ऊपर लगभग एक करोड़, 70 या 80 लाख रुपये खर्च हुआ और वह स्कीम कम्पलीट कर दी गई। उसको बहुत सारी आबादी को पानी दिए बगैर ही कम्पलीट कर दिया गया। पैसा वापस नाबार्ड में चला गया। मैंने जब अधिकारियों से पूछा कि यह आपने कैसे कर दिया? तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। आज वह स्कीम बन गई, पानी वहां आ रहा है, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं, कई किलोमीटर पर आबादी ऐसी है जहां पीने-का-पानी नहीं मिल रहा है। वैसे ही चंगररोड़ा हमारे यहां एक सिंचाई की स्कीम थी। उसके ऊपर एक करोड़, 60 लाख रुपये खर्च हुआ। लेकिन आज तक खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया। जब बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, मैं पूछता हूं कि वह कम्पलीट क्यों नहीं हुई, तो कहते हैं कि बस थोड़ा सा फर्क रहा है, बस हम पानी दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अधिकारी मौके पर जाकर यह देखना नहीं चाहता कि वहां खेतों तक पानी पहुंच रहा है या नहीं। उसी तरह हैण्ड पम्पज के ऊपर भी हुआ, पहले स्टेट लेवल पर टैण्डर लगते थे। फिर कहा कि इसको कैन्सल करो, दो-तीन साल यही रिहर्सल चलती रही। फिर कहा कि डिवीजन लेवल पर टैण्डर लगाओ। जब डिवीजन के ऊपर लगाया, तो पहाड़ी क्षेत्र का अलग रेट होगा और वही मैदानी क्षेत्र का रेट हो जाएगा। अब इस समय लोग हैण्ड पम्पज लगाने से डर रहे हैं। अब कहा गया कि डिवीजन लेवल पर नहीं, सर्कल के लेवल पर टैण्डर लगाओ, चीफ इंजीनियर लेवल पर

लगाओ। तो इस तरह ये चार वर्ष टैण्डर के प्रोसैस में ही चलते रहे और आज जो हमारी पीने-के-पानी की समस्या है, वह जस-की-तस है।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल) :आप क्या चाहते हैं?

श्री वीरेन्द्र कंवर : हम कुछ नहीं चाहते, केवल इतना चाहते हैं कि कम-से-कम आपके टैण्डर तो लगें। आप लगाओ, डिवीजन या सब-डिवीजन किसी भी लेवल पर लगें, हैण्ड पम्पज तो लगें। लेकिन हैण्ड पम्पज ही नहीं लग रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि लोगों को पीने-का-पानी मिले। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, कभी-कभी सी.पी.एस. साहब की भी सलाह ले लिया करें। ये अच्छी सलाह देते हैं।

29/03/2017/1610/RG/AG/2

सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में आज बहुत सारे ट्यूब-वैल्ज लगे हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है। आपने वाटर गाड्र्ज रखे। वाटर गाड्र्ज के लिए आपने बजट में कितना प्रावधान किया? आपने उनकी 5/-रुपये डेली बढ़ा दी। जिससे सारा दिन काम ले रहे हैं उसकी मात्र 5/-रुपये डेली बढ़ाई। उनका 150/-रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया और 1500/-रुपये उनकी तनख्वाह कर दी गई। आप बेरोजगारी के नाम पर करोड़ो रुपये उधार लेकर लूट शुरू करवा रहे हैं। उसकी बजाय तो अच्छा होता कि आप सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को वाटर गाड्र्ज ही दे देते। अगर आपने वाटर गाड्र्ज दिए होते, तो कम-से-कम पीने-के-पानी की समस्या का समाधान तो हो जाता।

सभापति महोदया, आज बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं क्योंकि अगर आप ट्यूब-वैल पर देखेंगे, तो कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जे.ई. के घर चले जाएंगे, तो आपको वहां दो-तीन लोग मिल जाएंगे, आप एस.डी.ओ. या ऐक्सीयन के घर चले जाएंगे, तो 4-5 लोग हैं, कोई दूध लाने के लिए लगाया हुआ है, कोई कुत्ते को घुमा रहा है, कोई सब्जी ला रहा है और कोई गाड़ी धो रहा है, अलग-अलग काम के लिए कर्मचारी उन्होंने रखे हुए हैं। मैं यहां कह रहा हूं, मैडम, आप आदेश दें और आप पता करें कि कितने कर्मचारी घरों में घूम रहे हैं। वे काम नहीं करते, अधिकारी उनसे अपने घर का काम करवा रहे हैं। मेरे यहां सिंचाई के ऐसे दो ट्यूब-वैल हैं जो तीन वर्षों से बिल्कुल तैयार हैं एक

लोअरलाणल और दूसरा डगेड़ा में है। यह ट्यूब-वैल कम्पलीट हैं, लेकिन आज तक विभाग ने उनको चालू नहीं किया है। मैं पिछले साल से बार-बार कह रहा हूं कि आप इनको शुरू करिए, तो कहते हैं कि थोड़ा सा रह गया है, अभी मोटर रखनी है, अभी यह करना है, लेकिन किसी चीज की कोई जिम्मेवारी भी होती है।

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2017/1615/MS/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी---------

उसके ऊपर एक करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन वह मशीनरी वैसी-की-वैसी खड़ी है और बाद में रखी-रखी खराब हो जाएगी। मेरा निवेदन है कि आप कम-से-कम इन्सपैक्शन तो कीजिए कि यह स्कीम इतने समय में तैयार होनी थी तो क्यों तैयार नहीं हुई। अगर तैयार हुई है तो इससे क्यों पानी खेत और घरों तक नहीं पहुंच पाया।

मंत्री महोदया, आपसे मेरा एक और निवेदन है। मेरी एक रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्कीम बनी थी जोकि हमारे अप्पर कुटलैहड़ के लिए पायलट प्रोजैक्ट था और उस पर 20 करोड़ रुपया खर्च होना था। हालांकि अब वह मेरा क्षेत्र चला गया है तो सुहानी-टकोली के साथ वे दो डैम वहां बनने थे। वे डैम बन भी गए। एक डैम सबुर खड्ड के ऊपर बन गया है। वहां पर पाइपें भी आ गई हैं और बिछनी भी शुरू हो गई हैं लेकिन आप जब से मंत्री बनी हैं वे पाइपें वहीं-की-वहीं जंग खा रही हैं। फिर कहा कि इसमें 10 करोड़ रुपये .(व्यवधान). निश्चित रूप से यह आपके ध्यान में नहीं होगा क्योंकि आपने कभी इन सारी चीजों की समीक्षा ही नहीं की। अब वह डैम बना हुआ है तो आपका विभाग उसमें पानी क्यों नहीं भर पाया? उस पर 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, इसका कौन जिम्मेवार है? हम सबकी जेब से टैक्सिज के रूप में वह पैसा गया हुआ है, वह पब्लिक मनी है और उससे 15000 कनाल जमीन सिंचित होनी थी। विभाग ने तीन साल के बाद एक और ऐस्टीमेट बनाकर दे दिया कि 10 करोड़ रुपया कुटलैहड़ में लगेगा और 10 करोड़ रुपया चिन्तपूरनी के एरिये में लगेगा। हमने अपनी विधायक प्राथमिकता में इसको दुबारा डाला। 10 करोड़ रुपया आए हुए 2 साल हो गए लेकिन 2 साल के बाद पिछले साल आदरणीय मंत्री जी आपने सिर्फ 50

लाख रुपया दिया। जो 10 करोड़ रुपये में काम होना है तो 50 लाख रुपये में तो विभाग वाले टैण्डर भी नहीं लगाते हैं और वह टैण्डर भी नहीं लगा। अब वह सफेद हाथी बनकर के वैसा-का-वैसा खड़ा है। अब इतना पैसा खर्च होने के बाद भी हमारी स्कीमें वैसी-की-वैसी खड़ी हैं। क्या हम ऐसा मानें कि सरकार बदलने की उनके ऊपर यह मार पड़ी है? यदि ऐसा है तो कुलदीप जी के ऊपर किस चीज की मार पड़ रही है? इनको तो चुनावों में फिर मार पड़ जाएगी, जब जनता पूछेगी कि

29/03/2017/1615/MS/AG/2

ये स्कीमें क्यों पूरी नहीं हुईं जिन पर पिछले सात सालों से काम चला हुआ है। मैं तो अपनी मार झेल लूंगा लेकिन ये तो आपकी ही पार्टी के सदस्य थे। ये कैसे मार झेलेंगे? मेरा यह कहना है कि यह विभाग की निष्क्रियता है और आज इसके लिए कोई जिम्मेवार है, ऐसा नहीं लगता है।

इसी तरह से हमारे यहां एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बना था जोकि स्वां नदी की ट्रिब्यूटरीज को चैनेलाइज करने का था। उसमें मेरा अधिकांश क्षेत्र आता है। हालांकि बहुत सारी खड्डे हैं लेकिन सरकार की इतनी मार पड़ गई कि बाकी जगह तो बहुत कुछ हो गया लेकिन मेरी एक भी खड्ड चैनेलाइज नहीं हो पाई यानी जो मुख्य खड्डे हैं वे एक भी चैनेलाइज नहीं हो पाईं। आज इस तरह का भेदभाव पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यह सरकार आम आदमी के लिए पीने-का-पानी तथा खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है इसलिए यह जो कटौती प्रस्ताव है, मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूं।

29/03/2017/1615/MS/AG/3

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर: सभापति महोदया, जलापूर्ति, सिंचाई एवं सफाई का जो विभाग है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह जहां हमारे जीवन और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा

हुआ है वहीं यह सभी वर्गों की इकॉनोमी से भी जुड़ा हुअर है। मुझे लगता है कि हमें आज पीने-के-पानी की क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का चेलेंज है। क्योंकि अब समय आ गया है कि लोग क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी वॉटर चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में चैलेंज क्वालिटी वॉटर का होगा। हमारे जो सोर्सिज हैं वे दिन-प्रतिदिन पॉल्यूट होते जा रहे हैं। चाहे उसका कारण औद्योगिकीकरण ले लीजिए या जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको वजह मान लीजिए। जिस तरह से सोर्सिज पॉल्यूट हो रहे हैं उनको ट्रीटमैंट की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए जो क्वालिटी वॉटर है उसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

29.03.2017/1\620/जेके/एएस/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः----**जारी**------

हमारे जितने भी माननीय सदस्यों ने इस डिमांड पर चर्चा की, कट मोशन जो लाया गया है, इसमें मुझे लगता है कि 90 प्रतिशत जो बात हुई है वह सिर्फ पेयजल पर हुई है। May be more than 90% बाकी जो इरिगेशन है, सीवरेज़ है, फ्लड प्रोटैक्शन है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। इससे पता लगता है कि यह इकट्ठा विभाग होने की वजह से जो दूसरे महत्वपूर्ण सैक्टर्ज हैं, जो हमारे किसानों की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ इरिगेशन है उसके बारे में हम कितना सोच पाते हैं और हमारा विभाग इसके बारे में कितना सोच पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लो हमारी तीन स्कीमें हैं, एक शहर की वॉटर सप्लाई है, एक गांव की वॉटर सप्लाई है और एक इरिगेशन स्कीम है। कहीं मान लो तीनों स्कीमों की पम्पिंग मशीनरी सड़ जाए जैसे जब पीक सीजन होता है उसमें नॉर्मली मोटर सड़ जाती है। हमारे जो इंजीनियर्ज़ हैं उनका सबसे पहले फोकस शहर की वॉटर सप्लाई को ठीक करने में होता है, उसके बाद गांव की वाटर सप्लाई ठीक करते हैं और उसके बाद इरिगेशन की मोटर ठीक करते हैं । जहां ज्यादा जागरूक लोग हैं, अगर गांव के लोग ज्यादा जागरूक हैं

तो वे अपना प्रैशर डाल करके चाहते हैं कि हमारा काम पहले हो। फिर होता क्या है कि वह इतनी बेढंगी बात हो जाती है कि वह कभी इधर को भागते हैं और कभी उधर को भागते हैं और हम जस्टिस किसी भी वर्ग के साथ नहीं कर पाते हैं। जब तक हम इरिगेशन की मोटर ठीक करते हैं तब तक हमारा जो पीक सीज़न होता है, जिस समय फसलों के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब तक वह सीजन निकल जाता है। कई बार 15-20 दिन लग जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है जैसे कि हम कोई प्रोजैक्ट इम्पलीमैंट करते हैं उसकी तीन स्टेजिज़ होती हैं। सबसे पहले प्लानिंग इन्वैस्टिगेशन की है और डी0पी0आर0 बनानी है। डी0पी0आर0 बना करके उसको फंडिंग एजैंसी को स्पोंसर करना और उसको फंड्ज़ स्वीकृत करवाना है। पहली फेज़ यह है। दूसरी स्टेज क्वालिटी एग्जिक्यूशन और टाईमली एग्जिक्यूशन है।

9.03.2017/1\620/जेके/एएस/2

तीसरी स्टेज जब स्कीम बन करके तैयार हो गई तो जनता को हेंडओवर करके उसको मेंटेंन करके सर्विसिज़ डिमांड के मुताबिक लोंगो को देना है। सबसे ज्यादा जो हमारी पहली स्टेज प्लैनिंग इन्वैस्टिगेशन की और डी0पी0आर0 तैयार करने की है, वह सबसे ज्यादा वीक है क्योंकि हम उसके लिए उतना टाईम ही नहीं दे पाते हैं हम दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हैं। हमारे इंजीनियर्ज़ तो मैक्सिमम इन्फोर्मेशन देने में व्यस्त रहते हैं। कभी हैड ऑफिस से इन्फोर्मेशन आ गई, कभी स्टेट गवर्नमैंट से और कभी सेन्टर गवर्नमैंट से। जो विभाग को काम करना है, उसमें वे बहुत कम समय दे पाते हैं। कोई इनोवेशन की बात हो, नया आइडिया हो, रिसर्च की बात हो, उसमें समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि वे नॉर्मली ओवर बीज़ी हैं। डी0पी0आर0 समय पर नहीं बनती है। हमारी माननीय मंत्री महोदया बहुत अच्छी हैं और सभी इनका बहुत सम्मान करते हैं और मैं भी इनका बहुत ही सम्मान करता हूं लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इनकी ज्यादा गलती न होने के बजाय, मैं नहीं मानता कि अकेले मिनिस्टर ही उनके लिए जिम्मेदार है, इनसे आगे भी पूरा सिस्टम है,

डिपार्टमैंट है। जो रिजल्ट्स हैं वे फील्ड में नहीं आ रहे हैं। उससे लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए सभी सम्माननीय विधायकों ने यहां पर रोष प्रकट किया है कि बहुत बुरा हाल है, डिपार्टमैंट खत्म हो गया है। लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल है। इसमें कई बार एग्जिक्युशन टाईम पर नहीं होती है या कई बार विभाग भी कह देता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है तो हम कैसे टेंडर करें? डी0पी0आर0 के बाद वर्किंग एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके लिए स्टाफ नहीं है यह भी बिल्कुल सच है। उसको समय लगता है और जो फंडिंग का शिड्यूल होता है उसके मुताबिक हम एग्जिक्युशन भी नहीं करवा पाते हैं, जो तीन साल में स्कीम कम्पलीट होनी होती है। नॉर्मली 5-5, 6-6 साल में कम्पलीट हो रही है। कॉस्ट एस्कलेशन भी हो जाती है और जो फैसिलिटी हमने तीन साल में देनी थी वह 6-7 साल बाद देते हैं। उससे भी लगता है कि एक प्रकार का क्राईम है। जो तीन साल में हमने लोगों को सुविधा देनी थी वह 6-7 साल बाद दे रहे हैं। उसके बाद मैंटिनेंस की बात आ जाती है, जैसे कि

29.03.2017/1\620/जेके/एएस/3

हमारा स्टाफ रिटायर हो रहा है, चाहे आप पम्प ऑप्रेटर की बात ले लीजिए, छोटा स्टाफ है लेकिन अगर वह रिटायर होता है तो उसकी पोस्टें नहीं भरी जाती हैं। उसमें जो आजकल आऊटसोर्स का माध्यम लिया हुआ है, हम आउटसोर्स एक साल के लिए कर रहे हैं। तो एक साल बहुत कम समय है। एक साल में क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है वह अपना एक साल टॉसिंग में निकाल देता है। कभी मोटर खराब हो रही है उसको ठीक करवाते हैं। दो-चार महीनें ऐसे ही निकल जाते हैं और तब तक एक साल हो जाता है। स्कीम जब वह हेंड ओवर करता है तब तक स्कीम की स्थिति और ज्यादा गम्भीर हो जाती है । अगली बार नया ठेका लेंगें । तो आऊटसोर्सिंग तो बहुत ही विश्वसनीय फर्म हो उसको देनी चाहिए। अगर यह ठेका देना ही है तो कम से कम यह पांच साल तक का होना चाहिए क्योंकि उस फर्म को पता हो कि मैंने यह स्कीम पांच साल तक चलानी है लोगों को यह सुविधा देनी है। वह एक साल तो जैसे-तैसे निकाल देते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

29.03.2017/1625/SS-AS/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर क्रमागतः

एक तो यह कम-से-कम पांच साल के लिए होनी चाहिए और इसके लिए कोई बहुत ही इंटेग्रिटी का कंट्रैक्टर हो। उसके लिए हमें कंडीशन्ज़ स्ट्रिक्ट करनी चाहिएं कि वे लोग इल्लीजिबल होंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ताकि वे कम-से-कम स्कीम का भट्ठा न बिठाकर जाएं। इस ढंग से हमें कम-से-कम पांच साल के लिए आउटसोर्स की बात करनी चाहिए और अच्छे ठेकेदार को देनी चाहिए।

इसके बाद इरीगेशन की बात ले लें। हमारे पास स्टाफ की कमी है या और कुछ भी कह लीजिए। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में डी0पी0आर0 पिछले साल केन्द्र सरकार को भेजनी थी लेकिन हम timely as per norms नहीं भेज पाए। कुछ भेज दी हैं। परन्तु जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सिज़ की गाइडलाइन्ज़ थीं, जो उनके प्रि-रिक्विजिट्स थे, उनको हम मीट विद नहीं कर पाए। तो हमारी कोई भी स्टेट की स्कीम पिछले साल प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में एप्रूव नहीं हुई और मुझे लगता है कि इस साल भी एप्रूव नहीं हो पाई है। यह भी एक कारण है कि हम इरिगेशन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हम एक बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ कर करेंगे।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

ऐसे ही हम अगली बातें ले लें। मैडम मिनिस्टर ने कहा था कि हम टैंकस में लॉक एंड की सिस्टम कर रहे हैं। यह फैक्ट है और नॉन-पॉलिटिकल बात है कि हमारे एरिया में कम-से-कम जोकि पहाड़ी एरिया है 20-25 परसैंट बने हुए स्टोरेज़ टैंकस की स्लैब डैमेज हो चुकी

है। पहले तो हमारे जितने भी स्टोरेज टैंकस डैमेज्ड हैं, इंटेक हैं, फिल्टर्ज़ हैं या तो वे फंक्शनल नहीं है या लगे ही नहीं हैं तो उन्हें कम-से-कम इन्हें इन ऑर्डर करें। उसके बाद ही टैंकस की लॉक एंड की अरेंजमैंट का कोई फायदा हो सकता है। सबसे पहले जो स्लैब डैमेज हुई है उसको रिस्टोर करें। एक

29.03.2017/1625/SS-AS/2

हमारे सोर्सिज़ जिनको हम स्प्रिंग्ज़ सोर्सिज़ या चश्मा कहते हैं, उनको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। परन्तु 20-25 परसैंट केसिज़ में यह होता है कि जो हमारे स्प्रिंग्ज़ सोर्सिज़ हैं जब बरसात का समय होता है तो उस समय वे खड्डों के साथ सब-मर्ज़ हो जाते हैं। खड्डों के साथ ही हमारे स्प्रिंग्ज़ हैं। एक किस्म से वह नाला सोर्स बन जाता है। इसलिए उन स्प्रिंग सोर्सिज़ के ट्रीटमैंट की ज़रूरत है। यह देखना पड़ता है कि वे कहीं बरसात में सब-मर्ज़ तो नहीं हो रहे। कहने का मतलब यह है कि क्वालिटी वाटर देने के लिए अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक आस्पैक्ट पैसा भी है। पैसा होने के साथ-साथ मुझे लगता है कि अगर हम हर साल ट्रीटमैंट करें तो उसको पूरा करने में चार-पांच साल लगेंगे। हम हर जगह प्रॉपर ट्रीटमैंट करें। इसके लिए पैसे के साथ-साथ टाइम भी चाहिए। उसके अतिरिक्त स्टाफ भी पूरा चाहिए। एक और बात है। हम नॉर्मली पीने के पानी की बात ले लें। हम ओवर हैड टैंक बनाते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण इश्यु है। कई बार हम ओवर हैड टैंक 10 हजार लीटर कैपेसिटी का बना देते हैं। वह इतना बड़ा होता है कि ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे इसके ऊपर कोई गड़वी रख दी है। मैं कहता हूं कि अगर ओवर हैड टैंक बनाना है, खर्चे में कोई ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कम-से-कम ओवर हैड टैंक की कैपेसिटी 50 हजार लीटर होनी चाहिए। उसमें खर्चा बराबर आयेगा। जो 10 हजार कैपेसिटी का ओवर हैड टैंक बनाते हैं इसको एवॉयड करना चाहिए। ऐसे ही डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जब हम नई स्कीम ऑगमैंट करते हैं और रिमोट एरिया के गांव के लास्ट बेनिफिशरी को पानी नहीं मिलता है तो बड़ा बुरा लगता है। जब तक स्कीम नहीं बनी तो कोई बात नहीं। लेकिन जब स्कीम को ऑगमैंट कर दिया, इम्प्रूव कर दिया और करोड़ों

रुपये खर्च कर दिये लेकिन रिमोट एरिया के कॉनर पर बैठे बेनिफिशरी को पानी नहीं मिलता है तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हमसे जवाब नहीं दिया जाता कि स्कीम बन गई है, अब तो इसके बाद कुछ नहीं होना क्योंकि सब कुछ खर्चा हो गया है। उसके लिए प्रत्येक सैक्टर में प्रत्येक हैबीटेशन के लिए स्टोरेज़ टैंक इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जितने हों तो अच्छा रहेगा। सैक्टर स्टोरेज टैंक होते हैं। आई0पी0एच0 ने काफी इम्प्रूव किया है। परन्तु अगर सैक्टर स्टोरेज टैंक हर

29.03.2017/1625/SS-AS/3

हैबीटेशन पर होगा तो इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन होगी। साथ-साथ में हमने कई बार देखा है कि मान लो दो किलोमीटर पाइप बिछा दी। दो या चार फैमलीज़ हैं वहां आधे इंच की पाइप बिछा देते हैं। मेरे हिसाब से वहां पाइप पौने इंच यानी मिनीमम 20 एम0एम0 की होनी चाहिए क्योंकि वहां चांसिज़ हैं कि और ज्यादा पापुलेशन हो जायेगी। इसलिए डिस्ट्रिब्यूशन के लिए आधा इंच की पाइप नहीं यूज करनी चाहिए। यह सिर्फ पसर्नल कनैक्शन के लिए होनी चाहिए। डिस्ट्रिब्यूशन के लिए मिनिमम 20 एम0एम0 डाया की पाइप होनी चाहिए ताकि वहां पर और लोगों की सैटलमैंट होने पर बार-बार पाइप न उखाड़नी पड़े और यह शिकायत न हो कि पानी नहीं मिला है। इसके अलावा पम्पिंग मशीनरी है। वह इतनी आउट डेटिड हो गई है कि उसकी मैंटीनेंस कॉस्ट नई मशीनरी की कैपिटल कॉस्ट से भी ज्यादा हो गई है। मेरा यही आग्रह है कि फेज़ड मैनर में जो पम्पिंग मशीनरी 15-16 साल सर्व कर चुकी है उनकी रिप्लेसमैंट होनी चाहिए ताकि बार-बार मशीनरी डैमेज न हो और साथ-साथ में जो बिना वजह खर्चा हो रहा है वह भी न हो। आउटसोर्स पर बात हो गई। ट्रीटमैंट और स्प्रिंग सोर्सिज़ की बात हो गई।

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2017/1630/केएस/डीसी/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी----

शुरू में जो प्लैनिंग एण्ड इन्वैस्टिगेशन और डी0पी0आर0 की बात थी तो मैं कहता हूं कि जो हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को फंडिंग के लिए प्रोजैक्ट्स स्पाँसर करने हैं, उसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले उसकी फीज़िबिलिटी स्टडी करवाएं। ऐसे मैंने दो प्रोजैक्ट्स डाले थे। वो मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट्स बनेंगें, हमने एम.एल.ए. प्रायोरिटी में भी डाले थे। सिर्फ उसकी फिज़िबिलिटी स्टडी करवा कर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सिज़ को फंडिंग के लिए स्पाँसर करना था। लगभग दो साल हो गए हैं अभी तक उसकी मॉडल स्टडी, फीज़िबिलिटी स्टडी स्टार्ट भी नहीं हुई है। प्रोजैक्ट्स के नाम है first is, Irrigation Project through construction of dames on Lohand, Mahadev , Chikni and Kundlu Khud to provide irrigation facility in the down side command area of Nalagarh valley. दूसरा है, Irrigation Project through construction of series of dames on Ghambhar Khud for right side and left side command area of that Khud in Nalagarh and Arki. ये नालागढ़ और अर्की चुनाव क्षेत्र में आएगा, ये दो प्रोजैक्ट्स हैं। तो दो प्रोजैक्ट्स की अगर हम मॉडल स्टडी करवाएं, ये चार-चार, पांच-पांच सौ करोड़ के प्रोजैक्ट होंगें और इनसे कम से कम 7-8 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी तो बहुत बड़ी क्रान्ति आएगी। जमीन बहुत उपजाऊ है परन्तु इरिगेशन फैसिलिटीज़ न होने की वजह से किसान लाचार हैं । मैं चाहता हूं कि इसके लिए मॉडल स्टडी जल्दी स्टार्ट करके, प्रदेश सरकार ने सिर्फ गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेजना है, फंडिंग पूरी की पूरी सैंटर गवर्नमैंट से होनी है। तो जल्दी से जल्दी इसकी डी.पी.आर. बनाएं। इसके अलावा इस डिमांड के बारे में जो महत्वपूर्ण इशू है, सबसे बड़ी जो आज के दिन की डिमांड है, जितने भी हमारे ग्राऊंड वाटर है, उसकी डैप्रीशिएशन हो रही है, ग्राऊंड वाटर डाऊन जा रहे हैं तो इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है और भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी यही कहना है कि हमें मैक्सिमम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए ताकि जो ग्राऊंड वाटर डैप्रीशिएट हो रहा है, उसका रीचार्ज हो, उसका बैलेंस मेंटेंन हो लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए प्रदेश में कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। न बजट में कोई ऐसी रिफ्लैक्शन है कि रेन वाटर

हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कोई प्रायोरिटी दी जा रही है। जहां कोई ए.आई.बी.पी. में भी प्रोजैक्ट अप्रूव हुए हैं, उसमें भी स्टडी में ही इतना समय लगा देते हैं कि जमीन पर वे

29.03.2017/1630/केएस/डीसी/2

प्रोजैक्ट्स नहीं आ रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि ऐसा न हो कि 15-20 साल में जो हमारे प्लेन एरियाज़ में ट्यूब वैल्ज़ लगे हैं या हमारे पहाड़ में चश्में हैं, वे सारे के सारे सूख जाएं। उस समय रातों-रात कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर हम अभी से सोच लें कि हमें ग्राऊंड वाटर को जितना एक्सप्लॉइट करना है उसके बराबर ही हम ग्राऊंड को रीचार्ज करने के लिए थ्रू डैम्ज़ चाहे वह हिल एरियाज़ में स्मॉल डैम्ज़ हैं, चाहे बड़ी खड्डे व बड़े डैम्ज़ हैं, उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रैस करें। इसका इरिगेशन मैक्सिमम फ्लो से होगा। वैसे भी इरिगेशन मैक्सिमम फ्लो से होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी पर बेस्ड जो हमारी स्कीमें होती हैं, उनके एक तो ब्रेक डाउन के बड़े चांसिज़ रहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। बजट में इसकी रिफ्लैक्शन होनी चाहिए थी लेकिन यह बड़ी मिसिंग है।

अध्यक्ष महोदय, इनोवेशन की डिपार्टमैंट को बहुत जरूरत है। आई.पी.एच. डिपार्टमैंट में एक रिसर्च विंग होनी चाहिए। रिसर्च एण्ड डिवैल्पमैंट विंग हो। इनोवेटिव आइडियाज़ उसमें डवैल्प हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी बातें जो प्रैज़ैंट सिस्टम है वह नहीं कर पाएगा। बात फिर वहीं आ जाएगी जो मैं बार-बार कहता हूं। हम न तो शहरी पॉपुलेशन को जस्टिस दे पा रहे हैं न रूरल को वाटर सप्लाई दे पा रहे हैं। न ही इरिगेशन सैक्टर में दे पा रहे हैं। वैसे भी सरकार ने बहुत ज्यादा अनफ्रूटफुल ऑफिसिज़ खोले हैं। चलो अच्छी बात है। इसका मैं ऑब्जैक्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सोच होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम सीरियस थॉट दें। अदरवाईज़ मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही बोलते जाएंगें। हो सकता है अगली बार आप यहां हो फिर आप ऐसा बोला करेंगें जैसे आज हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब लोग परेशान है तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम इसके लिए ट्राईफरकेशन के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसमें प्रैस्टिज़ इशू की कोई बात नहीं है। मैडम, एडज्वाइनिंग स्टेट में आप कोई

टीम भेजिए। उसको वहां देखिए। जेसे वहां अरबन वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज अलग है। अब हिमाचल भी कोई छोटा स्टेट नहीं रहा है। हिमाचल भी अब बड़ा स्टेट हैं। यहां पर मैक्सिमम प्रोजैक्ट्स सैंटर से आ रहे हैं। जैसे पी.डब्ल्यू.डी. की बात हो, वहां 61 नेशनल हाईवेज़ आ रहे हैं। वहां भी सोचा जा रहा है कि नेशनल हाईवेज़ की अलग एजैंसी होनी

29.03.2017/1630/केएस/डीसी/3

चाहिए, अलग डिपार्टमैंट होना चाहिए। तो ऐसे ही आई.पी.एच. में भी बहुत बड़े प्रोजैक्ट्स हम ला सकते हैं। अगर हम समय पर डी.पी.आर्ज़. बनाएं तो अरबन वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए एक अलग सोच हो, कम से कम यह सोचना शुरू कर दें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2017/1635/AV/DC/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर-------- जारी

अर्बन वाटर सप्लाई और सिवरेज के लिए एक अलग बोर्ड बनाना चाहिए। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का अलग से डिपार्टमैंट होना चाहिए। तीसरा हमारा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल है, अगर हम इसको इस ढंग से कर लेते हैं। इसको चाहे इन्टर्नेलाइजेशन इत्यादि जो भी करें इसके बारे में सोचा जा सकता है। यह तो आपके डिपार्टमैंट की बात है। आपका टैक्निकल विंग और इंजीनियर्स बहुत कम्पीटैंट है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उनको यही पता नहीं लग रहा है कि करना क्या है। अर्बन से रूरल में चले जाते हैं, रूरल से इरिगेशन चले जाते हैं तो इस तरह से उनकी एक स्टेबिलिटी नहीं है। क्वालीफाइड इंजीनियर और अच्छा केलिबर होते हुए भी वह वांछित रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। ट्राइफर्केशन के बारे में मैंने कई बार सोचा है और मेरा अपना ऐक्सपीरियंस है और उसी बेस पर मैं ऐसी बात कह रहा हूं। यह एक सोच है और ऐसा नहीं है कि यह काम अभी शुरू हो। हो सकता है कि यह सोच साल बाद शुरू हो परंतु ट्राइफर्केशन के लिए कम-से-कम एक सीरियस थोट होना चाहिए ताकि एक समय आए कि इरिगेशन में हम सबसे ऊपर है। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में सबसे ऊपर है,

अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम और सिवरेज में हमारी सबसे अच्छी सर्विस हैं। इस तरफ आगे बढ़ने की सोच स्टार्ट हो जानी चाहिए। सबके माईंड में यह बात आ जानी चाहिए कि यह सच में एक सीरियस बात है। अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हर बार इसी तरह के भाषण होंगे। एक सिस्टम के मुताबिक ही सब कुछ होता है जितनी सिस्टम की केपेसिटी होती है। चाहे वह इंजीनियर है या दूसरा स्टाफ है, काम वह अपनी केपेसिटी के अनुरूप ही कर पायेगा। केपेसिटी से ज्यादा हमें किसी को ज्यादा ऐक्सप्लॉय्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर काम करने का पीरियड 8 घंटे हैं और हम उसकी जगह किसी से 12 घंटे काम ले लेंगे तो वह ठीक से नहीं हो पायेगा। फेल्योर के बारे में सबने बताया कि कहां-कहां फेल्योर और क्या प्रोब्लम्ज है। हैण्ड पम्प के लिए मेरा एक सुझाव रहेगा। लोगों की सबसे ज्यादा प्रैजेंटेशन विधायक के पास आती है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। इसलिए हैण्ड पम्प विधायक की रिकमैंडेशन पर होनी चाहिए न कि पार्टी के आधार पर लगने चाहिए। इसमें भी प्रायोरिटी मैरिट के आधार पर होनी चाहिए, इसमें विधायक पिक एण्ड चूज नहीं करेगा क्योंकि उसको पता होता है कि उसने सबके वोट लेने है। अगर मैरिट पर काम करेंगे तो आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ेंगे।

29.3.2017/1635/AV/DC/2

इसलिए यह विधायक की कन्सैंट से होना चाहिए। दूसरा हैण्ड पम्प के साथ-साथ एक रिचार्ज सिस्टम इनबिल्ट कर दें क्योंकि हैण्ड पम्प में दो-चार साल बाद पानी का स्तर नीचे चला जाता है। उसके लिए नियर-बाई केचमैंट से रिचार्ज सिस्टम डीजाईन करना चाहिए। यह रिचार्ज सिस्टम 20-25 हजार रुपये में लग सकता है और इसके लिए अलग से पैसे रखे जाने चाहिए। आप अपने विभाग में इसके लिए अलग से सब कमेटी बनायें और इस पर विचार करना चाहिए कि हैण्ड पम्प को रिचार्ज करने के लिए क्या-क्या प्रोविजन होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर कोई हैण्ड पम्प लगे तो वह लगभग 15-20 साल तक चलना चाहिए। होता क्या है कि कोई हैण्ड पम्प लगता है तो उसके 3-4 साल बाद कहा जाता है कि इसको निकाल दो, इसका पानी का स्तर नीचे चला गया है। हैण्ड पम्प पोपुलेशन के नजदीक लगना चाहिए। कई बार कॉमन प्वाईंट पर लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि दस घर इधर है और दस घर उधर है इसलिए सैंटर में लगा दो। जब दस-दस घर दोनों तरफ है तो वहां पर दो हैण्ड पम्प लगाने चाहिए क्योंकि कॉमन प्लेस में लगाने से वहां से कोई पानी नहीं भरेगा। जहां पर पोपुलेशन नहीं होती वहां पर हैण्ड पम्प लगाने से उसका

कोई यूज़ नहीं होता है। कई बार सड़क के किनारे हम हैण्ड पम्प लगे देखते हैं उनसे एक गलत मेसैज जाता है। इसलिए हैण्ड पम्प मैरिट के आधार पर, पोपुलेशन के बीच में और उसमें रिचार्ज का कोई-न-कोई टैक्निकल पैरामीटर देखकर कि उसका रिचार्ज कैसे सम्भव है। कई जगह हैण्ड पम्प्स में ऐक्सैस आयरन होता है, उसके लिए आयरन रिमूवल प्लांट लगता है जिस बारे में एक बार बात चली थी। वह भी मुझे लगता है कि डीफंक्ट है और न लगाये जा रहे हैं। आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हम आई0पी0एच0 में बहुत अच्छी सर्विस देंगे तो हमें बड़ा अच्छा नाम मिलेगा। उसके लिए पोलिटिकल माइलेज भी मिलेगी। अगर नहीं दे पायेंगे तो लोग गालियां भी देते हैं क्योंकि सड़कें, पेयजल और सिंचाई का पानी सबके लिए होता है। हमारी सर्विस अच्छी होगी तो उससे लोगों को सुविधा मिलेगी और लोग दुआएं भी देंगे। हमारी सिंचाई की सुविधा अच्छी होगी तो प्रदेश की पर केपिटा इनकम भी बढ़ेगी।

श्री वर्मा द्वारा जारी

29/03/2017/1640/टी0सी0वी0-ए0जी0/1
श्री कृष्ण लाल ठाकुर ..... जारी ।

साथ ही अगर पीने का पानी हम साफ देंगे तो हमारी हैल्थ, जल जनित जो बीमारियां हैं, जैसे पीछे शिमला और सोलन में भी ये बीमारियां फैली थी। उसमें भी हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह सिस्टम का दोष है। शिमला में पानी का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम कॉरपोरेशन को दिया हुआ है, पानी हम आई0पी0एच0 से ले रहे हैं, तो इससे एक-दूसरे में टॉसिंग होती है। ये भी एक ही डिर्पाटमेंट के पास होना चाहिए, शायद इसके बारे में कुछ किया जा रहा है। ताकि सीवरेज, वॉटर सप्लाई और डिस्ट्रिव्यूशन की जिम्मेदारी भी उसकी हो otherwise tossing of responsibility होती है कि यह आई0पी0एच0 की गलती है, कॉरपोरेशन की गलती है या किसी और की गलती है। टॉसिंग के वजाय को-आर्डिनेशन से काम करें, ताकि आने वाले समय में उसका लोगों को फायदा मिल सकें।

Speaker: Hon'ble Member' Please wind-up.

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। आई0पी0एच0 में काम बहुत हुआ है, लेकिन प्लांड-वे से नहीं हुआ है, लेकिन आगे काम प्लॉड-वे से हों, रिजल्ट ऑरियंटिड/स्पेसिफिक हों और हमें क्लीयर हो जाना चाहिए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं? इन सब बातों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस कट मोशन का स्वागत करता हूं और मैंने जो सुझाव दिए हैं, माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देना शुरू कर दें ताकि कम-से-कम आपका नाम हो और यह मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्षः ज्यादा बोलने वालों को माननीय सदस्य अपना ही टाईम दे रहे हैं, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हैं।

29/03/2017/1640/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

श्री गोविन्द राम शर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्याः 13 "सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई" कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मुझ से पहले के वक्ताओं ने सारी बातें रख दी हैं और अभी भी श्री राजेश धर्माणी जी (मुख्य संसदीय सचिव) बोलने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि इनको पुराने टाईम की आदत है और अगले टाईम का भी ये आज से प्रयास करना चाह रहे थे कि जब कटौती प्रस्ताव आएंगे, तो उस पर बोलने के लिए मैं अभी से तैयार हूं। 6 महीने बाद आपकी बारी आएगी, आप बिल्कुल बोलना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पेयजल योजना और सिंचाई योजना की स्थिति बहुत सालों से अच्छी थी, लेकिन इस साल स्थिति कुछ गम्भीर लग रही है। अभी मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी हो गई है और इससे अप्रैल-मई में पेयजल की बहुत दिक्कत आएगी। हम आदरणीय शान्ता कुमार जी के आभारी हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में पेयजल योजना में नई क्रांति लाई। मैं आभारी हैं, पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिन्होंने 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' से देश में एक क्रांति लाई और उस योजना के अंतर्गत प्रदेश के

लिए इस वर्ष अरबों रुपये आये हैं। इसी कड़ी में मैं आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने पहली दफ़ा आई0पी0एच0 विभाग में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना शुरू की, जिससे प्रदेश और देश के लिए बहुत लाभ होगा।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी ।

29/03/2017/1645/एन0एस0/ए0जी0/1

श्री गोविन्द राम शर्मा --------जारी

क्योंकि यह योजना किसानों और बागवानों से संबंधित है। आज प्रदेश में पेयजल योजनाओं की स्थिति यह है कि जिन योजनाओं के शिलान्यास आदरणीय धूमल जी की सरकार के समय में हुए थे, पांच साल बीतने के बाद भी वे स्कीमें पूरी नहीं हुई हैं। इसके क्या कारण रहे हैं? इसके बारे में तो सरकार को ही पता होगा। लेकिन आज स्थिति बहुत गम्भीर है। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री महोदया काम नहीं करती हैं। जितनी हमारी उम्र हो है, उतना समय तो इनको राजनीति में हो गया है। इनका हम बहुत मान-सम्मान करते हैं। कई बार हम इनके पास अपनी दिक्कतों को ले करके गए हैं और इन्होंने प्रयास भी किया है। इन्होंने मेरे सामने एस0ई0 और एक्सिअन को टेलीफोन भी किए हैं। लेकिन एस0ई और एक्सियन भी क्या करें? ये लोग जब फील्ड में जाते हैं तो वहां पर बहुत से चेयरमैन और वाईस चेयरमैन, कई छोटे-छोटे नेता वहां पर हैं। कोई एक्सियन अगर हमारे कहने पर हैंडपम्प भी लगा देगा तो उस अधिकारी और कर्मचारी की खैर नहीं होती है। उनको धमकी दी जाती है कि आपको यहां से आज ही ट्रांसफर कर दिया जायेगा। आप सभी ने पीछे मीडिया के माध्यम से अखबारों में पढ़ा होगा कि विधायकों को 100-100 हैंडपम्पस दे दिये हैं। शायद यह खबर अमर उजाला अखबार में छपी थी। बहुत से लोग हमारे पास आने शुरू हो गये कि विधायक जी एक हैंडपम्प हमें दे दो। मैंने कहा कि यह जो न्यूज पेपर में दिखावा किया है, यह केवल हमें बदनाम करने के लिए किया गया है। हमारे कहने पर तो एक हैंडपम्प तक नहीं लगता है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अखबार में किसने और कैसे न्यूज दी

गई है। जब हमने मंत्री महोदया के पास 5-7 हैंडपम्पों की बात रखी तो इन्होंने टेलीफोन भी किया और उसके बाद वे अधिकारी डर के मारे कि उनकी ट्रांसफर कही और जगह न हो जाए या उनका कोई उत्पीड़न न हो जाए, वे हैंडपम्पस लगा ही नहीं सके। मैं यह नहीं कहता कि उनकी सोच यह नहीं थी कि ये हैंडपम्पस हमने लगाने ही नहीं हैं। वे जानते हैं कि ये हैंडपम्पस

29/03/2017/1645/एन0एस0/ए0जी0/2

लगने चाहिए क्योंकि इनकी वहां पर आवश्यकता है। मैंने कहा था कि चकलीधार क्षेत्र नालागढ़ में, देवीरा हाड़ा हरिजन बस्ती, दाऊटी पंचायत में एक हरिजन बस्ती भी है और दूसरा, सामान्य जाति से संबंधित लोग भी हैं। साऊग और रूडाल भी ठाकुरों के बहुत बड़े गांव हैं, मैंने माननीय मंत्री जी से उसके लिए भी आग्रह किया था क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और वहां गाड़ियां जा सकती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में हैंडपम्पस लगने चाहिए। अर्की क्षेत्र के अंदर तो मैक्सिमम शुष्क एरिया है और वहां पर जो टैंक बने हुए हैं, वे 1977 की जो स्कीमें बनी थीं, उस समय के बने हुए हैं। वहां पर जो पॉपुलेशन वर्ष 1977 में थी, आज उससे ज्यादा हो गई है। वहां टैंक्स भी नये बनने चाहिए और राईजिंग मेन भी बदलनी चाहिए। पाईप का डाया भी बढ़ना चाहिए। वहां पर वर्ष 1977 की पाईपें लगी हुई हैं और अगर वहां पर कहीं दो या चार पाईपें बदलनी हों, जब हम इसके लिए एक्सियन को बोलते हैं कि ये पाईपें बदल दो, लोग पानी को तरस रहे हैं और पानी के लिए त्राहि-त्राहि हो रही है, तब वे बोलते हैं कि हमारे पास पाईपें नहीं हैं। अगर हम उनको पम्पस और मोटरों को ठीक करने के लिए कहते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज यह स्थिति प्रदेश के अंदर है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को गर्मियों में किस प्रकार से पीने का पानी उपलब्ध होगा? इस विषय पर चिन्ता करने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब हम अधिकारियों को बोलते हैं कि कोई ट्रक या टैंकर लगा दो, मैं रविन्द्र रवि जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने अपने समय में हमें 100-150 हैंडपम्पस दिये हैं लेकिन जहां पर पानी की कमी रहती थी, वहां पर टैकर्ज़ भी लगवाये थे। इस सरकार में टैंकरों का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए स्थानीय लोगों की स्थिति क्या होगी? आज वहां पर वही स्थिति हो गयी है, जो वर्ष 1977 से पहले थी। माननीय शान्ता कुमार जी ने यहां पर पानी की क्रान्ति लाई थी। उससे पहले

चार-चार किलोमीटर से हमारी बहनें सिर पर उठा करके पानी लाती थीं। हमारे भाई और हम लोग जब स्कूल जाते थे तो पानी ले करके आते थे। हम चार-चार किलोमीटर की दूरी से पानी ले करके आते थे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा .....जारी।

29/03/2017/1650/RKS/AS/1

श्री गोविन्द राम शर्मा... जारी

वही स्थिति आज प्रदेश में पैदा हो रही है। इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकार ने पानी के बारे में कोई चिंता नहीं की है। अगर माननीय मंत्री जी चिंता करती भी हैं तो उसकी इम्प्लिमैंटेशन नहीं होती। इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी ही स्थिति सिंचाई के अंदर भी है। केंद्र से आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी कह रहे हैं कि सिंचाई योजनाएं बनाओ। मैंने भी कहा कि हमारे यहां सिंचाई योजनाएं बनाई जाएं। पहले भी हमने विधायक प्राथमिकता में सिंचाई योजनाएं डाली हैं परन्तु लिखा जाता हैं 'not feasible'. चाहे वह मटेरनी, कवाचखड्ड या जोबी की बात हो। हम मानते हैं कि यहां पर पानी नहीं है और ये क्षेत्र ड्राई हैं। लेकिन बड़े-बड़े डैम वहां पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमैंट को सरकार की डायरैक्शन चाहिए। अगर सरकार डायरैक्शन देगी तो बड़े-बड़े डैम बनना प्रस्तावित होंगे। अभी माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी कह रहे थे कि पानी के सोर्स नहीं हैं और हैंडपम्पस में पानी सूख जाता है। इस वर्ष भी मैंने मटूली, छाची और दिग्गल पंचायत के कुछ एरिया के लिए कवाचखड्ड से विधायक प्राथमिकता में सिंचाई की योजना डाली है। मेरा सरकार से निवेदेन है कि इसके लिए तुरंत डी.पी. आर. बनाई जाए। जो पुरानी योजनाएं हैं, कुछ पांच-पांच वर्षों की पुरानी पेयजल योजनाएं हैं उनको तुरंत तैयार किया जाए। हमने 30-35 करोड़ रुपये की पेयजल योजना गम्भर खड्ड से अर्की के लिए बनाई। उन पेयजल योजनाओं का उद्घाटन अब किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुनिहार की तीन पंचायतों में जाकर उनका उद्घाटन कर दिया। यह कौन-सा नया प्रोसिज़र शुरू हो गया है? अधिकारी क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री महोदया

अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से एक-एक पंचायत के लिए उद्घाटन करवा दो। शायद उनको इस बात का पता नहीं होगा परन्तु अधिकारियों को तो यह पता था। यह कम-से-कम 20-30 पंचायतों के लिए पानी की स्कीम बनी है। सरकार को चाहिए कि वे जनता की तरफ ध्यान दें। गर्मी में जो पानी की दिक्कत आने वाली है उस पर यदि आप आज से ही विचार करेंगे तो इसका लाभ हम सबको होगा। पूरे प्रदेश में पेयजल योजनाओं की दिक्कत

29/03/2017/1650/RKS/AS/2

आ रही है, सिंचाई योजनाओं को चलाने की दिक्कत आ रही है, इस का कारण यह है कि स्टाफ कम है। सरकार के पास सर्वेयर, एस.डी.ओ., फीटर, पम्प ऑप्रेटर, की-मैन और वेलदार कम हैं। इन अधिकारियों/कर्मचारियों को भर्ती करने का काम किसने करना है? यह काम सरकार का है। पांच वर्ष बीतने वाले हैं, 6-7 महीने रह गए हैं। परन्तु अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम मस्ती कर रहे हैं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना दो, दो-दो डायरेक्टर्ज बना दो, डिस्ट्रिकट लैवल, ब्लॉक लैवल में भी डायरैक्टर बना दो, कोई टांसपोर्ट, काई टूरिज्म या किसी और चीज का डायरेक्टर बना दो। आम जनता को किस चीज की आवश्यकता है? उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल इतना जरूर होता है, जब बी.जे.पी. के विधायक के कहने पर एक हैंडपम्प लगा दिया जाता है तो उस अधिकारी/कर्मचारी को बदल दिया जाता है। अधिकारी/कर्मचारी ने विपक्ष के विधायक के कहने पर कुछ काम कर दिया तो उसको बदल दो। आप सरकार में हैं और सरकार को पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम माननीय मंत्री जी का आदर करते हैं परन्तु इनके विभाग में इम्प्लिमैंटेशन नहीं हो रही है। इसका मुझे दुःख है। मैं चाहता हूं कि इम्प्लिमैंटेशन हो और जो गर्मियों के दिनों में पानी की दिक्कत आएगी उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

29.03.2017/1655/SLS-AG-1

अध्यक्ष : अब बैठक का निर्धारित समय समाप्त होने वाला है क्योंकि 5.00 बजने को हैं। मैं माननीय सदन से अनुमति लूंगा कि अभी इस सभा को एडजॅर्न किया जाए और कल पुनः इस मद को कंटिन्यू किया जाएगा।

इससे पूर्व कि मैं इस माननीय सदन की बैठक स्थगित करूं, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज सायं 7.00 बजे आप लोगों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया है जिसके लिए आप सबको निमंत्रण-पत्र भी भेजे गए हैं।

आज ही हमारी कॉमनवैल्थ पार्लियामैंटरी एसोसियेशन की वार्षिक मीटिंग 10-15 मिनट के लिए अभी मेन कमेटी रूम में होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मीटिंग को कमेटी रूम में उपस्थित होकर अटैंड करें।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 30 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 29 मार्च, 2017 **सचिव।**